



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्रकाशक से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 146]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 26, 2010/ज्यैष्ठ 5, 1932

No. 146]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 26, 2010/JYAISTHA 5, 1932

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मई, 2010

[विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (समविश्वविद्यालय बनने वाली संस्थाएं) विनियम, 2010]

प्रस्तावना

संस्थाओं को समविश्वविद्यालय घोषित करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित तरीके से चिनिबधित करने, खराब गुणवत्ता वाली संस्थाओं को इस घोषणा से अलग रखने; और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए समविश्वविद्यालय संस्थाओं द्वारा विश्वविद्यालय के लक्ष्यों के साथ सहयोग; के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 26 की उप-धारा (1) के खंड (क) और (ख) के अंतर्गत दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निम्नलिखित विनियम तैयार हैं :

1.0 लक्ष्यसूचक, अनुदान और अलग

- 1.1 इन विनियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (समविश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2010 कहा जाएगा ।
- 1.2 ये विनियम इसी प्रत्येक संस्था पर लागू होंगे जो समविश्वविद्यालय संस्था के रूप में घोषित किए जाने के लिए आवेदन करेगी । यद्यपि ये भावी रूप में उन संस्थाओं पर भी लागू होंगे जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत समविश्वविद्यालय घोषित किया जा चुका है ।
- 1.3 समविश्वविद्यालय में इसकी अधिसूचना की तिथि से ये लागू होंगे ।

2.0 परिभाषाएं

इन विनियमों में का कदा संदर्भ के लिए अलग आकरक न हो :

- 2.01 "अधिनियम" का अर्थ है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम 3) ।

- 2.02 “परिसर” का अर्थ है भारत के शहर/गांव में स्थित सम विश्वविद्यालय संस्था के मुख्यालय का वह परिसर जहाँ इसकी प्रमुख सुविधाएं, संकाय, स्टाफ, छात्र और इसके अकादमिक विभाग हैं। जबकि ‘ऑफ कैंपस केन्द्र’ का अर्थ है देश में इसके परिसर से बाहर समविश्वविद्यालय संस्था का अनुमोदन केन्द्र (केन्द्र सरकार द्वारा), विदेशी कैंपस का अर्थ है इसके परिसर से बाहर और भारत से बाहर समविश्वविद्यालय संस्था का अनुमोदित (केन्द्र सरकार द्वारा) केन्द्र।
- 2.03 “आयोग” का अर्थ है अधिनियम के अंतर्गत अथवा समविश्वविद्यालय संस्था को विनियमित करने के लिए अधिकृत किसी अन्य निकाय द्वारा उस समय लागू किसी कानून के अंतर्गत गठित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग।
- 2.04 “विशेषज्ञ समिति” का अर्थ है, ज्ञान के संगत क्षेत्रों में अकादमिकों, अनुसंधानकर्ताओं अथवा अन्य विशेषज्ञों वाले आयोग द्वारा नियुक्त और इन विनियमों के लिए ऐसे किसी उद्देश्यार्थ अधिसूचित समिति; और ऐसी कई विशेषज्ञ समितियां हो सकती हैं जिन्हें आयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए निश्चित कर सकता है।
- 2.05 “घटक संस्था” का अर्थ है प्रायोजित निकाय के प्रशासनिक, अकादमिक और वित्तीय नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करने वाली संस्था और अधिसूचना के अंतर्गत घोषित संस्था।
- 2.06 “नई संस्था” का अर्थ है संबद्ध विषयों में अकादमिक समुदाय की विशिष्ट लोगों द्वारा निर्दिष्ट विशेष और ‘ज्ञान के उभरते क्षेत्रों’ में शिक्षण और अनुसंधान में नवाचारों को समर्पित संस्था।
- 2.07 “ज्ञान के उभरते क्षेत्र” का अर्थ है आयोग द्वारा उद्देश्यार्थ गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर आयोग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित ज्ञान के क्षेत्र; और ऐसी समिति संगत विषयों में अध्ययन और अनुसंधान विकास के साथ-साथ भारत में इनके अध्ययन और अनुसंधान के मानकों को बढ़ाने की आवश्यकता के अनुसार अपनी सिफारिश करेगी।
- 2.08 “सरकार” का अर्थ है केन्द्र सरकार, जब तक कि यह संदर्भ विशिष्ट न हो।

- 2.09 “संस्था” का अर्थ है अथवा समस्त एक समस्तकोत्तर अथवा अन्य स्तरों पर उच्च अकादमिक मामलों के शिक्षण और अनुसंधान में लगी हुई उच्च शिक्षण संस्था।
- 2.10 “समविश्वविद्यालय संस्था” का अर्थ है केन्द्र सरकार द्वारा आयोग की सिफारिश पर अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत घोषित उच्च शिक्षा संस्था।
- 2.11 “प्रोसेसिंग शुल्क” का अर्थ है आवेदक संस्था द्वारा ऐसे आवेदन की प्रोसेसिंग के लिए आवेदन सहित आयोग को दिये जाने वाले प्रभार। इस राशि में आयोग द्वारा आवेदन की प्रोसेसिंग पर किए गए व्यय को ध्यान में रखा जाएगा जिसमें आयोग की विशेष समितियों द्वारा ऑनसाइट दौरे शामिल होंगे। आयोग प्रोसेसिंग शुल्क विनिर्दिष्ट करेगा और समय-समय पर इसे संशोधित करेगा।
- 2.12 “अधिसूचना” का अर्थ है अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत किसी उच्च शिक्षण संस्था को समविश्वविद्यालय संस्था घोषित करने के लिए राजकीय राजपत्र में केन्द्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना।
- 2.13 “प्रायोजक निकाय” का अर्थ है ऐसी दानी अथवा अलाभकारी सोसायटी अथवा ट्रस्ट जो अपने प्रशासनिक, अकादमिक और वित्तीय निबंधन में आने वाली संस्था को समविश्वविद्यालय घोषित करने के लिए आवेदन करे।
- 2.14 “सांविधिक निकाय” का अर्थ है उच्च शिक्षा के संगत क्षेत्रों में गुणवत्ता के मानकों को सुनिश्चित करने अथवा बनाए रखने लिए कुछ समय के लिए किसी कानून के अंतर्गत गठित निकाय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडियन नर्सिंग काउंसिल आदि इन विनियमों के उद्देश्यार्थ सांविधिक निकाय होंगे।

3.0 समविश्वविद्यालय संस्था के उद्देश्य

सरकार द्वारा किसी संस्था को समविश्वविद्यालय संस्था घोषित करने के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे:-

- 3.1 उच्च शिक्षा प्रदान करना ताकि विश्वविद्यालय शिक्षा रिपोर्ट (1948) और भारत में उच्च शिक्षा के नवीकरण एवं पुनर्गठन (2009) और समविश्वविद्यालयों

के लिए समीक्षा समिति की रिपोर्ट (2009) के द्वारा विश्वविद्यालय के संदर्भ से पूर्णतया सहमत स्नातकोत्तर और अनुसंधान डिग्री स्तरों पर उचित मानी जाने वाली ज्ञान की ऐसी श्रृंखलाओं में उत्कृष्टता और नव्यचार का प्रशोधन करना।

- 3.2 परंपरागत संस्थाओं द्वारा प्रदान किए जाने वाले कला, विज्ञान, इंजीनियरी, चिकित्सा, डेंटल, फार्मसी, प्रबंध आदि विषयों में परंपरागत डिग्रियों तक पहुंचने के लिए सामान्य स्वरूप के कार्यक्रमों से अकादमिक विनियोजन को अलग करने वाले-विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली के लक्ष्यों में महत्वपूर्ण भागीदारी करने के लिए योग्यता वाले विशिष्ट क्षेत्रों में लगना।
- 3.3 विभिन्न विषयों में पर्याप्त संख्या में पूर्णकालिक संकाय/अनुसंधान शिक्षाविदों (पीएच.डी. और पोस्ट डॉक्टोरल) द्वारा विभिन्न इन-हाउस अनुसंधान कार्यक्रमों के माध्यम से उच्च गुणवत्तापरक शिक्षण और अनुसंधान हेतु तथा ज्ञान की प्रगति और उसके वितरण हेतु प्रावधान करना।
- 3.4 अकादमिक समुदाय के विशिष्ट व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श की प्रक्रिया से विनिर्दिष्ट हमारी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए अथवा देश की प्रमुख आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा अभ्ययन और अनुसंधान के विशिष्ट क्षेत्रों में प्रायोजित-“नए” वर्ग के अंतर्गत ऐसे विशेष और उभरते क्षेत्रों में जिन्हें परंपरागत अथवा वर्तमान संस्थाओं द्वारा कार्य में नहीं लाया जा रहा है, के अंतर्गत समविश्वविद्यालय संस्थाओं के सूझ में सहायता करना।
- 4.0 समविश्वविद्यालय के रूप में घोषित की जाने वाली संस्था के लिए पात्रता मानदंड

समविश्वविद्यालय संस्था के रूप में घोषित किए जाने के लिए आवेदन करने वाली संस्था को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:-

(क) पात्रता मानदंड

- 4.1 कम से कम पंद्रह वर्ष से विद्यमान हो (नए वर्ग के अंतर्गत समविश्वविद्यालय संस्था के रूप में घोषणा चाहने वाली संस्थाओं के अलावा)।

- 4.2 अनुसंधान के अपने कार्यक्रमों में विविधता द्वारा, शिक्षण में नवप्रवृत्तियों के अंशगण द्वारा और अनुसंधान परिणाम सम्बन्धित उच्च गुणवत्ता के माध्यम से विश्वविद्यालय की विशेषताओं को प्राप्त कर लेना हो।
- 4.3 कुछ समय के लिए लागू किसी कायून के अंतर्गत मान्यताप्राप्त बाह्य प्रशिक्षण/मूल्यांकन एजेंसियों द्वारा आवधिक समीक्षा और मूल्यांकन किए जाने का विकल्प हो। जिस संस्था का प्रशिक्षण न हुआ हो अतः जहाँ ऐसा संभव न हो तो इन विनियमों के अनुच्छेद 3.4 में उल्लिखित संस्था 'नए' वर्ग के अंतर्गत सम्मिश्रित विश्वविद्यालय की घोषणा के लिए इस्मानी उपयुक्तता के आवश्यक मूल्यांकन की शर्त होगी।
- 4.4 ठेका अंतःअनुशासनात्मक पुनश्चर्या और संयोजन के ज्ञान विभिन्न विषयों में अथवा स्नातक, स्नातकोत्तर और अनुसंधान कार्यक्रमों के अंतर्गत पूर्णतः स्थापित, प्रसारित और व्यवहार्य होना चाहिए।
- 4.5 ऐसी संस्था नहीं होना चाहिए जहाँ केवल परंपरागत विधियों की शिक्षा ही दी जाती हो। उदाहरण के तौर पर यह केवल इंजीनियरी अथवा प्रबंध अथवा चिकित्सा अथवा फार्मेसी अथवा डेंटल विज्ञान आदि कार्यक्रमों तक ही सीमित न हो, इन कार्यक्रमों को कालेज की वर्तमान स्थिति के साथ प्रदान किया जाना जारी रखा जा सकता है।
- 4.6 संस्था ऐसी नहीं होगी चाहिए जो मुख्य रूप से सेवाकालीन कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करे अथवा केवल कौशल अभिवृद्धि अथवा उत्पादन से संबंधित किसी अथवा डिप्लोमा कार्यक्रम ही चलाए।
- 4.7 गुणवत्तापरक अनुसंधान कार्यों, उच्च मानकों वाले प्रकाशनों और शैक्षिक कार्यों में लगा होना चाहिए जिसका परिणाम अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त डाटाबेस में समावेशन हो; और डॉक्टरेट/पोस्ट डॉक्टरेट अनुसंधान कार्यक्रम सक्षम होने चाहिए और पूर्णकालिक डॉक्टरेट स्तरीय विधियों के महत्वपूर्ण परिणाम होने चाहिए।
- 4.8 शिक्षण और अनुसंधान के लिए पर्याप्त संख्या में पूर्णकालिक पूर्णतः अर्हता प्राप्त संकाय होना चाहिए जिसमें कम से कम कुछ अपने विषयों में ख्याती प्राप्त हों।

- 4.9 गुणवत्तापत्रक अनुसंधान के लिए आवश्यक अवसंरचना और अभ्युक्ति सूचना संसाधनों के लिए वृहद पहुंच होनी चाहिए।
- 4.10 विभिन्न सार्वजनिक/निजी एजेंसियों से मेरिट आधारित बाहरी अनुसंधान विस्तारपोषण प्राप्त करने का प्रयत्न रिकार्ड होना चाहिए।
- 4.11 पेटेंट, कॉपीराइट के रूप में बौद्धिक संपदा का सृजन और वांछनीय विशेषता के रूप में प्रौद्योगिकी का अंतरण किया है।
- 4.12 विस्तृत सेवाओं और सामाजिक विनियोजनों का प्रमाणिक रिकार्ड होना चाहिए।
- 4.13 ऐसी संस्थाओं के पास, वर्तमान में मान्य, प्रदत्त शीर्षस्थ ग्रेड का मान्य प्रत्यायन होना चाहिए जो या तो राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन बोर्ड से होना चाहिए अथवा इसके सभी पात्र पाठ्यक्रम राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से अथवा समय-समय पर आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त प्रत्यायन एजेंसी से प्रत्यायित होने चाहिए।
- 4.14 यह वचन दे कि वह दूरस्थ मोड में कोई कार्यक्रम प्रदान नहीं करेगा।

(ख) शर्तें

- 4.15 एक बार 'समविश्वविद्यालय' की घोषणा कर दिए जाने पर कोई अन्य वर्तमान संस्था इसके साथ घटकीय संस्था के रूप में तब तक संलग्न नहीं हो सकती है जब तक कि संलग्न होने वाली संस्था इन विनियमों के सभी मानदंडों को स्वतंत्र रूप से पूरा कर रही हो।
- 4.16 समय समय पर आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार प्रत्येक समविश्वविद्यालय के लिए गहन बाह्य समीक्षा अनिवार्य होगी।
- 4.17 आवेदक संस्थाएं अलाभकारी संगठन होने चाहिए और उच्च शिक्षा के बाणिज्यीकरण में शामिल नहीं होने चाहिए।

4.18 समविश्वविद्यालय संस्था का दर्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से पहले पांच वर्ष की अवधि में आवेदक संस्था का किसी सांविधिक प्राधिकरण की दिशानिर्देशों किन्हीं भी सांविधियों के प्रावधानों का उल्लंघन न करने का ट्रैक रिकार्ड होना चाहिए।

5.0 समविश्वविद्यालय घोषित की जाने वाली संस्थाओं के लिए शर्तें प्रणाली

समविश्वविद्यालय के रूप में घोषित किए जाने वाली संस्था को निम्नलिखित मानदंडों को मानना होगा:-

- 5.1 प्रस्तावित समविश्वविद्यालय संस्था को या तो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत अलाभकारी सोसायटी के रूप में अथवा सोसायटी/ट्रस्ट के साथ पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम के अंतर्गत अलाभकारी ट्रस्ट के रूप में पंजीकरण होना चाहिए जो निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार हो।
- 5.2 समविश्वविद्यालय के प्राधिकारियों में एक मुख्य निदेशक शिक्षण की भूमिका मुख्यतः औपचारिक होगी। कुलाधिपति की नियुक्ति प्रायोजक सोसायटी अथवा प्रायोजक ट्रस्ट द्वारा की जाएगी। वह प्रायोजक सोसायटी के अध्यक्ष अथवा इसके नजदीकी रिश्तेदारों के अथवा प्रख्यात शिक्षाविद अथवा प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए।
- 5.3 समकुलपति की कोई शक्ति नहीं होगी।
- 5.4 समविश्वविद्यालय का उच्चतम शक्ती विषय प्रबंध बोर्ड होना चाहिए जिसकी अध्यक्षता कुलपति अथवा किसी प्रख्यात शिक्षाविद द्वारा की जानी चाहिए। इस विषय में कम से कम दस और अधिकतम बारह सदस्य होंगे।
- 5.5 संस्था का प्रबंध बोर्ड ट्रस्ट (अथवा) सोसायटी से अपने अध्यक्ष और प्रशासनिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होना चाहिए। प्रबंध बोर्ड में ट्रस्ट (अथवा) सोसायटी के प्रतिनिधियों/नामितियों की संख्या अधिकतम दो तक सीमित होगी।

5.6 प्रबंधन बोर्ड में ऐसे विख्यात व्यक्ति होंगे जो विश्वविद्यालय के आदर्शों और परंपराओं में भागीदारी करने और उसे बकाय रखने में सक्षम हों।

5.7 प्रबंध बोर्ड में निम्नलिखित शामिल होने चाहिए:-

- (i) कुलपति.....अध्यक्ष
- (ii) समकुलपति (जहां भी लागू हो)
- (iii) संकायाध्यक्ष, दो से अधिक न हों (वरिष्ठता आधारित चकानुकम)
- (iv) कुलाधिपति द्वारा नामित तीन प्रतिष्ठित शिक्षाविद
- (v) यूजीसी के साथ परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा नामित किया जाना वाला एक प्रख्यात शिक्षाविद
- (vi) वरिष्ठता आधारित चकानुकम द्वारा दो शिक्षक (प्रोफेसरों, एसोसिएट प्रोफेसरों में से)
- (vii) प्रायोजक सोसायटी का एक नामित
- (viii) रजिस्ट्रार जो सचिव होगा।

प्रबंध बोर्ड की सदस्यता और इसके अधिकारों की शर्तें अनुसूची-1 में दी गई हैं।

5.8 कुलपति एक प्रख्यात शिक्षाविद होगा चाहिए और इसकी नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा खोज-सूझ-चयन समिति की सिफारिश पर की जानी चाहिए। इस समिति में सरकार का एक नामित होगा जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परामर्श से नामित किया जाना चाहिए, कुलाधिपति का एक नामित और प्रबंध बोर्ड का एक नामित शामिल होगा चाहिए। समिति की अध्यक्षता प्रबंध बोर्ड के नामित द्वारा की जानी चाहिए।

5.9 समविश्वविद्यालय के अन्य सभी संबंधित विषयों की व्यवस्था अनुसूची-2 में की गई है।

6.0 नियुक्ति और सुका संरचना

6.1 सभी समविश्वविद्यालयों, सार्वजनिक शिक्षा बोर्डों, में स्थापित विभिन्न स्तरों के विभिन्न अखिल भारतीय परीक्षा में मेरिट के आधार पर और इस संबंध में कानून पर बवाई गई राष्ट्रीय नीति के अनुरूप होना चाहिए।

- 6.2 समविश्वविद्यालय संस्थाओं में अतिवासी भारतीयों/भारतीयों के अतिवासी विदेशी छात्रों के सम्बन्ध में उन संस्था में उनका समय पर आवेदन द्वारा समाप्त नष्ट विद्यार्थियों/विद्यार्थियों के अनुसार कर लेने चाहिए।
- 6.3 समविश्वविद्यालय संस्थाओं को कम से कम एक वर्ष के लिए वित्तियन संयोजी रिपोर्ट को संभाल कर रखना चाहिए।
- 6.4 समविश्वविद्यालय में अध्ययन के विभिन्न कार्यक्रमों हेतु शुल्क संरचना को भी समय समय पर इस संबंध में सरकार अथवा अखिल भारत सरकार नष्ट शुल्क विनियमों के अनुसार निश्चित किया जाना चाहिए।
- 6.5 समविश्वविद्यालयों में प्रदान किए जा रहे पाठ्यक्रमों हेतु लिए जा रहे शुल्क के स्तर का पाठ्यक्रम बनाए जाने की लागत से तर्कसंगत संबंध होना। शुल्क अकादमिकता को विचारपूर्वक और संयम की दृष्टिकोण पर विचारित जाएंगे।
- 6.6 प्रत्येक ऐसी संस्था जिसे समविश्वविद्यालय, सार्वजनिक अथवा निजी, के रूप में घोषित किया गया है से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षा का वाणिज्यिककरण न हो। ऐसी प्रत्येक संस्था को सभी पात्र छात्रों को समानता और पहुंच का अवसर प्रदान करना चाहिए।
- 6.7 अधिनियम के अंतर्गत समविश्वविद्यालय संस्था के रूप में घोषित कर दिए जाने पर संस्था को आपने अनुमोदित अकादमिक कार्यक्रमों में छात्रों को दाखिला केवल उस अकादमिक सत्र से देना चाहिए जो केन्द्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के बाद होगा। समविश्वविद्यालय संस्था के रूप में घोषित किए जाने के पूर्वानुमान में अथवा संस्था के समविश्वविद्यालय संस्था के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आ जाने, अथवा किसी अन्य कारण से संस्था में छात्रों का दाखिला आवेदन को अवैध बना देगा। ऐसे छात्र जो समविश्वविद्यालय संस्था की घोषणा के लिए आवेदन की तिथि से पहले अथवा समविश्वविद्यालय के कार्यक्षेत्र में आने पर, पहले से ही संस्था में दाखिल हैं वे सभी उद्देश्यों के लिए ऐसे संबद्ध विश्वविद्यालयों में दाखिल रहेंगे और उन्हें उच्च संबद्ध विश्वविद्यालयों से डिग्री भी प्राप्त होगी।

7.0 अवसंरचना और अन्य सुविधाएं

7.1 ऐसी संस्थाओं में समविश्वविद्यालय संस्था के रूप में प्रशासन और अनुसंधान के लिए आवश्यक वित्तीय और अवसंरचनात्मक व्यवहार्यता होनी चाहिए और विश्वविद्यालय के आदर्शों और परंपराओं में भागीदारी और शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार कार्यों की गुणवत्ता में वृद्धि करने की क्षमता रखने वाला प्रबंधन होना चाहिए।

7.2 इसके पास निम्नलिखित न्यूनतम अवसंरचना और अन्य सुविधाएं होनी चाहिए:-

7.2.1 भूमि और भवन:-

- i) यदि ये संस्था महानगर क्षेत्र में स्थित है तो इसके मुख्य परिसर में पांच एकड़ से कम भूमि नहीं होनी चाहिए; यदि यह गैर महानगरीय शहरी क्षेत्र में स्थित है तो इसके मुख्य परिसर में सात एकड़ भूमि होनी चाहिए; अथवा यदि यह गैर शहरी क्षेत्रों में स्थित है तो इसके मुख्य परिसर में दस एकड़ भूमि होनी चाहिए अथवा संबद्ध सांविधिक/विनियामक निकाय के मानकों के अनुसार, जो भी अधिक हो। बहुविषयक संस्था के मामले में औसत भूमि आवश्यकता सभी पाठ्यक्रमों के लिए विभिन्न सांविधिक परिषदों द्वारा विनिर्दिष्ट कुल भू-क्षेत्र होना चाहिए।
- ii) कम से कम 1000 वर्गमीटर का प्रशासनिक भवन
- iii) कम से कम 10000 वर्गमीटर का अकादमिक भवन जिसमें पुस्तकालय, व्याख्यान थियेटर और प्रयोगशालाएं शामिल हैं। इसमें से केन्द्रीय पुस्तकालय ही लगभग 2000 वर्गमीटर का होगा।
- iv) समविश्वविद्यालय संस्था के रूप में घोषित किए जाने के लिए आवेदन के समय शिक्षकों के लिए आवास, गेस्ट हाउस और विद्यार्थियों के लिए छात्रावास होने चाहिए। समविश्वविद्यालय संस्था की घोषण के तीन वर्ष

के अंदर ही छात्रवास कमरा को कम से कम 2.5 प्रतिशत बड़ा किया जाना चाहिए।

- v) यदि संस्था अध्ययन के व्यावसायिक कार्यक्रम चल रही है तो ऊपर के अतिरिक्त संबद्ध सांविधिक निकाय के विद्यमान मानक और प्रतिष्ठापक लागू होने चाहिए।
- vi) उपस्कर, पुस्तकें, पत्र-पत्रिकाएँ और अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाएँ

संस्था के उपस्कर, पुस्तकें और पत्र-पत्रिकाएँ संस्था के आन्तर और कार्य के अनुरूप होने चाहिए और उन्हें संबद्ध सांविधिक/वित्तीय/निकाय की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। इन अध्ययन/व्यावसायिक प्रयोगों/तकनीकों के अनुसार कार्य करने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संस्था के पास उचित स्तर की ब्राडबैंड कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए। इसके साथ-साथ पत्र-पत्रिकाओं, पुस्तकों और अन्य अध्ययन सामग्रियों तक इलेक्ट्रॉनिक पहुंच का प्रबंधन भी होना चाहिए।

7.3 अकादमिक कार्यक्रम

- अंतरविषयक अध्ययन और अनुसंधान के लिए अकादमिक कार्यक्रम में पर्याप्त अवसर होंगे।
- कार्यक्रम का वितरण नवागती शिक्षण और अध्ययन प्रक्रिया तथा मूल्यांकन प्रणाली पर आधारित होगा।
- इसे उपयुक्त अर्हता प्राप्त संकाय का सहयोग प्राप्त होगा।

इसमें अवर स्नातक और कम से कम पांच स्नातकोत्तर अकादमिक विभाग होने चाहिए जिसमें प्रत्येक विभाग में सम्मान्य पदवीधरों के लिए एक प्रोफेसर दो रीडर और तीन लेक्चरर वाला न्यूनतम स्थायी संकल्प होना चाहिए और इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, डेंटल, नर्सिंग, फार्मसी, फिजियोथेरेपी आदि जैसे अन्य विषयों के पाठ्यक्रमों के मामले में संकाय को संबद्ध सांविधिक परिषद के मानकों और दिशानिर्देशों के अनुसार होंगे जिनकी अर्हता और वेतनमान आयोग/संबद्ध सांविधिक परिषद द्वारा निर्दिष्ट किए जाएंगे, संबद्ध सांविधिक निकाय द्वारा बनाए गए मानकों और प्रतिष्ठापकों के अनुसार उन्हें अनिवार्य तकनीकी और मंत्रालयी सहायक स्टाफ दिया जाएगा।

7.4 वित्तीय व्यवहार्यता:

समविश्वविद्यालय संस्था के रूप में घोषणा के लिए आवेदन की तारीख से पहले पिछले पांच वर्ष के लिए संस्थान के संपरीक्षित लेखों द्वारा संस्था की वित्तीय व्यवहार्यता का सत्यापन किया जाएगा।

7.5 कायिक निधि:

7.5.1 सरकार द्वारा अनुरक्षण अथवा वित्तपोषण न किए जाने वाली संस्थाओं के मामले में निम्नलिखित कायिक निधि का सृजन किया जाएगा और इसे अपरिवर्तनीय सरकारी सुरक्षा अथवा आयोग द्वारा अनुमोदित अन्य स्वरूपों के माध्यम से प्रस्तावित समविश्वविद्यालय संस्था के नाम पर स्थायी रूप से अनुरक्षित किया जाएगा:-

- क. इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी, चिकित्सा जैसे व्यावसायिक कार्यक्रम प्रदान करने वाली संस्थाओं के लिए 8.00 करोड़ रुपए
- ख. प्रबंधन, कानून, शिक्षा जैसे कार्यक्रम प्रदान करने वाली संस्थाओं के लिए 5.00 करोड़ रुपए
- ग. अन्य कार्यक्रम प्रदान करने वाली संस्थाओं के लिए 4.00 करोड़ रुपए
- घ. व्यावसायिक और अन्य, दोनों, कार्यक्रम प्रदान करने वाली संस्थाओं के लिए 10.00 करोड़ रुपए
- ङ. नए वर्ग के अंतर्गत आने वाली संस्थाओं के लिए 25 करोड़ रुपए

7.5.2 आयोग की पूर्वानुमति के बिना कायिक निधि को परिसमाप्त नहीं किया जाएगा।

7.5.3 आयोग को अधिकार होगा कि वह समय समय पर कायिक निधि के किसी उर्ध्वमुखी संशोधन का निदेश दे।

7.5.4 कायिक निधि पर प्राप्त व्याज का उपयोग संस्था के विकास के उद्देश्य से ही किया जाएगा।

7.5.5 समविश्वविद्यालय स्तर की घोषणा वापस लिए जाने अथवा समविश्वविद्यालय संस्था की सोसायटी अथवा ट्रस्ट के समाप्त हो जाने के मामले में

उत्तरदायित्वों को पूरा करने, यदि कोई हो, के लिए कायिक विधि आयोग को अपवर्तित होगी।

7.5.6 कायिक विधि से संबंधित प्रावधान केवल उन्हीं समविश्वविद्यालयों पर लागू होंगे जो इन विनियमों की अधिसूचना के बाद अस्तित्व में आए हैं। तथापि, सार्वजनिक वित्तपोषित संस्थाओं के मामले में राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा उन्हें लगातार वित्तपोषित करने की प्रतिबद्धता को पर्याप्त माना जाएगा।

7.6 संस्था की सभी चल और अचल संपदा प्रस्तावित समविश्वविद्यालय संस्था का अनिवार्य अंग है और वे उसी प्रकार से संस्था को कानूनी रूप से प्राप्त होंगी जो संपदा स्थानांतरण अधिनियम, 1882 अथवा उस समय लागू किसी अन्य कानून के अंतर्गत मान्य होंगे। तथापि, यदि संस्था ने अचल संपदा को किराए पर प्राप्त किया है तो यह लीज सतत स्वरूप की होगी और आरंभ में कम से कम 99 वर्ष के लिए लागू होगी।

7.7 संस्था की आय और संपदा, जो किसी तरह भी प्राप्त की गई हो, उसका उपयोग केवल संस्था के लक्ष्यों की प्रगति के लिए ही किया जाएगा जिसमें संस्था की उन्नति और विकास शामिल है। संस्था की आय/संपदा का कोई भी भाग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में लाभ के तौर पर ऐसे व्यक्तियों को नहीं दिया जाएगा अथवा स्थानांतरित किया जाएगा जो संस्था के सदस्य हैं। बशर्ते इसमें शामिल किसी भी कारण से किसी ऐसे सदस्य को विश्वास में मानदेय के रूप में भुगतान को रोक नहीं जाएगा जिसने न किया गया हो अथवा किसी अन्य व्यक्तियों को संस्था की सेवा की हो अथवा यात्रा, कहीं रुकने और अन्य सम्मान प्रभावों के लिए भुगतान न किया गया हो और ऐसे सभी व्यय जिन्हें किसी उद्देश्यार्थ संस्था के लेखों में उचित तौर पर दर्शाया गया हो।

8.0 सम विश्वविद्यालय बनने वाली संस्था की घोषणा किए जाने के लिए कार्यप्रणाली

8.01 किसी संस्था को समविश्वविद्यालय घोषित करने के लिए प्रस्तावों पर विचार करने हेतु इन विनियमों में दिए गए न्यूनतम पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाली संस्थाएं अपने आवेदन विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में दो प्रतियों में सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, भारत सरकार को भेज

सकती हैं। प्रत्येक आवेदन के लिए आयोग को प्रोसेसिंग शुल्क का भुगतान सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 के पक्ष में आहरित डिमांड ड्राफ्ट के जरिए किया जाएगा।

- 8.02 यह अपने आवेदन के साथ प्रमाणपत्र सहित एक आश्वासन भी प्रस्तुत करेगा कि इसके द्वारा पहले से चलाए जा रहे व्यावसायिक कार्यक्रमों, यदि कोई हो, के लिए एआईसीटीई, एमसीआई, डीसीआई, एनसीटीई, बीसीआई, आईएनसी आदि जैसी संगत सांविधिक/विनियामक निकायों का अनुमोदन है। साथ ही ऐसे निकायों द्वारा दिए गए अनुमोदन के पत्र की सत्यापित प्रति भी लगाएंगे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक आवेदन के साथ जहां आवश्यक हो, संबद्ध राज्य सरकार से आवश्यकता प्रमाण पत्र भी लगा होना चाहिए।
- 8.03 अपने आवेदन के साथ इसे संबद्ध विश्वविद्यालय/संबद्ध विश्वविद्यालयों जैसा भी मामला हो, से एक प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। इस प्रमाणपत्र में दिया जाना चाहिए कि ऐसी संस्था/संस्थाओं में पहले से दाखिल छात्र प्रस्तावित समविश्वविद्यालय संस्था का महत्वपूर्ण भाग होंगे। उक्त संबद्ध विश्वविद्यालय/संबद्ध विश्वविद्यालयों में दाखिल छात्र अपने संगत अकादमिक कार्यक्रमों को पूरा करने तक वर्तमान निबंधनों और शर्तों के अंतर्गत सभी उद्देश्यों के लिए उस विश्वविद्यालय के छात्र होंगे।
- 8.04 मानव संसाधन विकास मंत्रालय परामर्श हेतु इन आवेदनों को आयोग को भेजेगा।
- 8.05 आयोग संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन की प्रारंभिक जांच करेगा और यदि आवश्यक हो तो कमियों के लिए यदि कोई हो, संस्था को लिखेगा और स्पष्टीकरण/अतिरिक्त सूचना/आवश्यक दस्तावेज मांगेगा। आयोग संबद्ध राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को आवेदन पर उनके विचार जानने के लिए भी लिखेगा।
- 8.06 इन विनियमों में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार गठित विशेषज्ञ समिति की सहायता से आयोग आवेदन की जांच करेगा। विशेषज्ञ समिति में आयोग का कोई वर्तमान सदस्य शामिल नहीं होगा। इस प्रकार से गठित विशेषज्ञ समिति में संबद्ध सांविधिक परिषद (परिषदों) का प्रतिनिधि एक सदस्य के रूप में शामिल होगा जिसके पास परामर्श की न मानने का अधिकार भी होगा।

8.07 विशेषज्ञ समिति अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित कार्य भी करेगी:-

- क) विस्तार में आवेदन की जांच और संवीक्षा करेगी;
- ख) संस्था का दौरा, इसके प्रमुख पणधारियों के साथ विचार विमर्श और इन विनियमों में दिए गए विश्वविद्यालय के संदर्भों और अन्दरों का संस्थान द्वारा पालन किया जा रहा है इसकी अकादमिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन करना;
- ग) उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर अकादमिक और अनुसंधान उत्कृष्टता सुनिश्चित करना;
- घ) स्नातक होने वाले छात्रों के कार्यनिष्पादन, पीएच.डी. के लिए पंजीकृत अनुसंधान अध्येताओं, पूरी हो गई और चल रही प्रायोजित अनुसंधान परियोजनाओं, सूचीबद्ध पत्र पत्रिकाओं में अनुसंधान प्रकाशन, पिछले पांच वर्ष के लिए पीएच.डी. आदि वाली संकाय जैसे मामलों पर विशिष्ट सूचना देना;
- ङ.) इसकी वित्तीय व्यवहार्यता को सुनिश्चित करने के लिए इसके रिक्त सत्यापित करना; और
- च) सरकार को उचित सलाह देने में मदद करने के लिए आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

8.08 विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के साथ-साथ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की टिप्पणियाँ यदि कोई हो, और सांविधिक और विनियामक निकायों के विचारों की जांच आयोग द्वारा की जाएगी और तत्पश्चात मंत्रालय के विचार हेतु आयोग अपनी राय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को प्रस्तुत करेगा। आयोग को सांविधिक निकाय की रिपोर्ट में न केवल कालेज के रूप में संस्था के कार्यनिष्पादन हेतु न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति को दर्शाया जाएगा बल्कि इसमें शिक्षा और अनुसंधान के लिए उच्च मानकों में संस्था की उपलब्धियों के अपने मूल्यांकन के साथ-साथ परंपरागत व्यावसायिक कालेज की तुलना में विश्वविद्यालय के स्तर के अनुसार नवाचार और उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने की इसकी क्षमता को भी शामिल किया जाना चाहिए।

8.09 किसी संस्था को समविश्वविद्यालय संस्था अथवा किसी अन्य रूप में घोषित किए जाने के लिए केन्द्र सरकार को परामर्श देने के कर्तव्यों का आयोग की

रूप में उल्लेख होगा। इसके साथ समविश्वविद्यालय संस्था के भाग के रूप में संस्थाओं की संख्या और नामों का भी उल्लेख होगा।

- 8.10 केन्द्र सरकार को अपनी अंतिम सिफारिशों में आयोग प्रस्तावित समविश्वविद्यालय संस्था के नाम पर चल और अचल परिसंपत्तियों के स्थानांतरण से संबंधित आवश्यक दस्तावेज के प्रस्तुतीकरण और अन्य शर्तों यदि कोई हों, के बारे में सरकार को सूचित करेगा।
- 8.11 प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार अनुच्छेद 8.05 के अंतर्गत अपने विचार देते हुए पारदर्शी नीति बनाएगी और आयोग द्वारा दिए गए प्रोफार्मा में 60 दिनों के अंदर अपनी विचारित टिप्पणियों को आयोग और केन्द्र सरकार को भेजेगी जिसमें संबद्ध संस्था को भी एक प्रति होगी। यदि पत्र जारी करने के 60 दिनों के अंदर आयोग को ऐसी कोई टिप्पणियां प्राप्त नहीं होती हैं तो यह मान लिया जाएगा कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार को आवेदन पर कोई टिप्पणी नहीं देनी है।
- 8.11.1 प्रस्ताव की सिफारिश करने वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार को प्रस्तावित समविश्वविद्यालय के बंद हो जाने की स्थिति में अथवा अन्य किसी भी कारण से, दाखिल छात्रों के हितों की रक्षा करने की अपनी इच्छा को दर्शाना होगा।
- 8.12 इन विनियमों में दी गई सभी आवश्यकताओं को संस्था पूरा करती है इस बात से सहमत हो जाने के पश्चात केन्द्र सरकार अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत ऐसी संस्था को समविश्वविद्यालय संस्था के रूप में घोषित करने की अधिसूचना जारी कर सकती है। यह घोषणा आरंभ में पांच वर्ष की अवधि के लिए होगी। 'समविश्वविद्यालय' की घोषणा का पुष्टिकरण इन विनियमों के प्रावधानों को इसके द्वारा पूरा किए जाने की समीक्षा और इसके संतोषजनक कार्यानिष्पादन पर आधारित होगा।
- 8.13 यदि आयोग के परामर्श पर केन्द्र सरकार इस निर्णय पर पहुंचती है कि संस्था समविश्वविद्यालय संस्था के रूप में घोषणा किए जाने योग्य नहीं है तो सरकार तदनुसार कारण देते हुए संस्था को सूचित कर सकती है।

- 8.13.1 यदि सरकार आयोग की सिफारिश से सहमत नहीं है तो सरकार को लिखित में इसका स्पष्टीकरण प्रदान करना होगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।
- 8.14 किसी संस्था को समविश्वविद्यालय संस्था के रूप में घोषित न किए जाने के निर्णय पर पहले के निर्णय की तारीख से एक साल से पहले समीक्षा हेतु विचार नहीं किया जाएगा। ऐसी समीक्षा का प्रस्ताव संबद्ध संस्था द्वारा केन्द्र सरकार को विशेष अनुरोध पर ही किया जाएगा। संस्था ऐसी समीक्षा के लिए केन्द्र सरकार को अपना अनुरोध तभी कर सकती है जब वह केन्द्र सरकार द्वारा अपने पहले निरस्त आवेदन/प्रस्ताव में दी गई कमियों को सही कर लेती है।
- 8.15 केन्द्र सरकार आयोग के परामर्श के लिए मामला आयोग को भेज सकती है
- 8.16 आयोग एक नई विशेषज्ञ समिति गठित करके संशोधित आवेदन की संवीक्षा और मूल्यांकन के लिए ऊपर अनुच्छेद 8.07 के माध्यम से 8.05 के अनुसार इस विनियम में विनिर्दिष्ट तरीके से समीक्षा प्रक्रिया आरंभ कर सकता है। इस समिति का आकार कम से कम उसी पुरानी समिति की तरह होगा जिसमें इस प्रस्ताव को निरस्त किया था, इसके सदस्यों में पिछली समिति का कोई विशेषज्ञ सदस्य नहीं होगा।
- 8.17 ऐसी 'समीक्षा' पर लिए गए निर्णय पर पुनः विचार अथवा पुनः समीक्षा नहीं की जाएगी। तथापि आवेदक संस्था को अनुमति होगी कि वह संबंध संस्था को 'समीक्षा' के संबंध में मंत्रालय द्वारा दिए गए निर्णय की तारीख से कम से कम तीन वर्ष के अंतराल के पश्चात् 'समविश्वविद्यालय संस्था' की स्थिति के लिए पुनः आवेदन दे सके।
- 8.18 आयोग प्रत्येक आवेदन की स्थिति के संबंध में सूचना अपनी वेबसाइट पर मासिक आधार पर डालेगा। केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की गई अधिसूचनाओं में दी गई शर्तों की पूर्ति पर प्रगति रिपोर्ट देते हुए आयोग केन्द्र सरकार वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

9.0 सम विश्वविद्यालय बनने वाली संस्था का नए वर्ग में आना

9.1 इस वर्ग के अंतर्गत समविश्वविद्यालय संस्था के रूप में घोषित करने की मांग करने वाली संस्था को इस संबंध में तथ्य प्रस्तुत करने होंगे कि वह ज्ञान के विशेष और उभरते हुए क्षेत्रों को समर्पित है, परंतु परंपरागत वर्तमान संस्थाओं द्वारा अनुकरणीय नहीं है—विशेष रूप से अध्ययन और अनुसंधान के विशिष्ट क्षेत्रों में—जिन्हें देश की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के लिए अथवा हमारी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित किया जाता है—इसमें अकादमिक समुदाय के विशिष्ट व्यक्तियों के साथ विस्तृत विचार विमर्श की सुगठित प्रक्रिया से सुनिश्चित किया जाता है। इस उद्देश्यार्थ आवेदक संस्था को ज्ञान के उभरते हुए क्षेत्रों में अपने द्वारा प्रदान किए जाने वाले पाठ्यक्रमों और अनुसंधान कार्यक्रमों की विस्तृत पाठ्यचर्या का ब्यौरा देना होगा।

9.1.1 ऐसी नई संस्थाएं अपने कार्यों का विस्तार करने और संबंधित/अनुपूरक क्षेत्रों में प्रवेश करने की इच्छा रखती हैं तो ऐसा करना तभी संभव होगा यदि समविश्वविद्यालय का दर्जा की सरकार की पुष्टि के पांच वर्ष की समाप्ति पर समीक्षा के पश्चात इसके दर्जे की पुष्टि हो जाती है। इसके लिए इन्हें केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी जिसके लिए आयोग ऐसी संस्थाओं को ऐसी अनुमति देने से पहले सख्त समकक्ष समीक्षा करेगा।

9.2 सरकार (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) के माध्यम से परामर्श हेतु नए वर्ग के अंतर्गत समविश्वविद्यालय संस्था के रूप में स्वयं को घोषित कराने के लिए किसी संस्था से आवेदन की प्राप्ति पर आयोग विनियमों के अनुच्छेद 8 में दी गई प्रक्रिया का पालन करेगा। तथापि, अनुच्छेद 8 में दी गई प्रक्रिया आरंभ करने से पहले आयोग इस आवेदन की जांच एक समिति के माध्यम से करेगा जिसमें एक अध्यक्ष और संगत विषयों में तीन विशेषज्ञ शामिल होंगे जो अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामित किए जाएंगे। इस समिति में संगत सांविधिक परिषद का एक प्रतिनिधि भी शामिल होगा। आवेदक संस्था समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण करेगा। समिति का यह कर्तव्य होगा कि यह यह सिफारिश करे कि यह संस्था ज्ञान के उभरते क्षेत्रों में आयोग की नीति के अनुरूप है और इस संस्था पर नए वर्ग के अंतर्गत विचार किया जा सकता है। आयोग की विशेषज्ञ समिति द्वारा संस्था के दौरे पर निर्णय लेने से पहले समिति को यह सब सिफारिशें करनी होंगी।

- 9.3 केंद्र सरकार अनुच्छेद 8 में दी गई प्रक्रिया का पालन करेगी और इस बात का संतोष होने पर कि संस्था इन विनियमों में दी गई आवश्यकताओं को पूरा करती है वह नए वर्ग के अंतर्गत संस्था को अन्तिम रूप से ~~संविधिक~~ संस्था घोषित करने की अधिसूचना जारी कर सकती है।
- 9.4 केंद्र सरकार आयोग के परामर्श पर नए वर्ग के अंतर्गत ऐसी संस्था के पांच वर्ष पूरे हो जाने के पश्चात संस्था को दिए गए समविश्वविद्यालय के दर्जे को, उदघोषणा के द्वारा पुष्टि प्रदान कर सकती है। संबद्ध संस्था की समीक्षा के लिए आयोग के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति (समितियों) की पांच निरंतर वार्षिक कार्यनिष्पादन रिपोर्टों के माध्यम से इस उद्देश्यार्थ आयोग अपनी सलाह दे सकता है। यदि केंद्र सरकार इस निर्णय पर पहुंचती है कि संस्था समविश्वविद्यालय संस्था की घोषणा किए जाने के लिए पात्र नहीं है तो वह तदनुसार कारण बताते हुए संस्था को सूचित कर सकती है।

10.0 वित्तपोषण

ऐसी संस्थाएं जिन्हें समविश्वविद्यालय संस्था घोषित कर दिया गया है वे अपने अनुरक्षण और विकासशील व्यय जिसमें व्यय और भविष्य के विस्तार में वेतन और गैर वेतन में वृद्धि शामिल है, के लिए उन्हीं निधीयन स्रोतों से निधियां प्राप्त करते रहेंगे जो ऐसी उदघोषणा ने पहले उन्हें वित्तपोषित कर रहे थे। ऐसी संस्थाएं अपने वित्त को अनुपूरित भी कर सकती हैं।

11.0 मानकों का अनुरक्षण

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया, हॉटल काउंसिल आफ इंडिया, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, बार काउंसिल आफ इंडिया, इंडियन नर्सिंग काउंसिल आदि जैसी संबद्ध सांविधिक/विनियामक निकायों द्वारा अथवा आयोग द्वारा कालेज स्तरीय संस्थाओं के लिए विनिर्दिष्ट निदेशात्मक अकादमिक और भौतिक अयसंरचना, शिक्षकों की अर्हता आदि के न्यूनतम मानकों से अधिक प्रतिमानकों को समविश्वविद्यालय संस्था को बनाए रखना होगा और जहां भी लागू हो वहां अध्ययन के विभिन्न कार्यक्रमों को चलाने के लिए उनका अनुमोदन प्राप्त करेगा। आयोग द्वारा गठित समितियों द्वारा इसकी आवधिक मनीटरिंग की जाएगी।

12.0 नए विभाग, ऑफ-कैम्पस केन्द्र और विदेशी परिसर

- 12.01 जैसा कि केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना में और इसके विशेषज्ञता के क्षेत्र के भीतर आने वाले अध्ययन के अनुमोदित कार्यक्रमों के आधार में घोषित किया गया है कोई भी समविश्वविद्यालय संस्थान सामान्यतः अपने स्वयं के मुख्य परिसर के भीतर ही कार्य करेगा।
- 12.02 यदि कोई समविश्वविद्यालय संस्थान किसी ऐसे विषय, जो इसके विशेषज्ञता के अथवा समवर्गी क्षेत्र में नहीं है, के लिए कोई नया विभाग शुरू करना चाहता है तो यह ऐसा केवल आयोग की पूर्व अनुमति से और तभी कर सकता है यदि वह क्षेत्र इस समविश्वविद्यालय संस्थान के उन उद्देश्यों के अंतर्गत शामिल हो जिनके लिए इस समविश्वविद्यालय संस्थान की स्थापना की गई थी।
- 12.03 किसी भी समविश्वविद्यालय संस्थान को निम्नलिखित परिस्थितियों को इसके अपनी अनुमोदित भौगोलिक सीमाओं के बाहर कार्य संचालन तथा दूरवर्ती परिसर (परिसरों)/विदेशी परिसर (परिसरों) को शुरू करने की अनुमति दी जा सकती है।
- 12.03.1 यह कम से कम तीन वर्ष की अवधि से समविश्वविद्यालय संस्थान के रूप में विद्यमान हो।
- 12.03.2 यह स्नातकोत्तर और शोध कार्यक्रमों का संचालन कर रहा हो।
- 12.03.3 इसने उत्कृष्ट और नवाचारी शिक्षण जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मॉड्यूलर संरचना की शुरुआत, सतत आंतरिक मूल्यांकन आदि जैसे व्यवहारिक शैक्षिक और परीक्षा संबंधी सुधार शामिल हैं और सार्थक एवं सोद्देश्य शोध तथा विस्तार कार्यक्रमों के लिए ख्याति अर्जित की हो।
- 12.03.4 शिक्षण के न्यूनतम मानकों, संकाय की अर्हता, अखिल भारतीय स्तर पर विद्यार्थियों के योग्यता आधारित दाखिलों और यथोचित शुल्क संरचना के संबंध में आयोग और अन्य सांविधिक/विनियामक निकायों के संबद्ध विनियमों/मानदंडों के अनुपालन के संबंध में इसका रिकार्ड अच्छा हो।

12.03.5 नए विभाग/कार्यक्रम शुरू करने के लिए इसने, जहां भी लागू हो, सांविधिक/विनियामक निकाय का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया हो, उक्त निकाय की सभी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हो।

12.03.6 इसके पास प्रस्तुत उच्चतम बैज के साथ राष्ट्रीय प्रत्यायन एवं मूल्यांकन परिषद् का वर्तमान प्रत्यायन हो।

12.03.7 इसके पास प्रस्तावित नए विभाग/दूरवर्ती केन्द्र/विदेशी परिसर शुरू करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन हों।

12.03.8 इसने समविश्वविद्यालय संस्था के ऑफ-कैम्पस/विदेशी कैम्पस की स्थापना करने और उन्हें चलाने के लिए किसी अन्य संगठन के साथ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से फेंचाइजी करार संवन्धन न किया हो।

12.04 किसी भी समविश्वविद्यालय संस्था द्वारा मुख्य परिसर में अथवा अनुमोदित ऑफ कैम्पस में कोई नया विभाग केवल आयोग के अनुमोदन से ही खोला जा सकता है।

12.05 किसी भी समविश्वविद्यालय संस्था द्वारा नए ऑफ-कैम्पस केन्द्र की स्थापना आयोग की सिफारिश पर केवल केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से ही की जा सकती है। ऑफ-कैम्पस की स्थापना के प्रस्ताव पर केन्द्रीय सरकार संबंधित राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकार के विचारों को भी ध्यान में रखेगी।

12.06 किसी भी समविश्वविद्यालय संस्था द्वारा विदेशी परिसर की स्थापना आयोग की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार और मेजबान देश की सरकार से विधिवत अनुमति प्राप्त करने के बाद ही की जाएगी। बशर्ते कि वह देश जहां इस प्रकार विदेशी परिसर स्थापित करना प्रस्तावित है, को इस प्रकार की स्थापना हेतु इसके अनुमोदन की आवश्यकता होगी। इसके पश्चात उस देश द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के साथ अनुमति हेतु केन्द्र सरकार को आवेदन दिया जाएगा।

बशर्ते कि उस देश में जहां विदेशी परिसर स्थापित करने का प्रस्ताव है, को उस देश के प्रथम उपबंध में दिए अनुसार अनुमोदन हेतु भारत सरकार की पूर्व सहमति अपेक्षित है।

तो केन्द्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिश के प्रस्ताव पर 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' दे सकती है परंतु इस अनापत्ति को, समविश्वविद्यालय संस्था द्वारा विदेशी परिसर स्थापित करने हेतु केन्द्र सरकार की अनुमति नहीं समझा जाएगा। इस प्रकार की समविश्वविद्यालय संस्था एक वचनपत्र भी प्रस्तुत करेगी कि यह उस देश द्वारा निर्धारित सभी विधियों, मानदंडों और मानकों का अनुपालन करेगा जहां विदेशी परिसर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

- 12.07 किसी नए ऑफ कैम्पस/विदेशी कैम्पस को शुरू करने की इच्छा रखने वाली कोई समविश्वविद्यालय संस्था केन्द्र/दूरवर्ती परिसर शुरू करने की प्रस्तावित तारीख से कम से कम छः माह पूर्व निर्धारित प्रपत्र में भारत सरकार को आवेदन करेगी। भारत सरकार इस प्रस्ताव को परामर्श हेतु आयोग के पास भेजेगी। परिसर अथवा अनुमोदित दूरवर्ती केन्द्र में कोई नया विभाग अथवा अनुमोदित ऑफ-कैम्पस खोलने के मामले में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन सीधे आयोग को भेजा जाएगा।
- 12.08 केन्द्रीय सरकार को अपना परामर्श भेजने से पूर्व आयोग अवसंरचनागत सुविधाओं, कार्यक्रमों, वित्तीय व्यवहार्यता इत्यादि का सत्यापन करने के लिए प्रस्तावित नए ऑफ कैम्पस (कैम्पसों) और विदेशी परिसर (परिसरों) का स्थल दौरा/सत्यापन करेगा/नया विभाग स्थापित के प्रस्ताव के मामले में आयोग स्थल दौरे के बाद निर्णय लेगा।
- 12.09 यदि समविश्वविद्यालय संस्था को अनुमति नहीं दी जाती है तो वह समविश्वविद्यालय संस्था अपने पूर्ववर्ती आवेदन की नामंजूरी की तारीख से दो वर्ष पश्चात ही ऐसी अनुमति के लिए पुनः आवेदन कर सकती है।
- 12.10 ऑफ-कैम्पस केन्द्र/विदेशी परिसर में आयोग और संबद्ध सांविधिक/विनियामक निकाय द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुसार पर्याप्त शैक्षिक और भौतिक अवसंरचनागत सुविधाएं होंगी। ऐसी सुविधाएं ऑफ-कैम्पस केन्द्र/विदेशी परिसर के आकार और क्रियाकलापों के समानुपात में होंगी। समविश्वविद्यालय संस्था के विदेशी परिसर स्थापित राष्ट्र के मानकों और प्रतिमानों का पालन करेगा।

12.11 प्रवेश, शिक्षण, मूल्यांकन, डिग्री प्रदान करना इत्यादि के मामलों में ऑफ-कैम्पस/विदेशी कैम्पस सीधे मूल समविश्वविद्यालय संस्था द्वारा प्रशासित होंगे। विदेशी परिसरों के मामले में पट्टा समविश्वविद्यालय के नाम पर (ऐसा विदेशी परिसर स्थापित करने का प्रस्ताव है वह उस देश की क्रियाविधि के अनुसार) स्वीकार्य होगा। यदि किसी विशेष देश में पट्टा अनुमेय नहीं है तो वहां भूमि और अन्य परिसंपत्तियां किसी नीतिगत भागीदार के नाम पर स्वीकार्य होंगी। इसके लिए समविश्वविद्यालय संस्था नीतिगत भागीदार के साथ विधिवत पंजीकृत समझौता ज्ञापन/सहयोग करेगी जो भारत में उस समय लागू कानून के अनुसार शासित होगा।

12.12 नए विभाग/ऑफ-कैम्पस केन्द्र/विदेशी परिसर अध्ययन के केवल उन्हीं कार्यक्रमों को प्रस्तुत करेंगे जो समविश्वविद्यालय संस्था के उपयुक्त निकायों और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारतीय चिकित्सा परिषद, भारतीय दंत चिकित्सा परिषद, भारतीय फार्मसी परिषद, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय नर्सिंग परिषद इत्यादि, जो भी लागू हो, जैसे संबद्ध सांविधिक/विधियामक निकाय द्वारा अनुमोदित किए गए हों। यदि उच्च अध्ययन की किसी नई अथवा मौजूदा संस्था को किसी मौजूदा समविश्वविद्यालय संस्था के संघटक एकक के रूप में उसके विस्तार के अंतर्गत लाए जाने का प्रस्ताव है, तो मौजूदा समविश्वविद्यालय संस्था की परिधि के अंतर्गत संस्था को लाए जाने से संबंधित यूजीसी अधिनियम की धारा 3 के तहत घोषणा की अधिसूचना की तारीख के बाद की तारीख को उस संस्था में दाखिल हुए विद्यार्थी ही समविश्वविद्यालय संस्था द्वारा परीक्षा लिए जाने के पात्र होंगे और इसीलिए अपने अध्ययन के संबंधित पाठ्यक्रमों अथवा कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर समविश्वविद्यालय संस्था की डिग्री अथवा अन्य किसी अर्हता के पात्र होंगे।

12.13 किसी विदेशी परिसर के मामले में मुख्य परिसर से/को निधियों का प्रेषण भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों द्वारा शासित होगा।

12.14 ऑफ-कैम्पस/ओवरसीज कैम्पस के समग्र कार्य निष्पादन की मानीटरिंग आयोग द्वारा छः वर्ष के लिए द्विवार्षिक रूप से की जाएगी और तत्पश्चात पांच वर्ष के बाद की जाएगी तथा प्रबंध, शैक्षिक विकास और सुधार पर उसके निर्देश कैम्पस के लिए अनिवार्य होंगे।

12.15 यदि समविश्वविद्यालय संस्था के कैम्पस के कार्य आयोग द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करते हैं और आयोग द्वारा यथा मूल्यांकित दो लगातार समीक्षाओं के लिए असंतोषजनक हैं तो समविश्वविद्यालय संस्था को आयोग की सलाह पर केन्द्र सरकार द्वारा संबद्ध परिसर/परिसर बाह्य केन्द्र को बंद करने की सलाह दी जा सकती है। आयोग ऐसे परिसर बाह्य केन्द्र/कैम्पस के विरुद्ध प्राप्त गंभीर शिकायतों के आधार पर दोषी समविश्वविद्यालय संस्था के विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है। छात्रों के हित में आयोग ऐसे निर्देश की तारीख के अनुसार नामांकित छात्रों के अंतिम बैच के उत्तीर्ण होने तक केन्द्र/कैम्पस को कार्य करने की अनुमति दे सकता है। समविश्वविद्यालय संस्था केन्द्र/परिसर में संकाय/स्टाफ के हितों की रक्षा करने के लिए उचित कदम उठाएगा। केन्द्र/कैम्पस के बंद होने की स्थिति में उसकी संपत्तियां और देनदारियां समविश्वविद्यालय संस्था को हस्तांतरित हो जाएगी।

12.16 जहां भी सांविधिक परिषदों अथवा मेजबान राष्ट्र द्वारा ऑफ-कैम्पस और विदेशी परिसरों की स्थापना के लिए आवश्यक होगा वहां आयोग समविश्वविद्यालय संस्थाओं को 'सिद्धांततः अनापत्ति' दे सकता है बशर्ते वह प्रस्ताव की व्यवहार्यता से संतुष्ट हो। परंतु इस प्रकार के अनापत्ति को सम विश्वविद्यालय संस्था द्वारा ऑल-कैम्पस केन्द्र स्थापित करने की अनुमति नहीं माना जाएगा। ऐसे मामलों में आयोग द्वारा इन विनियमों के अंतर्गत अनौपचारिक प्रस्ताव (वों) की जांच की जा सकती है। आयोग/सरकार के अंतिम अनुमोदन के पश्चात ही समविश्वविद्यालय संस्थाएं इन पाठ्यक्रमों में छात्रों को दाखिला दे सकती हैं।

13.0 समविश्वविद्यालय संस्थाओं के तत्वाधान के अंतर्गत अन्य संस्थाओं का समावेशन

13.01 जैसा कि ऊपर अनुच्छेद 8.12 में उल्लिखित है समविश्वविद्यालय संस्था समान प्रबंधन के अंतर्गत विद्यमान संस्थाओं को घटकीय संस्थाओं/इकाइयों के रूप में समाविष्ट करने के लिए आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में आवेदन कर सकती है। ऐसा वह समविश्वविद्यालय संस्था के रूप में अपने दर्जे की पुष्टि के बाद ही कर सकती है।

- 13.02 शिक्षा के विशेषाधिकार के प्रयोग को रोकने के लिए इस संबंध में समय-समय पर आयोग द्वारा लगाई गई शर्तों का सभी समविश्वविद्यालय संस्थाओं द्वारा पालन किया जाना आवश्यक होगा।
- 18.03 यदि समान प्रबंधन के अंतर्गत विद्यमान संस्था विश्वविद्यालय से संबद्ध है तो इसे समविश्वविद्यालय संस्था के तत्वाधान में तभी लिया जा सकेगा जब यह संबद्ध विश्वविद्यालय से असंबद्ध हो जाएगी। संबद्ध विश्वविद्यालय इसकी सहमति भी देगा कि संस्था(ओं) विशेष के छात्र जिन्होंने वहां दाखिला लिया हुआ है वे सभी उद्देश्यों के लिए इसके संबद्धन के अंतर्गत अपने पाठ्यक्रम को जारी रख सकेंगे और वह उन छात्रों को डिग्री भी प्रदान करेगा जो अभी संस्था(ओं) से पाठ्यक्रम कर रहे हैं।
- 13.04 ऐसी संस्थाओं के पास, वर्तमान में मान्य, प्रदत्त शीर्षस्थ ग्रेड का मान्य प्रत्यायन होना चाहिए जो या तो राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन बोर्ड से होना चाहिए अथवा इसके सभी पात्र पाठ्यक्रम राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से अथवा समय-समय पर आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त प्रत्यायन एजेंसी से प्रत्यायित होने चाहिए।
- 13.05 समविश्वविद्यालय संस्था जो किसी संस्था को अपनी घटकीय इकाई के रूप में, अपने तत्वाधान में लाना चाहती है उसे आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रोफार्म में दो प्रतियों में, अपना प्रस्ताव सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) को प्रस्तुत करना चाहिए बशर्ते उक्त संस्था इन विनियमों के अंतर्गत पात्रता मानदंडों और अन्य संगत शर्तों को पूरा करे।
- 13.06 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार परामर्श हेतु प्रस्ताव की एक प्रति आयोग को भेजेगा।
- 13.07 प्राप्त प्रस्ताव की जांच के लिए तब आयोग अनुच्छेद 8.05 से 8.07 के अंतर्गत दी गई कार्य प्रणाली को अपनाएगा।
- 13.08 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को उपयुक्त सिफारिश करने से पहले आयोग अपनी विशेषज्ञ समिति के माध्यम से सभी संगत घटकों और पहलुओं को सत्यापित करेगा।

- 13.09 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को सिफारिश करने से पहले संबद्ध सांविधिक/विनियामक निकाय के विचारों/टिप्पणियों और संबद्ध राज्य सरकार के विचार, यदि कोई हों, के साथ विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के साथ-साथ निरीक्षण रिपोर्ट की जांच कार्य-पद्धति के अनुसार आयोग द्वारा की जाएगी।
- 13.10 यदि निरस्तीकरण होता है तो केन्द्र सरकार तदनुसार संस्था को सूचित कर सकती है।
- 13.11 विनियम 8 में दिए गए कार्य पद्धति के संगत कदम उठाने के पश्चात केन्द्र सरकार निम्नलिखित से संतुष्ट होने पर समविश्वविद्यालय संस्था के तत्वाधान के अंतर्गत संस्था के समावेशन को अधिसूचित करेगी:
- क) उत्कृष्ट और नवाचार शिक्षण के लिए, अर्थपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण अनुसंधान के लिए मॉड्यूलर अवसंरचना, सतत आंतरिक मूल्यांकन इत्यादि जैसे शैक्षिक प्रक्रिया और परीक्षा सुधार के लिए तथा विस्तार क्रियाकलापों के लिए सम्मान प्राप्त किया हो; और
 - ख) शिक्षा के माध्यम के न्यूनतम मानकों, अध्यापकों की योग्यताओं, अखिल भारतीय स्तर पर छात्रों के मेरिट आधारित प्रवेश और समुचित फीस ढांचा के संबंध में आयोग तथा संबद्ध सांविधिक/विनियामक निकायों के संगत विनियमों/मानदंडों के अनुरूप अच्छा रिकार्ड।
- 13.12 समविश्वविद्यालय के तत्वाधान में आने वाली किसी संस्था के संबंध में समविश्वविद्यालय केवल स्वयं को संबद्ध विश्वविद्यालय से अलग करने के पश्चात संस्था में नामांकित छात्रों को डिग्री प्रदान करेगा। समविश्वविद्यालय संसी के तत्वाधान में शामिल होने से पहले ऐसी संस्था में नामांकित छात्र उस विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त करेंगे जिनसे वह संस्था उनके पंजीकरण के समय संबद्ध थी।
- 13.13 एक बार कोई संस्था समविश्वविद्यालय के तत्वाधान में आ जाती है तो वह समविश्वविद्यालय संस्था के ऑफ-कैम्पस के समान होगी और समविश्वविद्यालय संस्था के ऑफ-कैम्पस से संबंधित विनियमों के सभी अनुच्छेद उस पर लागू होंगे।

13.14 संस्था की सभी चल और अचल संपत्ति तथा मौजूदा मानव शक्ति और इसके रिकार्ड (उनको छोड़कर जो ऐसे छात्रों से संबद्ध है जिन्होंने संस्था से पास होने तक पहले ही पंजीकरण कर लिया है) को अधिसूचना से पहले समविश्वविद्यालय संस्था को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

13.15 यदि कोई संस्था जो उसी पंजीकृत सोसायटी/न्यास के तहत न हो और समविश्वविद्यालय संस्था के तत्वावधान में आना चाहती हो तो वह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम अथवा न्यास अधिनियम, जैसा भी मामला हो, की प्रक्रिया के अनुसार सोसायटी/न्यास को आवेदन करेगी और सोसायटी/न्यास का एक भाग बन जाएगी। इसके पश्चात् सोसायटी/न्यास इसे समविश्वविद्यालय संस्था के तत्वावधान में लाने के लिए इन विनियमों का पालन करेगी।

13.16 यदि समविश्वविद्यालय संस्था के तत्वावधान में लाने के लिए किसी संस्था का आवेदन किसी भी कारण से अस्वीकृत कर दिया जाता है तो समविश्वविद्यालय संस्था अपने पूर्व आवेदन की अस्वीकृति की तारीख से दो वर्ष के पश्चात् इसके लिए पुनः आवेदन करने की पात्र होगी।

14.0 संयुक्त कार्यक्रम

14.1 कोई समविश्वविद्यालय संस्था आयोग की पूर्व अनुमति के साथ भारत तथा विदेशों में किसी अन्य विश्वविद्यालय/समविश्वविद्यालय संस्था के साथ संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम चला सकती है। प्रस्तावित संयुक्त कार्यक्रम ऐसे कार्यक्रमों के लिए समय-समय पर लागू होने वाले अधिनियमों और आयोग के नियमों के अनुरूप होना चाहिए।

14.2 इनमें पर्याप्त रक्षोपाय होंगे ताकि ऐसे कार्यक्रमों में नामांकित छात्रों के हितों की रक्षा की जा सके।

14.3 ये कार्यक्रम अनिवार्य मूल्यांकन और प्रत्यायन के अधीन होने चाहिए।

15.0 समविश्वविद्यालय संस्था सभी के लिए खुली हों

15.1 किसी समविश्वविद्यालय संस्था में प्रवेश और रोजगार मत, धर्म, जाति अथवा संप्रदाय और भारत में आवास के किसी भी क्षेत्र/स्थान पर ध्यान न देते हुए भारत के सभी नागरिकों के लिए खुला होगा।

15.2 सार्वजनिक और निजी वित्तपोषित विश्वविद्यालय स्तरीय संस्थाओं के लिए लागू सभी नीतियां और प्रक्रियाएं उचित वर्ग की समविश्वविद्यालय संस्थाओं पर लागू होंगी।

16.0 समविश्वविद्यालय संस्था एकात्मक होगी

एक बार किसी संस्था को एकात्मक संस्था का दर्जा दे दिया जाता है तो वह किसी अन्य संस्था के साथ संबद्ध नहीं होगी।

17.0 आरक्षण नीति

समविश्वविद्यालय संस्था प्रवेश और भर्ती में समय-समय पर लागू संसद के किसी अधिनियम के अनुरूप आरक्षण नीति को कार्यान्वित करेगी।

18.0 दूरस्थ शिक्षा

इन विनियमों के तदनुरूप केन्द्र सरकार द्वारा घोषित किसी भी समविश्वविद्यालय संस्था को दूरस्थ प्रणाली से कोई पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, इन विनियमों से पहले घोषित किसी भी संस्था को इन विनियमों के तदनुरूप अपने ऑफ-कैम्पस केन्द्र/अनुमोदित ऑफ-शोर कैम्पस से दूरस्थ प्रणाली में पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

19.0 विश्वविद्यालय निकायों की बैठकें

समविश्वविद्यालय संस्था प्रबंध बोर्ड, शैक्षिक परिषद् इत्यादि जैसे अपने सांविधिक निकायों की विनियमों के अनुसार नियमित अंतराल पर बैठकें

आयोजित करेगी और ऐसी प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त को संस्था की वेबसाइट पर दर्शाया जाएगा।

20.0 'विश्वविद्यालय' शब्द का प्रयोग

कोई समविश्वविद्यालय संस्था अपने नाम के आगे 'विश्वविद्यालय' शब्द का प्रयोग नहीं करेगी। परंतु वह अपने नाम के आगे "समविश्वविद्यालय" का उल्लेख कर सकती है।

21.0 नामावली में कुछ शब्दों के प्रयोग पर रोक

केवल केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित शैक्षिक संस्थाएं ही अपने नाम के आगे "भारतीय/राष्ट्रीय संस्था" (अंग्रेजी अथवा देशी भाषा में) का प्रयोग कर सकती हैं।

22.0 विनियमों का उल्लंघन करने के परिणाम

22.1 केन्द्र सरकार/आयोग को समविश्वविद्यालय संस्था, इसके भवनों, प्रयोगशालाओं, परीक्षाओं, समविश्वविद्यालय संस्थाओं द्वारा संचालित शिक्षण एवं अन्य कार्यों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा, और किसी समविश्वविद्यालय संस्था के मामले में केन्द्र सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यदि आवश्यक समझा जाए तो कोई जांच करने का अधिकार होगा।

22.2 स्वयं आयोग द्वारा समविश्वविद्यालय संस्था की जांच करने के पश्चात अथवा किसी अन्य भरोसेमंद स्रोत से प्राप्त कोई अन्य प्रमाणिक सूचना अथवा रिपोर्ट के आधार पर और समविश्वविद्यालय संस्था द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर विचार करने के पश्चात यदि आयोग इस बात से संतुष्ट है कि समविश्वविद्यालय संस्था ने इन विनियमों के किसी प्रावधान का उल्लंघन किया है अथवा आयोग द्वारा जारी किसी दिशा-निर्देश का उल्लंघन किया है तो आयोग संबद्ध समविश्वविद्यालय संस्था को आयोग द्वारा घोषित अवधि के लिए नए छात्रों को प्रवेश न देने के लिए निर्देश दे सकता है और इन विनियमों के जानबूझकर लगातार उल्लंघन के मामले में वह केन्द्र सरकार को उस अधिसूचना को हटाने की सलाह दे सकता है जिसमें संस्था को समविश्वविद्यालय संस्था के रूप में

घोषित किया गया था। ऐसी घोषणा को वापस लिए जाने की स्थिति में समविश्वविद्यालय संस्था की सभी चल और अचल संपत्तियां आयोग द्वारा जब्त कर ली जाएगी। पहले उल्लंघन के लिए ऐसी अधिसूचना को हटाए जाने की अवधि एक शैक्षिक सत्र तक सीमित होगी जिसे बार-बार उल्लंघन करने पर पांच शैक्षिक सत्र तक बढ़ाया जा सकता है। तथापि, गंभीर और जानबूझकर उल्लंघन करने के लिए समविश्वविद्यालय का दर्जा स्थायी रूप से हटा लिया जाएगा।

22.3 समविश्वविद्यालय के दर्जे को हटाए जाने की स्थिति में ऐसी विशिष्ट स्थिति के लिए लागू अथवा निर्धारित पूर्व प्रक्रियाओं के अनुसार छात्रों के हितों की रक्षा करने के लिए साथ-साथ कार्रवाई की जानी चाहिए।

22.4 यदि कोई समविश्वविद्यालय संस्था स्वयं को अथवा अपने घटकों को 'समविश्वविद्यालय संस्था' के दर्जे से हटाना चाहता है तो वह केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति से ऐसा कर सकता है। उन्हें हटाया जाना उस तारीख से लागू होगा जब नामांकित छात्रों का अंतिम बैच समविश्वविद्यालय संस्था से उत्तीर्ण हो जाए।

23.0 पुराने प्रस्तावों पर विचार करना

सभी प्रस्ताव (समविश्वविद्यालय के रूप में घोषित किए जाने अथवा ऑफ-कैम्पस/ऑफ-शोर कैम्पस की स्थापना के रूप में अनुमोदन अथवा समविश्वविद्यालय संस्था के तत्वावधान में ऑफ-कैम्पस केन्द्रों को शामिल करना चाहने वाले) जो आयोग में लंबित अथवा प्रक्रियाधीन हैं अथवा जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त किया गया है उन्हें नए विनियमों के द्वारा शासित होगा।

एन. ए. काज़मी, सचिव

[विज्ञापन III/4/113/10/असा.]

अनुबंध-1

1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत समविश्वविद्यालय संस्था के रूप में घोषित किए जाने की मांग करने वाली प्रत्येक संस्था को प्रस्तावित समविश्वविद्यालय संस्था के नाम और तरीके से सोसायटी अथवा किसी न्यास के रूप में पंजीकृत किया जाएगा।

2. ऐसी प्रत्येक संस्था को स्पष्ट रूप से निम्नलिखित को दर्शाना होगा:

- i) नाम: प्रस्तावित समविश्वविद्यालय संस्था के नाम के साथ सोसायटी/न्यास का नाम।
- ii) कार्यालय: सोसायटी अथवा न्यास का पंजीकृत कार्यालय, संस्था का अधिकारिक पता।
- iii) उद्देश्य: प्रस्तावित समविश्वविद्यालय संस्था का उद्देश्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा। उद्देश्य को सही प्रकार से परिभाषित और प्रस्तावित समविश्वविद्यालय संस्था के छात्रों, अध्यापकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को पूर्णतः ज्ञात होना चाहिए।
- iv) उपर्युक्त निर्धारित उद्देश्यों को कानून में धर्मार्थ प्रकृति के समझा जाएगा।

3. समविश्वविद्यालय संस्था के कार्यक्रम

3.1 इन उद्देश्यों को देखते हुए संस्थानों में निम्नलिखित होंगे:

- (i) प्रस्तावित अध्ययन कार्यक्रम और अनुसंधान अथवा सुविधाएं अध्ययन के उन शाखाओं में ऐसे माध्यम का प्रावधान करेंगी जो संस्था अधिगम की प्रोन्नति तथा ज्ञान के प्रसार के लिए आवश्यक समझें।

(ii) उन व्यक्तियों जिन्होंने अध्ययन कार्यक्रम और/अथवा अनुसंधान को संतोषजनक रूप से पूरा कर लिया है, को डिग्री और डिप्लोमा तथा/अथवा प्रमाण पत्रों की प्रकृति और परीक्षा एवं मूल्यांकन हेतु निर्धारित योजना।

(iii) विजिट्रशिप, फेलोशिप, पुरस्कार और मेडल जैसी अन्य शैक्षिक योजनाओं के ब्यौरे।

4. संस्था का प्रबंधन

4.1 नियमों के अनुसार विभिन्न प्राधिकारियों के गठन तक प्रबंध बोर्ड के पहले सदस्यों के नाम, पते और व्यवसाय जिन्हें संस्था के प्रबंधन के अंतर्गत गठित किया गया है, के ब्यौरे उनकी सहमति पत्र के साथ आवेदन के समय प्रस्तुत किए जायेंगे।

4.2 प्रबंध बोर्ड एक समेकित निकाय होगा जो इसे सुविचारित निर्णयों को शीघ्रता से लेने और उनका कार्यान्वयन करने तथा आपदा स्थिति से प्रभावी रूप से निपटने का पात्र बनाएगा।

4.3 प्रबंध बोर्ड में निम्नलिखित शामिल होंगे:-

- i) कुलपति अध्यक्ष
- ii) समकुलपति (जहां लागू हो)
- iii) संकाय के डीन दो से अधिक नहीं (वरिष्ठता के आधार पर रोटेशन द्वारा)
- iv) कुलाधिपति द्वारा नामित तीन प्रबुद्ध शिक्षाविद्
- v) केन्द्र सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परामर्श से नामित एक प्रबुद्ध शिक्षाविद्
- vi) वरिष्ठता के आधार पर रोटेशन द्वारा दो अध्यापक (प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसरों से)
- vii) प्रायोजक सोसायटी का एक नामित
- viii) रजिस्ट्रार, जो सचिव होगा

प्रबंध बोर्ड की सदस्यता की शर्तें और अधिकार निम्नानुसार होंगे:-

4.3.1 पदेन सदस्यों और शिक्षण स्टाफ के सदस्यों के अलावा प्रबंध बोर्ड के सभी सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए कार्यभार ग्रहण करेंगे और वे पुनःनियुक्ति के पात्र होंगे।

4.3.2 प्रबंधन बोर्ड में शिक्षण स्टाफ के सदस्य दो वर्ष की अवधि अथवा उनके शिक्षण स्टाफ के सदस्य बने रहने जो भी कम हो, तक के लिए कार्यभार संभालेंगे।

4.4 प्रबंध बोर्ड के अधिकार

प्रबंध बोर्ड प्रबंधन का मुख्य अंग होगा और समविश्वविद्यालय संस्था का प्रमुख कार्यकारी निकाय होगा और उसकी निम्नलिखित शक्तियां होंगी, नामतः:

- i) शैक्षिक परिषद् की सलाह पर शैक्षिक कार्य के लिए प्रभागों और विभागों की स्थापना करना और समविश्वविद्यालय संस्था के कार्य करना और उनको अध्ययन, शिक्षण और अनुसंधान के क्षेत्र आकर्षित करना;
- ii) शिक्षण एवं शैक्षिक पदों का सृजन करना, आयोग, और संबद्ध सांविधिक निकाय द्वारा यथाव्युज्जित उनकी संख्या, कैडर और अर्हताओं का निर्धारण करना और वित्त समिति के परामर्श से ऐसे पदों के वेतन का निर्धारण करना;
- iii) चयन समिति की सिफारिश के आधार पर आवश्यक समझे गए प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर और अन्य शैक्षिक स्टाफ की नियुक्ति करना;
- iv) समविश्वविद्यालय संस्था के प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और अन्य शैक्षिक स्टाफ के कर्तव्यों और सेवा शर्तों को शैक्षिक परिषद् के परामर्श से निर्धारित करना;
- v) विजिटिंग फैलो और विजिटिंग प्रोफेसर्स की नियुक्ति का प्रावधान करना;
- vi) निर्धारित कैडर के रूप में प्रशासनिक, मंत्रालयी और अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा वित्त समिति के परामर्श से उनकी नियुक्ति करना;

- vii) शिक्षण, शैक्षिक, तकनीकी, प्रशासनिक और अन्य स्टाफ के हित के लिए ऐसी पेंशन, बीमा, भविष्यनिधि और ग्रेच्युटी का गठन करना जो वह उचित समझे और समविश्वविद्यालय संस्था के स्टाफ और छात्रों के लाभ के लिए एसोसिएशन की स्थापना और सहायता, संस्था, निधियां, न्यास और परिवहन में सहायता देना;
- viii) समविश्वविद्यालय संस्था के कर्मचारियों के बीच अनुशासन को विनियमित और लागू करना तथा जहां भी आवश्यक हो, अनुशासनात्मक कार्रवाई करना;
- ix) समविश्वविद्यालय संस्था के कर्मचारियों और छात्रों की शिकायतों को दूर करने के लिए निर्णय देना;
- x) कुलपति को अनुपस्थिति की छुट्टी प्रदान करना और उसकी अनुपस्थिति के दौरान कार्य करने हेतु आवश्यक प्रबंध करना;
- xi) परीक्षा के परिणाम के आधार पर डिग्री और डिप्लोमा प्रदान करने की अनुमति देना और डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र और अन्य शैक्षिक शीर्षक तथा डिस्टिंक्शन प्रदान करना;
- xii) परीक्षकों, मॉडरेटर, टेबुलेटर और परीक्षाओं के लिए नियुक्त अन्य कर्मियों के वेतन और यात्रा तथा अन्य भत्तों को शैक्षिक परिषद् और वित्त समिति के परामर्श से निर्धारित करना;
- xiii) इस उद्देश्य के लिए तैयार किए जाने वाले नियमों के अनुसार ट्रेवलिंग फैलोशिप, छात्रवृत्ति, स्टूडेंटशिप, मेडल और पुरस्कारों सहित फैलोशिप गठित करना;
- xiv) समविश्वविद्यालय संस्था की ओर से किसी अचल संपत्ति को प्राप्त करने, उसके प्रबंधन तथा निपटान के संबंध में किसी मामले पर कार्यरत न्यासियों को सलाह देना;

- xv) ऐसी शर्तों जिन्हें आवश्यक समझा जाए पर समविश्वविद्यालय संस्था के उद्देश्यों के लिए आवश्यक भूमि अथवा भवन अथवा कार्य को लीज पर लेना अथवा उपहारस्वरूप प्राप्त करना अथवा अन्यथा खरीदना और ऐसे भवनों अथवा कार्यों पर निर्माण करना अथवा उनमें संशोधन करना और उनका रखरखाव करना;
- xvi) समविश्वविद्यालय संस्था की ओर से चल संपत्ति को हस्तांतरित करना अथवा हस्तांतरण को स्वीकार करना;
- xvii) कार्यरत न्यासियों (यदि कोई हो) के परामर्श से समविश्वविद्यालय संस्था से संबद्ध अथवा समविश्वविद्यालय संस्था के उद्देश्य के लिए प्राप्त संपत्ति, चल अथवा अचल के संबंध में यात्रा, सरकारी प्रतिभूतियों का हस्तांतरण, पुनः यात्रा, मोर्टगेज, लीज, बॉन्ड, लाइसेंस और करार करना;
- xviii) उद्देश्य के प्रावधानों के अनुरूप समविश्वविद्यालय संस्था के उद्देश्य हेतु अपील जारी करना, अनुदान, दान, सहयोग, उपहार, पुरस्कार, छत्रवृत्ति, फ़ीस और अन्य राशि प्राप्त करना, अनुदान और दान देना, पुरस्कार, छत्रवृत्ति देना इत्यादि;
- xix) धारक न्यासी (यदि कोई हो) के परामर्श से ऐसी शर्तों जो वह उचित समझे पर बॉन्ड, मोर्टगेज, प्रोमिजरी नोट्स अथवा अन्य दायित्वों अथवा प्रतिभूतियों अथवा समविश्वविद्यालय संस्था की संपत्तियों के आधार पर राशि उगाहना अथवा ऋण लेना, पैसा उगाहने में सभी व्यय और लिए गए ऋण का पुनर्भुगतान करना;
- xx) भारत सरकार के और अन्य प्रोमिजरी नोट्स, विनिमय बिल, चैक अथवा अन्य इंस्ट्रूमेंट को निकालना और स्वीकार करना और छूट देना तथा मोलभाव करना;
- xxi) ऐसी निधि को रखना जिसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा:
- (क) केन्द्र अथवा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदत्त सभी राशियां;

- (ख) समविश्वविद्यालय संस्था द्वारा प्राप्त सभी फीस और अन्य प्रभार;
- (ग) समविश्वविद्यालय संस्था द्वारा अनुदान, उपहार, दान, लाभ, अनुरोध अथवा हस्तांतरण द्वारा प्राप्त सभी राशि और
- (घ) समविश्वविद्यालय संस्था द्वारा किसी अन्य तरीके से अथवा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त सभी राशियां;
- xxii) समविश्वविद्यालय संस्था का किसी एक अथवा अधिक अनुसूचित बैंकों के साथ खाता अथवा खाते खोलना और उसको संचालित करने के लिए प्रक्रिया निर्धारित करना;
- xxiii) अनुसूचित बैंकों में निधियों में जमा सारी राशि को जमा करवाना और उन्हें वित्त समिति के परामर्श से निवेश करना;
- xxiv) समविश्वविद्यालय संस्था की निधियों का निवेश करना और समविश्वविद्यालय संस्था को सौंपी गई निधियों का ठीक समझे गए प्रतिभूतियों में निवेश करना और समय-समय पर किसी निवेश को बंद करना;
- xxv) प्रत्येक पिछले वित्तीय वर्ष के लिए विनियम/उप नियम द्वारा निर्धारित तरीके से तुलन पत्र सहित समुचित लेखे और अन्य संगत रिकार्ड रखना और वार्षिक लेखा विवरण तैयार करना;
- xxvi) समविश्वविद्यालय संस्था के राजस्व, वित्त, लेखों, निवेश, संपत्तियों, कार्यों और सभी अन्य प्रशासनिक मामलों को प्रबंधन करना, विनियमित करना और उन्हें लागू करना तथा इस उद्देश्य के लिए आवश्यक समझे गए एजेंट अथवा एजेंटों को नियुक्त करना;
- xxvii) समविश्वविद्यालय संस्था के कार्य करने के लिए आवश्यक भवन, परिसर, फर्नीचर, फिटिंग, उपकरण और अन्य सुविधाओं को प्रदान करना;

- xxviii) समविश्वविद्यालय संस्था के संकाय सदस्यों और कर्मचारियों के लिए आवास बनाना और प्रबंधन करना तथा छात्रों के लिए छात्रावास बनाना और प्रबंधन करना;
- xxix) समविश्वविद्यालय संस्था के छात्रों के लिए अन्य एजेंसियों द्वारा बनाए गए और प्रबंधित छात्रावासों, को मान्यता प्रदान करना और उनका नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण करना और ऐसी मान्यता को रद्द करना;
- xxx) प्रबंध बोर्ड द्वारा उचित समझे गए उद्देश्यों के लिए और अधिकारों के साथ ऐसी समितियों की नियुक्ति करना और इन समितियों में ऐसे व्यक्तियों को शामिल करना जो आवश्यक समझे जाएं;
- xxxi) समविश्वविद्यालय संस्था के किसी इंस्ट्रूमेंट अथवा कार्य के उद्देश्य से किसी व्यक्ति की ऐसी शक्तियों के साथ जो आवश्यक समझी जाएं समविश्वविद्यालय संस्था का अग्रणी नियुक्त करना;
- xxxii) अगले वर्ष के लिए लेखा परीक्षक की नियुक्ति करना;
- xxxiii) समविश्वविद्यालय संस्था का चिन्ह का चयन करना और समान मुहर का चयन करना और ऐसी मुहर को रखने और उसके उपयोग का प्रावधान करना;
- xxxiv) किसी समिति अथवा उसके द्वारा गठित उप समिति अथवा समविश्वविद्यालय संस्था के कुलपति अथवा किसी अन्य व्यक्ति को अपना कोई भी अधिकार प्रदान करना;
- xxxv) समविश्वविद्यालय संस्था के सभी प्रशासनिक मामलों को जिनका अभिन्न रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, का संचालन करना;
- xxxvi) समविश्वविद्यालय संस्था के कार्यों को उचित और सक्षम रूप से संचालित करने के लिए सभी आवश्यक निर्णय लेना;

4.5 प्रबंध बोर्ड की बैठकें

- (i) प्रबंध बोर्ड की वर्ष में कम से कम चार बार बैठकें होंगी। प्रबंध बोर्ड की बैठक के लिए कम से कम 15 दिन का समय दिया जाएगा। प्रबंध बोर्ड की बैठक के लिए कोरम आठ (8) सदस्यों का होगा।
- (ii) प्रबंध बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा और उनकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने बीच से चुने गए किसी सदस्य द्वारा की जाएगी।
- (iii) अध्यक्ष सहित प्रबंध बोर्ड के प्रत्येक सदस्य का एक वोट होगा और बोर्ड की बैठकों में निर्णय साधारण बहुमत से लिया जाएगा। समान वोट होने पर अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा।
- (iv) प्रबंध बोर्ड के लिए आवश्यक कोई कार्य इसके सदस्यों के बीच समुचित संकल्प पत्र का परिचालन करके किया जाएगा और इस प्रकार परिचालित तथा साधारण बहुमत से अनुमोदित कोई संकल्प पत्र इस प्रकार प्रभावी और अनिवार्य होगा जैसा कि उस संकल्प को बोर्ड की बैठक में पारित किया गया हो।
- (v) प्रत्येक बैठक की कार्यवाही की एक प्रति बैठक के पश्चात शीघ्रातिशीघ्र समविश्वविद्यालय संस्था के कुलाधिपति को प्रस्तुत की जाएगी।

4.6 सदस्यता को समाप्त करना

यदि कुलपति के अलावा तथा अध्यापकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों के अलावा कोई सदस्य समविश्वविद्यालय संस्था ने पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार करता है और प्रबंध बोर्ड की लगातार तीन बैठकों में पूर्व अनुपस्थिति अवकाश के बगैर अनुपस्थित रहता है तो वह प्रबंध बोर्ड का सदस्य नहीं रहेगा।

4.7 प्रबंध बोर्ड द्वारा स्थायी समिति और तदर्थ समिति का गठन

- 4.7.1 समविश्वविद्यालय संस्था के नियमों के प्रावधानों के अधीन प्रबंध बोर्ड एक संकल्प पत्र द्वारा ऐसे उद्देश्यों के लिए और उन अधिकारों के साथ जो वह

समविश्वविद्यालय संस्था के किसी कार्य को पूरा करने में आवश्यक समझे अथवा समविश्वविद्यालय संस्था के किसी मामले में जांच करके, रिपोर्ट करने, सलाह देने के लिए ऐसी स्थायी समिति अथवा तदर्थ समिति अथवा समितियों का गठन कर सकता है।

4.7.2 प्रबंध बोर्ड स्थायी समिति अथवा तदर्थ समितियों में ऐसे व्यक्तियों को ले सकता है जिन्हें वह उचित समझे।

4.8 प्रबंधन बोर्ड के अधिकारों को सौंपना

प्रबंध बोर्ड एक संकल्प पत्र द्वारा स्थायी समिति अथवा तदर्थ समिति के समविश्वविद्यालय संस्था के कुलपति अथवा किसी अन्य अधिकारी को इस शर्त के साथ आवश्यक समझे गए अधिकार सौंप सकता है कि इस प्रकार सौंपे गए अधिकारों में कुलपति अथवा संबद्ध अधिकारी अथवा स्थायी समिति अथवा तदर्थ समिति द्वारा किए गए कार्य प्रबंध बोर्ड की अगली बैठक में सूचित किए जावेंगे।

अनुबंध-2**समविश्वविद्यालय संस्था के अन्य प्राधिकरण**

समविश्वविद्यालय संस्था के अन्य प्राधिकरण निम्नलिखित होंगे:

1. शैक्षिक परिषद्
2. आयोजना एवं मानीटरिंग बोर्ड
3. वित्त समिति
4. अध्ययन बोर्ड
5. ऐसे अन्य प्राधिकरण जिन्हें समविश्वविद्यालय संस्था के प्राधिकारियों द्वारा नियमों के अनुसार घोषित किया जाए।

1. **शैक्षिक परिषद्**

- 1.1 शैक्षिक परिषद् समविश्वविद्यालय संस्था का मुख्य शैक्षिक निकाय होगा और नियमों के प्रावधानों के अधीन उसके पास शिक्षण, शोध, प्रशिक्षण, पाठ्यक्रमों का अनुमोदन, अनुसंधान गतिविधियों को समन्वय, समविश्वविद्यालय संस्था के भीतर परीक्षा का नियंत्रण और जिम्मेदारी होगी और वह संस्था के नियमों द्वारा निर्धारित अथवा प्रदत्त ऐसे अधिकारों का प्रयोग करेगा और ऐसे कार्यों को करेगा जो कि आवश्यक समझे गए हों।

1.2 **शैक्षिक परिषद् का गठन**

शैक्षिक परिषद् में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे, नामतः:

1. कुलपति अध्यक्ष
2. समकुलपति (यदि कोई हो)
3. संकाय के डीन

4. विभागों के प्रमुख
5. विभागों के प्रमुखों से इतर दस प्रोफेसर (वरिष्ठता के रोटेशन द्वारा)
6. विभागों के प्रमुखों से इतर विभागों से तीन एसोसिएट प्रोफेसर, वरिष्ठता के रोटेशन द्वारा
7. वरिष्ठता के रोटेशन द्वारा विभागों से तीन सहायक प्रोफेसर
8. सम्मानित शिक्षाविदों अथवा समविश्वविद्यालय संस्था की गतिविधियों से संबद्ध अन्य क्षेत्रों से तीन व्यक्ति जो समविश्वविद्यालय संस्था की सेवा में नहीं हों, कुलपति द्वारा नामित
9. शैक्षिक परिषद् द्वारा उनके विशिष्ट ज्ञान के लिए तीन व्यक्ति जो शिक्षण स्टाफ के सदस्य नहीं हों
10. रजिस्ट्रार, जो शैक्षिक परिषद् का सचिव होगा।

टिप्पणी: विभिन्न श्रेणियों के लिए अभ्यावेदन केवल रोटेशन द्वारा होंगे और चयन द्वारा नहीं। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कोई विशिष्ट संकाय सदस्य परिषद् की सदस्यता में हावी न हो।

1.3 सदस्यता की अवधि

पदेन सदस्यों के अलावा सदस्यों की अवधि दो वर्ष की होगी।

1.4 शैक्षिक परिषद् के अधिकार और कार्य

शैक्षिक परिषद् के निम्नलिखित अधिकार और कर्तव्य होंगे, नामतः:

- i. स्वयं अथवा प्रबंध बोर्ड के अनुरोध पर अथवा विभागों/संकाय सदस्यों द्वारा प्रस्तावित शैक्षिक हित के मामलों पर विचार करना और उन पर उचित कार्रवाई करना;
- ii. समविश्वविद्यालय संस्था के शैक्षिक कार्यों का सामान्य पर्यवेक्षण करना तथा शिक्षा के माध्यम, मूल्यांकन और शैक्षिक मानकों में सुधार के संबंध में निर्देश देना;

- iii. समविश्वविद्यालय संस्था के भीतर अनुसंधान का संवर्धन करना, समय-समय पर ऐसे शोधकर्ताओं के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त करना;
- iv. समविश्वविद्यालय संस्था की डिग्री और डिप्लोमा के लिए अध्ययन पाठ्यक्रम निर्धारित करना;
- v. उप नियमों के अनुरूप परीक्षा के संचालन हेतु प्रबंध करना;
- vii. परीक्षाओं के उचित मानकों का अनुरक्षण करना;
- viii. विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थाओं के डिप्लोमा और डिग्री को मान्यता प्रदान करना और समविश्वविद्यालय संस्था के डिप्लोमा और डिग्री का समकक्ष निर्धारित करना;
- ix. विभागीय सहयोग के लिए उपाय सुझाना;
- x. निम्नलिखित के संबंध में प्रबंध बोर्ड की सिफारिशें देना:
 - क) शोध और प्रशिक्षण के अध्ययन के मानकों के सुधार हेतु उपाय;
 - ख) फेलोशिप, ट्रेवलिंग फेलोशिप, छात्रवृत्ति, मेडल, पुरस्कार इत्यादि का गठन;
 - ग) प्रबंध बोर्ड को विभागों/केन्द्रों की स्थापना अथवा उन्हें बंद करने की सिफारिश करना; और
 - घ) समविश्वविद्यालय संस्था के शैक्षिक कार्यों, प्रवेश, परीक्षा, फेलोशिप और छात्रवृत्ति, फ्रीशिप प्रदान करना, छूट, उपस्थिति, अनुशासन, आवास इत्यादि को शामिल करते हुए नियम बनाना;

- xi. प्रबंध बोर्ड द्वारा उल्लिखित विशिष्ट मामलों पर सलाह देने के लिए उप समितियों की नियुक्ति करना;
- xii. उप समितियों की सिफारिशों पर विचार करना और प्रत्येक मामले में आवश्यक कार्रवाई करना;
- xiii. विभागों/केन्द्रों की गतिविधियों की आवधिक समीक्षा करना और निदेश के मानकों को बनाए रखने और उनमें सुधार करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करना;
- xiv. प्रबंध बोर्ड को शिक्षण पदों (प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर) के गठन की सिफारिश करना; और
- xv. नियमों द्वारा प्रदत्त ऐसे अन्य अधिकार और कार्य करना।

1.5 शैक्षिक परिषद् की बैठक

- i. शैक्षिक परिषद् की बैठक शैक्षिक वर्ष में जितनी बार आवश्यक समझा जाए अथवा न्यूनतम तीन बार आयोजित की जाएगी। शैक्षिक परिषद् की बैठक के लिए न्यूनतम 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा।
- ii. शैक्षिक परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई शैक्षिक परिषद् की बैठक के लिए क्वोरम होगा।
- iii. अध्यक्ष सहित प्रत्येक सदस्य का एक वोट होगा और शैक्षिक परिषद् की बैठक में साधारण बहुमत से निर्णय लिया जाएगा। बराबर मत होने पर अध्यक्ष का वोट निर्णायक होगा।
- iv. शैक्षिक परिषद् के लिए इसकी बैठक से पहले रखे गए कार्य को छोड़कर, कोई भी आवश्यक समझा गया कार्य इसके सदस्यों के बीच संकल्प पत्र के परिचालन द्वारा किया जाएगा और इस प्रकार परिचालित तथा सामान्य बहुमत से अनुमोदित संकल्प इस

प्रकार प्रभावी और अनिवार्य होगा जैसा कि शैक्षिक परिषद् की बैठक में पारित किया गया हो, बशर्ते कि शैक्षिक परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या का कम से कम आधे सदस्यों ने संकल्प पर अपने विचार रिकार्ड करवाए हों।

2.0 आयोजना और मानीटरिंग बोर्ड

2.1 आयोजना और मानीटरिंग बोर्ड समविश्वविद्यालय संस्था का प्रमुख आयोजना निकाय होगा और वह समविश्वविद्यालय संस्था के विकास कार्यक्रमों की मानीटरिंग के लिए जिम्मेदार होगा।

2.2 आयोजना और मानीटरिंग बोर्ड के अध्यक्ष कुलपति होंगे। रजिस्ट्रार इसके सचिव होंगे। इसके यूजीसी के एक नामिति सहित सात आंतरिक सदस्य तथा तीन बाह्य प्रबुद्ध विशेषज्ञ हो सकते हैं।

2.3 आयोजना एवं मानीटरिंग बोर्ड का गठन, अधिकार और कार्य नियमों द्वारा निर्धारित किए जायेंगे।

2.4 आयोजना और मानीटरिंग बोर्ड को समविश्वविद्यालय संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक समझे गए किसी मामले पर प्रबंध बोर्ड तथा शैक्षिक परिषद् को सलाह देने का अधिकार होगा।

2.5 आयोजना एवं मानीटरिंग बोर्ड की सिफारिशों को प्रबंध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ तथा अनुमोदनार्थ रखा जाएगा। शैक्षिक मामलों से संबद्ध प्रस्तावों को शैक्षिक परिषद् के माध्यम से हल किया जा सकता है।

3.0 वित्त समिति

3.1 वित्त समिति का गठन:

वित्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे

1. कुलपति -अध्यक्ष
2. समकुलपति

3. समिति अथवा व्याप्त द्वारा नामित एक सदस्य
4. प्रबंध बोर्ड के दो नामित, जिनमें से एक बोर्ड का सदस्य होगा।
5. केन्द्र सरकार का एक प्रतिनिधि
6. यदि समविश्वविद्यालय संस्था राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त कर रही है तो राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि
7. वित्तीय अधिकारी-सचिव

3.2 वित्त समिति का कार्यकाल

पदेन सदस्यों को छोड़कर वित्त समिति के सभी सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए कार्य करेंगे।

3.3 वित्त समिति के अधिकार और कार्य:

- (i) समविश्वविद्यालय संस्था के वार्षिक लेखों तथा वित्तीय अनुमानों पर विचार करना और उन्हें प्रबंध बोर्ड को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करना;
- (ii) प्रबंध बोर्ड के वार्षिक बजट और संशोधित अनुमानों पर विचार करना तथा सिफारिश करना;
- (iii) समविश्वविद्यालय संस्था की आय और स्रोतों के आधार पर वर्ष के कुल आर्वात तथा कुल अनावर्त व्यय की सीमा निर्धारित करना;

टिप्पणी: बजट में प्रवर्त व्यय के अतिरिक्त समविश्वविद्यालय संस्था द्वारा वित्त समिति के अनुमोदन के बगैर कोई व्यय नहीं किया जाएगा।

3.5 वित्त समिति की बैठकें

वित्त समिति की लेखों की जांच करने और व्यय के लिए प्रस्तावों की जांच करने हेतु एक वर्ष में कम से कम दो बार बैठक होगी। बैठक के लिए पांच सदस्यों का कोरम होगा।

4.0 अध्ययन बोर्ड

4.1 समविश्वविद्यालय संस्था के प्रत्येक विभाग के लिए एक अध्ययन बोर्ड होगा।

4.2 प्रत्येक संकाय/विभाग के अध्ययन बोर्ड में निम्नलिखित शामिल होंगे:

1. संकाय के डीन/विभाग प्रमुख - अध्यक्ष
2. संकाय/विभाग के सभी प्रोफेसर
3. वरिष्ठता के रेटेशन द्वारा संकाय/विभाग के दो एसोसिएट प्रोफेसर
4. वरिष्ठता के रेटेशन द्वारा संकाय/विभाग के दो सहायक प्रोफेसर
5. संबद्ध व्यवसाय अथवा उद्योग से संबंध रखने वालों सहित विशेषज्ञ विद्वानों को शामिल करते हुए अधिकतम दो व्यक्ति

4.3 अध्ययन बोर्ड के अधिकार और कार्य समविश्वविद्यालय संस्था के नियमों द्वारा निर्धारित किए जायेंगे।

5.0 चयन समिति

5.1 प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर और समविश्वविद्यालय संस्था में नियमों द्वारा निर्धारित अन्य पदों पर नियुक्ति के लिए प्रबंध बोर्ड को सिफारिश करने हेतु एक चयन समिति होगी।

5.2 प्रत्येक चयन समिति का गठन प्रबंध बोर्ड द्वारा तैयार किए गए नियमों के अनुरूप किया जाएगा।

5.3 चयन समिति की बैठकें

- (क) चयन समिति की बैठकें चयन समिति के अध्यक्ष द्वारा जब भी आवश्यक समझा जाए आयोजित की जाएगी।
- (ख) चयन समिति के चार सदस्यों में कम से कम दो विशेषज्ञ कोरम होंगे।
- (ग) यदि प्रबंध बोर्ड चयन समिति की सिफारिशों को स्वीकार नहीं कर पाता है तो वह इसके कारण रिकार्ड करेगा और उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा उचित समीक्षा की आवश्यकता होगी।

6.0 समविश्वविद्यालय संस्था के अधिकारी

समविश्वविद्यालय संस्था के निम्नलिखित अधिकारी होंगे:

- (क) कुलाधिपति
- (ख) कुलपति
- (ग) समकुलपति
- (घ) रजिस्ट्रार
- (ङ.) वित्त अधिकारी
- (च) परीक्षा नियंत्रक
- (छ) संकाय का डीन
- (ज) विभाग प्रमुख
- (झ) समविश्वविद्यालय संस्था के नियमों में निर्धारित अन्य अधिकारी

6.1 कुलाधिपति

समविश्वविद्यालय संस्था में एक कुलाधिपति होगा जो उपस्थित होने पर समविश्वविद्यालय संस्था के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा परंतु वह प्रधान कार्यकारी अधिकारी नहीं होगा। कुलाधिपति की नियुक्ति प्रायोजक सोसायटी अथवा ट्रस्ट के द्वारा की जाएगी और वह

पाच वर्ष की अवधि के लिए कार्य करेगा तथा एक और टर्म के लिए पात्र होगा। कुलाधिपति न तो सोसायटी के या न्यास के सदस्य होंगे और न ही सोसायटी या न्यास के अध्यक्ष के निकटवर्ती संबंधी होंगे।

जहां भी कुलाधिपति को प्राधिकरणों में व्यक्ति नामित करने का अधिकार दिया जाएगा वह जहां तक आवश्यक हो समविश्वविद्यालय संस्थाओं के लक्ष्यों की प्रोन्नति हेतु विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए व्यक्तियों को नामित करेगा।

6.2 कुलपति

(i) कुलपति समविश्वविद्यालय संस्थाओं के पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होंगे तथा उनकी नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा जांच एवं चयन समिति द्वारा सुझाए गए तीन नामों के पैनल में से की जाएगी। जांच एवं चयन समिति का गठन निम्नलिखित अनुसार होगा:-

1. कुलाधिपति का नामित व्यक्ति
2. केन्द्र सरकार का नामित व्यक्ति; जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचार-विमर्श से सरकार द्वारा नामित लब्धप्रसिद्ध शिक्षाविद् होंगे।
3. प्रबंधन बोर्ड का एक नामित व्यक्ति

(ii) कुलपति की अवधि 5 वर्षों की होगी। वे दूसरी अवधि के लिए पात्र होंगे बशर्ते कि वे 70 वर्ष से अधिक के न हों।

बशर्ते कि 5 वर्षों की अवधि समाप्त होने के बावजूद वे छः महीने तक या उनके उत्तरवर्ती की नियुक्ति होने तथा उनके कार्यभार संभालने तक, जो भी पहले हो कार्यालय में रह सकते हैं।

(iii) यदि कुलपति का पद, मृत्यु, त्यागपत्र देने या किसी अन्य कारण से तथा उनकी बीमारी के कारण तथा किसी अन्य कारण रिक्त पड़ा रहता है तो उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम डीन या,

यदि कोई छीन नहीं है तो वरिष्ठतम प्रोफेसर नए कुलपति की नियुक्ति होने तक या वर्तमान कुलपति के कार्यभार संभालने तक, जैसा भी मामला हो, कुलपति का कार्यभार संभालेंगे।

6.3

कुलपति के अधिकार

- i) कुलपति समविश्वविद्यालय संस्थाओं के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे तथा वह समविश्वविद्यालय संस्था का सामान्य निरीक्षण करेंगे और उसके कार्यकलापों की देखभाल करेंगे तथा मुख्यतः सभी समविश्वविद्यालय संस्थाओं के निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे।
- ii) कुलपति, प्रबंधन बोर्ड, शैक्षिक परिषद, वित्त समिति, आवासना एवं अनुवीक्षण बोर्ड तथा चयन समितियों के पदेन अध्यक्ष होंगे।
- iii) कुलपति को समविश्वविद्यालय संस्था के विभिन्न प्राधिकरणों की बैठकें आयोजित करने का अधिकार होगा।
- iv) यदि कुलपति का मत है कि किसी भी मामले पर स्वीच कार्रवाई की जानी चाहिए तो वह समविश्वविद्यालय संस्था के विभिन्नता एवं नियमों के अंतर्गत इसके किसी भी प्राधिकरण को प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर सकेगा तथा ऐसी कार्रवाई कर सकता है या इस प्रकार की कार्रवाई करने का उपक्रम कर सकता है अथवा इस प्रकार के मामलों में उसके द्वारा की गई कार्रवाई पर संबंधित प्राधिकारी को रिपोर्ट कर सकता है।

वस्तुतः कि ऊपर खंड (ii) में उल्लिखित संबंधित प्राधिकारी का विचार है कि इस प्रकार की कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए तो वह मामला कुलपति को प्रस्तुत कर सकता है जिसका निर्णय अंतिम होगा।

वस्तुतः कि समविश्वविद्यालय संस्था में सेवारत कोई भी व्यक्ति उपर्युक्त खंड के अंतर्गत कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई से

असंतुष्ट है तो उसे ऐसे निर्णय के विरुद्ध इस प्रकार की कार्रवाई के बारे में सूचित की जाने वाली तिथि से 30 दिन के अंदर प्रबंधन बोर्ड के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा तथा उसके पश्चात प्रबंधन बोर्ड तदंतर बैठक आयोजित कर सकता है और कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई की पुष्टि कर सकता है, संशोधन कर सकता है या उसे वापस ले सकता है।

- v) यह सुनिश्चित करना कुलपति का कर्तव्य होगा कि समविश्वविद्यालय संस्था के विनियमों तथा नियमों का यथावत अनुपालन एवं कार्यान्वयन हों; तथा इस संबंध में उसके समक्ष सभी आवश्यक अधिकार होंगे।
- vi) समविश्वविद्यालय संस्था के उचित अनुरक्षण एवं अनुशासन से संबंधित सभी अधिकार कुलपति को प्रदत्त होंगे।
- vii) कुलपति को, प्रबंधन बोर्ड की सहमति और अनुमति से अपने किसी भी सहायक अधिकारियों को अपने कुछ अधिकार पुनः प्रत्यायुक्त करने का अधिकार होगा।
- viii) कुलपति को प्रबंधन बोर्ड द्वारा प्रदत्त सभी अन्य अधिकारों को प्रयोग करने का अधिकार होगा।
- ix) कुलपति विनियमों, नियमों तथा उपविधियों द्वारा यथा प्रस्तावित सभी अन्य अधिकारों का प्रयोग कर सकेंगे तथा ऐसे अन्य कार्य कर सकेंगे।

6.4 समकुलपति

- (i) समकुलपति का पद प्रबंधन बोर्ड और केन्द्र सरकार के अनुमोदन से सृजित किया जाना चाहिए।

- (ii) समकुलपति की नियुक्ति, कुलपति की सिफारिश पर प्रबंधन बोर्ड द्वारा की जाएगी।
- (iii) समकुलपति, कुलपति के कार्यालय के साथ ही कार्य करेंगे तथा कुलपति के निदेशानुसार कार्य करेंगे।
- (iv) समकुलपति के अधिकार और कर्तव्य समविश्वविद्यालय संस्था के नियमों के अनुसार होंगे।

6.5 रजिस्ट्रार

- (i) रजिस्ट्रार समविश्वविद्यालय संस्था के पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होंगे तथा उनकी नियुक्ति चयन समिति की सिफारिशों पर प्रबंधन बोर्ड द्वारा की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:-

1. कुलपति -अध्यक्ष
2. कुलाधिपति द्वारा एक नामित व्यक्ति
3. प्रबंधन बोर्ड का एक नामित व्यक्ति
4. प्रबंधन बोर्ड द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञ जो समविश्वविद्यालय संस्था का कर्मचारी नहीं हो

- (ii) रजिस्ट्रार का पारिश्रमिक, अन्य नियम एवं शर्तें, समविश्वविद्यालय संस्था के नियमों द्वारा वसूलीधारित होंगी।

- (iii) जब रजिस्ट्रार का पद रिक्त पड़ा है या रजिस्ट्रार बीमारी या अन्य कारण से अनुपस्थित है तो रजिस्ट्रार के कर्तव्य और कार्य इस प्रयोजनार्थ कुलपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा किए जायेंगे।

- (iv) रजिस्ट्रार प्रबंधन बोर्ड, शैक्षिक परिषद और योजना एवं अनुवीक्षण बोर्ड के पदेन सचिव होंगे पर इनमें से किसी भी प्राधिकरण के सदस्य नहीं माने जायेंगे।

(v) रजिस्ट्रार सीधे कुलपति के लिए उत्तरदायी होंगे तथा उसके निर्देशाधीन कार्य करेंगे।

(vi) रजिस्ट्रार के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे:-

1. समविश्वविद्यालय संस्था के रिकार्ड और निधियों तथा ऐसी अन्य संपत्ति के परिरक्षक होंगे जिसका अधिकार प्रबंधन बोर्ड ने उन्हें सौंपा है;
2. समविश्वविद्यालय संस्था के प्राधिकरण की ओर से सरकारी पत्राचार करना;
3. समविश्वविद्यालय संस्था के प्राधिकरणों तथा इन प्राधिकरणों द्वारा नियुक्त सभी समितियों और उपसमितियों की बैठकें आयोजित करने हेतु नोटिस जारी करना;
4. समविश्वविद्यालय संस्था के सभी प्राधिकरणों तथा इनमें से किसी भी प्राधिकरण द्वारा नियुक्त सभी समितियों और उप समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त का अनुरक्षण करना;
5. समविश्वविद्यालय संस्था द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिए प्रबंध करना और उनका निरीक्षण;
6. समविश्वविद्यालय संस्था द्वारा या उसके विरुद्ध मुकद्दमे में समविश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करना तथा मुख्तारनामा हस्ताक्षरित करना और अपना पक्ष रखना तथा इस प्रयोजनार्थ अपना प्रतिनिधि नियुक्त करना;
7. समविश्वविद्यालय संस्था की ओर से करार, दस्तावेज हस्ताक्षरित करना तथा रिकार्ड अधिप्रमाणित करना;
8. समविश्वविद्यालय संस्था के भवन, उद्यान, कार्यालय, कैंटीन, कार और अन्य वाहन, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, पढनकक्षों,

उपकरणों एवं अन्य संपत्ति के अभिरक्षण और सुरक्षा के लिए प्रबंध करना;

9. नियमों अनुसार या प्रबंधन बोर्ड या कुलपति द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट सभी अन्य कार्य करना।

6.6 वित्त अधिकारी

- (i) वित्त अधिकारी समविश्वविद्यालय संस्था का पूर्णकालिक चैतनिक अधिकारी होगा तथा इसकी नियुक्ति प्रबंधन बोर्ड द्वारा की जाएगी।
- (ii) वित्त अधिकारी का पारिवर्त्मिक एवं अन्य नियम एवं सेवा शर्तें, समविश्वविद्यालय संस्था के नियमों द्वारा तथा प्रस्तावित अनुसार होगी।
- (iii) वित्त अधिकारी कुलपति के निर्देशाधीन कार्य करना तथा कुलपति के माध्यम से प्रबंधन बोर्ड के लिए उत्तरदायी होगा।
- (iv) वह, वित्त समिति और प्रबंधन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए वार्षिक बजट, अनुमानों एवं लेखा विवरण तैयार करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- (v) वह प्रबंधन बोर्ड के नियंत्रणाधीन समविश्वविद्यालय संस्था की निधियों और निवेशों के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होगा।

6.7 परीक्षा संचालक

- (i) परीक्षा संचालक की नियुक्ति प्रबंधन बोर्ड द्वारा की जाएगी।
- (ii) परीक्षा संचालक का पारिवर्त्मिक एवं अन्य सेवा नियम व शर्तें समविश्वविद्यालय संस्था के नियमों द्वारा यथाविधि निर्दिष्ट होगी।

(iii) परीक्षा संचालक यह सुनिश्चित करेगा कि परीक्षा और मूल्यांकन के संबंध में प्रबंधन बोर्ड, शैक्षिक परिषद तथा कुलपति के सभी विनिर्दिष्ट निर्देशों का अनुपालन किया जाए।

(iv) परीक्षा संचालक प्रबंधन बोर्ड के स्थायी आमंत्रित होंगे।

6.8 डीन

संबद्ध विषयों वाले विभागों को संकायों में समूहबद्ध किया जा सकता है। प्रत्येक संकाय के अध्यक्ष डीन होंगे।

6.9 विभागाध्यक्ष

(i) समविश्वविद्यालय संस्था में प्रत्येक विभाग का एक विभागाध्यक्ष होगा जिसकी नियुक्ति विभाग के प्रोफेसरों में से कुलपति द्वारा की जाएगी।

यदि विभाग में कोई प्रोफेसर नहीं है या विभाग में केवल एक प्रोफेसर है जिसकी विभागाध्यक्ष के रूप में अवधि समाप्त हो रही है तो कुलपति एसोसिएट प्रोफेसर को विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकते हैं।

(ii) विभागाध्यक्ष की अवधि सामान्यतः 3 वर्षों की होगी तथा वह एक और अवधि हेतु पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे परंतु लगातार दो अवधियों के लिए नहीं।

(iii) विभागाध्यक्ष के अधिकार और कार्य समविश्वविद्यालय संस्था के नियमों द्वारा यथानिर्धारित अनुसार होंगे।

7.0 अधिकारों का प्रत्यायोजन

इन विनियमों एवं विनियमों के प्रावधानों के अनुसार समविश्वविद्यालय संस्था को कोई भी प्राधिकारी या अधिकारी प्रबंधन बोर्ड के अनुमोदन से

अपने अधिकार किसी अन्य प्राधिकारी या अधिकारी या उनके नियंत्रणाधीन व्यक्ति को इन शर्तों पर प्रदान कर सकता है कि प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करने का संपूर्ण उत्तरदायित्व उस प्राधिकारी या अधिकारी के संभल रहेगा जो इन्हें प्रदान कर रहा है।

8.0 वरिष्ठता सूची

(क) जब कभी इन नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति कोई कार्यभार संभालता है या वरिष्ठता के चक्रवर्तीनुसार समविश्वविद्यालय संस्था के प्राधिकरण का सदस्य बनता है तो इस प्रकार की वरिष्ठता, प्रबंधन बोर्ड द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित ऐसे अन्य सिद्धांतों अनुसार समविश्वविद्यालय संस्था के ग्रेड में ऐसे व्यक्ति की लगातार सेवा अवधि के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

(ख) ऐसे व्यक्तियों किन पर इन नियमों के प्रावधान लागू होते हैं, के प्रत्येक वर्ग/कांडर के संबंध में पूर्ववर्ती खंड के प्रावधानों अनुसार पूर्ण और अद्यतन वरिष्ठता सूची तैयार करना रजिस्ट्रार का कर्तव्य होगा।

(ग) यदि दो या दो से अधिक व्यक्तियों की एक विशेष ग्रेड/कांडर में लगातार सेवा की समान अवधि है या किसी भी व्यक्ति का व्यक्तियों की प्रासंगिक वरिष्ठता पर संदेह है तो रजिस्ट्रार अपनी इच्छा से या ऐसे किसी व्यक्ति के अनुरोध पर मामला बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है जिसका निर्णय अंतिम और बाध्य होगा।

9.0 सदस्यता के लिए विवाद

यदि ऐसा कोई भी विवाद उठता है कि क्या कोई भी व्यक्ति समविश्वविद्यालय संस्था के किसी प्राधिकरण या किसी समिति के सदस्य के रूप में यथावत नामित या नियुक्त किया गया है या सदस्य के लिए पात्र है तो मामला कुलाधिपति को भेज दिया जाएगा जिसका निर्णय अंतिम और बाध्य होगा।

10.0 शिकायत सुधार तंत्र

व्यक्तिगत शिकायतों के लिए प्रत्येक समविश्वविद्यालय संस्था में नियमों अनुसार यथानिर्धारित शिकायत सुधार तंत्र होगा।

11.0 त्यागपत्र

किसी भी प्राधिकरण के पदेन सदस्य के अतिरिक्त अन्य कोई सदस्य रजिस्ट्रार को संबोधित अपने पत्र द्वारा त्यागपत्र दे सकता है तथा त्यागपत्र उस तिथि से प्रभावी होगा जिस तिथि से कुलाधिपति अथवा प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा यह स्वीकार किया जाता है।

12.0 बैठकों के कार्यवाहक अध्यक्ष

यदि अध्ययन हेतु ऐसा कोई प्रावधान नहीं रखा गया है कि वह समविश्वविद्यालय संस्था के किसी प्राधिकरण या इस प्रकार के प्राधिकरण की किसी समिति की बैठक की अध्यक्षता करे अथवा इस प्रावधान के बावजूद अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उपस्थित सदस्य बैठक की अध्यक्षता हेतु अपने में से किसी एक का चयन कर सकते हैं।

13.0 कुछ कार्रवाईयों, निर्णयों की वैधता

समविश्वविद्यालय संस्था के किसी भी प्राधिकरण या किसी भी व्यक्ति या किसी भी समिति की कोई भी कार्रवाई या कार्यवाही किसी भी रिक्ति के कारण अमान्य नहीं होगी।

14.0 अयोग्य

(क) ऐसा कोई भी सदस्य, समविश्वविद्यालय संस्था के किसी भी प्राधिकरण के सदस्य के रूप में चयन हेतु और या सदस्य, अयोग्य होगा यदि:

i) यदि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है

ii) यदि वह अभ्यर्गुक्त दिवालिया है

iii) यदि उसे नैतिक रूप से भ्रष्टाचार के अपराध में न्यायालय द्वारा सजा दी गई है।

(ख) यदि यह विवाद उठता है कि व्यक्ति उपरोक्तलिखित अयोग्यताओं के अंतर्गत आता है तो इस विवाद को कुलाधिपति के निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

15.0 आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना

विश्वविद्यालय संस्था के किसी प्राधिकरण अथवा किसी समिति के सदस्यों (पदेन सदस्यों को छोड़कर) के बीच होने वाली आकस्मिक रिक्तियों को सुविधा के अनुसार ऐसे प्राधिकरण अथवा व्यक्ति द्वारा भरा जाएगा जिसने उस सदस्य को नियुक्त अथवा सहयोजित किया था जिसका स्थान रिक्त हुआ है और एक आकस्मिक रिक्ति पर नियुक्त अथवा सहयोजित व्यक्ति उस शेष कार्यकाल के लिए उस प्राधिकरण अथवा समिति का सदस्य होगा जिसके लिए वह व्यक्ति सदस्य होता जिसके स्थान पर उसकी नियुक्ति हुई है।

16.0 समविश्वविद्यालय संस्था के शैक्षिक कार्यक्रमों की समीक्षा

समविश्वविद्यालय संस्था के कार्यक्रमों की समीक्षा आयोग द्वारा नियुक्त समिति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में की जाएगी, यदि आवश्यक हो, इससे पहले की जाएगी।

17.0 आयोग द्वारा समविश्वविद्यालय संस्था का निरीक्षण

i) आयोग, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जिन्हें वह निदेश देता है, समविश्वविद्यालय संस्था इसके भवन, उपस्कर, प्रयोगशालाओं तथा उपकरण तथा परीक्षाओं, अध्यापन और किए गए अन्य कार्य का निरीक्षण कर सकता है तथा यदि आवश्यक हो तो समविश्वविद्यालय संस्था के प्रशासन या वित्त से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में जांच कर सकता है।

- ii) आयोग प्रत्येक मामले में समविश्वविद्यालय संस्था को किए जाने वाले निरीक्षण या जांच के लिए नोटिस देगा तथा नोटिस प्राप्त होने पर समविश्वविद्यालय संस्थाओं को, जैसा आवश्यक समझे, आयोग को अभ्यावेदन देने का अधिकार होगा।
- iii) जहां कहीं भी आयोग द्वारा निरीक्षण या जांच की जानी है वहां समविश्वविद्यालय संस्था अपना प्रतिनिधि नियुक्त करने की पात्र होगी जिसे इस प्रकार के निरीक्षण या जांच में उपस्थित रहने तथा सुनवाई का अधिकार होगा।
- iv) आयोग, समविश्वविद्यालय संस्था द्वारा की जाने वाली कार्रवाई पर अपने परामर्श के साथ इस प्रकार के निरीक्षण या जांच के परिणाम से कुलपति को अवगत करा सकता है, जो इसे प्रबंधन बोर्ड को प्रस्तुत कर देगे।
- v) प्रबंधन बोर्ड, निरीक्षण या जांच के संबंध में तथा समविश्वविद्यालय संस्था द्वारा की जाने वाली कार्रवाई हेतु प्रस्तावों पर उपयुक्त रूप से विचार करेगा तथा यदि कोई कार्रवाई करने का प्रस्ताव या इस प्रकार के निरीक्षण या जांच पर कोई कार्रवाई की गई है तो उसके बारे में आयोग को सूचित करेगा।
- vi) यदि प्रबंधन बोर्ड उचित समय में आयोग की संतुष्टि अनुसार कोई कार्रवाई नहीं करता तो आयोग प्रबंधन बोर्ड द्वारा दिए गए अभ्यावेदन या प्रस्तुत स्पष्टीकरण पर विचार करके यथोचित निर्देश जारी कर सकता है तथा प्रबंधन बोर्ड ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगा।

18.0 समविश्वविद्यालय संस्था की आय और संपत्ति का केवल इसके प्रयोजनार्थ उपयोग किया जाना चाहिए

समविश्वविद्यालय संस्था की आय और संपत्ति का प्रयोग पूर्णतः समविश्वविद्यालय संस्था के लक्ष्यों को प्रोन्नत करने के लिए किया जाना चाहिए।

19.0 लाभ के रूप में समविश्वविद्यालय संस्था की आय और संपत्ति के भुगतान या हस्तांतरण पर रोक

समविश्वविद्यालय संस्था की आय या संपत्ति का कोई भाग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, डिविडेंड, बोनस या लाभ के रूप में अन्य किसी प्रकार से उन व्यक्तियों को जो किसी भी समय समविश्वविद्यालय संस्था के सदस्य थे/या हैं, उनमें से किसी भी व्यक्ति को या उनके माध्यम से दावा किए जाने वाले व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा बशर्ते कि इनमें दिए गए कोई भी कारण उसके किसी भी सदस्य या ऐसे व्यक्ति के द्वारा समविश्वविद्यालय संस्था के लिए की गई कोई भी सेवा या यात्रा हेतु या अन्य भत्तों तथा अन्य प्रभारों के भुगतान को रोक नहीं सकते।

20.0 निधियां, लेखे, लेखापरीक्षा एवं वार्षिक रिपोर्ट

- i) समविश्वविद्यालय संस्था के लेखे, समविश्वविद्यालय संस्था के नाम से अनुरक्षित किए जायेंगे न कि उस प्रायोजक सोसायटी या न्यास के नाम में। संस्था के लेखे प्रबंधन बोर्ड द्वारा यथानिर्धारित अनुसार रखे जायेंगे तथा आयोग द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप होंगे। संस्था के लेखे आयोग द्वारा जांच के लिए खुले रहेंगे।
- ii) वार्षिक वित्तीय विवरण और लेखों की समविश्वविद्यालय संस्था के सनदी लेखाकार द्वारा लेखापरीक्षा की जाएगी।
- iii) समविश्वविद्यालय संस्था वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षित रिपोर्ट वित्त वर्ष की समाप्ति के नौ महीने के अंदर आयोग को प्रस्तुत करेगी।

21.0 समविश्वविद्यालय संस्था के नियम

आयोग के विनियमों और नियमों के प्रावधानों के अतिरिक्त प्रबंधन बोर्ड के समक्ष अन्य प्रदत्त अधिकारों के अतिरिक्त समविश्वविद्यालय संस्था की ऐसी नियमावली प्रारूपित करने का अधिकार होगा जिनमें निम्नलिखित सभी या किसी एक के लिए प्रावधान होगा:-

- (i) अध्यापन विभागों की स्थापना;
- (ii) समविश्वविद्यालय संस्था की सभी डिग्रियों, डिप्लोमा और प्रमाणपत्रों हेतु निर्धारित अध्ययन पाठ्यक्रम;
- (iii) शैक्षिक पुरस्कार (जैसे डिग्री और डिप्लोमा) और पदक प्रदान करना;
- (iv) समविश्वविद्यालय संस्था में छात्रों का दाखिला और उनका नामांकन;
- (v) अध्ययन पाठ्यक्रमों हेतु तथा समविश्वविद्यालय संस्था की परीक्षाओं, डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण पत्रों में दाखिले के लिए, लिए जाने वाले शुल्क;
- (vi) परीक्षाओं का आयोजन, परीक्षकों की नियुक्ति और उनके परिणामों का अनुमोदन और प्रकाशन;
- (vii) फैलोशिप, छात्रवृत्ति, स्टूडेंटशिप, मेडल और पुरस्कार प्रदान करना निर्धारित करना और उनके लिए शर्तें प्रस्तावित करना;
- (viii) छात्रों के बीच अनुशासन बनाए रखना;
- (ix) कर्मचारियों के बीच अनुशासन बनाए रखना;
- (x) आवासीय हॉलों की स्थापना तथा आवास की शर्तें और छात्रों का स्वास्थ्य;
- (xi) वर्गीकरण, उपलब्धियां, नियुक्ति की प्रणाली और स्टाफ की सेवा शर्तों और नियमों का निर्धारण;
- (xii) शैक्षिक परिषद् के ऐसे सभी अन्य अधिकार कर्ष और कर्तव्य जिनका कहीं अन्य उल्लेख नहीं है;

- (xiii) अध्ययन और अनुवीक्षण बोर्ड का गठन अधिकार और कार्य;
- (xiv) अध्ययन बोर्ड के अधिकार और कार्य;
- (xv) शिक्षण सुधार तंत्र का गठन, अधिकार और कार्य;
- (xvi) समविश्वविद्यालय संस्था के ऐसे अन्य अधिकारियों के रूप में व्यक्ति प्रस्तावित करना;
- (xvii) कुलपति के ऐसे सभी अन्य अधिकार और कार्य जिसका अन्य कहीं उल्लेख नहीं;
- (xviii) रजिस्ट्रार का पारिश्रमिक, सेवा के नियम एवं शर्तें;
- (xix) वित्त अधिकारी का पारिश्रमिक, सेवा के नियम एवं शर्तें;
- (xx) अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य स्टाफ के लाभ के लिए पेंशन, भविष्यनिधि, बीमा आदि का गठन;
- (xxi) विशेष केन्द्रों की स्थापना;
- (xxii) ऐसी अन्य समितियों या निकाय का सृजन, गठन और कार्य जिन्हें समविश्वविद्यालय संस्था के कार्य हेतु आवश्यक समझा जाता है;
- (xxiii) बजट अनुमान तैयार करने और प्रस्तुत करने की प्रक्रिया;
- (xxiv) किसी प्राधिकरण या समिति की बैठक आयोजित करने की प्रक्रिया;
- (xxv) किसी भी प्राधिकरण या समिति की बैठक में अनुपालन किए जाने वाले प्रक्रियाओं का निर्धारण;

(xxvi) समविश्वविद्यालय संस्था के प्राधिकरण के रूप में किसी अन्य निकाय का गठन;

(xxvii) किसी भी प्राधिकारी या अधिकारी को अधिकारों का प्रत्यायोजन;

(xxviii) अन्य सभी मामले इस विनियम या नियम में शामिल किए जाने चाहिए परंतु किसी भी नियम का शैक्षिक परिषद् से चर्चा किए बिना आवास, स्वास्थ्य, अनुशासन, दाखिला, छात्रों का नामांकन, शर्तें, नियुक्ति के माध्यम, परीक्षकों के कर्तव्य, परीक्षाओं या किसी अन्य अध्ययन पाठ्यक्रमों के स्तरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

22.0 प्रतिपादित खंड

आयोग के विनियम या नियमों के प्रतिपादन के संबंध में विचारों में मतभेद होने पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

23.0 समविश्वविद्यालय संस्था के विघटन पर आय और संपत्ति का समायोजन समविश्वविद्यालय संस्था के विघटन या समाप्त होने पर इसके सभी ऋण और दायित्वों की आपूर्ति करने के पश्चात इसकी कोई भी संपत्ति समविश्वविद्यालय संस्था के किसी सदस्य को दी या वितरित नहीं की जाएगी परंतु उन संबंधित एजेंसियों के साथ जिन्होंने इस संपत्ति के सृजन में सहायता की है, चर्चा करके आयोग या अन्य निकायों को स्थानांतरित की जाएगी।

24.0 विधि प्रक्रियाएं

- i) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 की धारा के प्रयोजनार्थ वह व्यक्ति जिसके नाम समविश्वविद्यालय संस्था का मुकद्मा कर सकती है या किया जाएगा, संस्था का रजिस्ट्रार होगा।
- ii) इन नियमों के अनुसरण में की गई कोई भी या की जाने वाली कोई भी कार्यवाई के संबंध में केन्द्र सरकार या आयोग या समविश्वविद्यालय संस्था या समविश्वविद्यालय संस्था के किसी भी अधिकारी या समविश्वविद्यालय संस्था के प्राधिकरण के किसी सदस्य के विरुद्ध कोई मुकद्मा या कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी।

25.0 समविश्वविद्यालय संस्था के कार्यकरण को प्रशासित करने वाले नियमों में आशोधन, संशोधन और संयोजन

समविश्वविद्यालय संस्था के कार्यकरण को प्रशासित करने वाले कोई भी नियम तथा उप नियम में प्रबंध बोर्ड या इस प्रकार के अन्य सक्षम निकाय द्वारा उस सीमा तक कोई आशोधन, संशोधन, संयोजन नहीं किया जा सकता जहां विवाद उत्पन्न हो या इन विनियमों के प्रावधानों के लिए हानिकारक हों; तथा सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1980 या इस समय लागू संगत सार्वजनिक म्यास अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना नियमों और उप नियमों में कोई आशोधन, संशोधन या संयोजन नहीं किया जाएगा।

**UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st May, 2010

[UGC (INSTITUTIONS DEEMED TO BE UNIVERSITIES) REGULATIONS, 2010]

PREAMBLE

To regulate, in an orderly manner, the process of declaration of institutions as deemed to be universities; preventing institutions of dubious quality from being so declared; and, further to maintain quality of higher education imparted by institutions deemed to be universities consistent with the ideals of the concept of a university; the University Grants Commission, in exercise of powers conferred under clauses (f) & (g) of sub-section (1) of Section 26 of the University Grants Commission Act, 1956; hereby, makes the following Regulations, namely:—

1.0 SHORT TITLE, APPLICATION AND COMMENCEMENT

- 1.1 These Regulations may be called the UGC [Institutions Deemed to be Universities] Regulations, 2010.
- 1.2 These Regulations shall apply to every institution seeking declaration as an institution deemed to be university under the Act as also, albeit prospectively, to an institution which has been declared as an institution deemed to be university under Section 3 of the UGC Act, 1956.
- 1.3 They shall come into force with effect from the date of their notification in the Official Gazette.

2.0 DEFINITIONS

In these Regulations, unless the context otherwise requires:

- 2.01 "Act" means the University Grants Commission Act, 1956 [Act 3 of 1956].
- 2.02 "Campus" means Campus of the institution deemed to be university at its headquarters, wherein its major facilities, faculty, staff, students and its

Academic Departments are located in a city /town /village in India. While 'off-Campus centre' means an approved (by the Central Government) centre of the institution deemed to be university beyond its Campus in the country, an 'off-shore Campus' means an approved (by the Central Government) centre of the institution deemed to be university beyond its Campus and outside India.

- 2.03 "Commission" means the University Grants Commission (UGC) constituted under the Act or any other body empowered to regulate an institution deemed to be university under any law for the time being in force.
- 2.04 "Committee of Experts" means a Committee appointed by the Commission consisting of academics, researchers or other experts in the relevant fields of knowledge and notified under these Regulations for such purpose as it may specify; and there may be as many Committees of Experts as the Commission may determine for different purposes.
- 2.05 "Constituent Institution" means an institution operating under the administrative, academic and financial control of the sponsoring body and declared as such under the Notification.
- 2.06 "*De-novo* Institution" means an institution devoted to innovations in teaching and research in unique and 'emerging areas of knowledge', so determined by eminent peers of the academic community in the concerned disciplines.
- 2.07 "Emerging area of knowledge" means such area of knowledge as may be notified from time to time by the Commission on the recommendation of a Committee of Experts constituted by the Commission for the purpose; and, such Committee shall make its recommendation having regard to the stage of development of studies and research in relevant disciplines as well as the potential and need for raising standards of study and research thereof, in India.
- 2.08 "Government" means the Central Government, unless the context so specifies.
- 2.09 "Institution" means an institution for higher education engaged in teaching and research of high academic standards at the undergraduate, post-graduate or higher levels.

- 2.10 "Institution deemed to be university" means an institution for higher education so declared, on the recommendation of the Commission, by the Central Government under Section 3 of the Act.
- 2.11 "Processing Fee" means the charges that have to be paid by the applicant institution to the Commission along with the application for processing such application. This amount shall take into account the expenditure to be incurred by the Commission for processing an application that shall include onsite visits of Expert Committees of the Commission. The Commission shall prescribe the processing fee and revise it from time to time.
- 2.12 "Notification" means a notification issued by the Central Government in the Official Gazette declaring an institution for higher education, as an institution deemed to be university u/s 3 of the Act.
- 2.13 "Sponsoring body" means a body being a charitable or a not-for-profit Society or Trust making an application for declaring an institution under its administrative, academic and financial control as a deemed to be university.
- 2.14 "Statutory body" means a body constituted under any law for the time being in force for determining or maintaining standards of quality in the relevant areas of higher education and bodies known as All India Council for Technical Education (AICTE), Medical Council of India (MCI), Dental Council of India (DCI), National Council for Teacher Education (NCTE), Bar Council of India (BCI), Indian Nursing Council (INC), etc. shall be the Statutory bodies for the purposes of these Regulations

3.0 OBJECTIVES OF AN INSTITUTION DEEMED TO BE UNIVERSITY

The objectives for which an institution is declared by the Government as an institution deemed to be university shall be:

- 3.1 To provide for higher education leading to excellence and innovations in such branches of knowledge as may be deemed fit primarily at post-graduate and

UGC [Institutions Deemed to be Universities] Regulations, 2010

research degree levels fully conforming to the concept of university, namely, University Education Report (1948) and the Report of the Committee on Renovation and Rejuvenation of Higher Education in India (2009) and the Report of the Review Committee for Deemed to be Universities (2009).

- 3.2 To engage in areas of specialization with proven ability to make distinctive contributions to the objectives of the university education system that is – academic engagement clearly distinguishable from programmes of an ordinary nature that lead to conventional degrees in arts, science, engineering, medicine, dental, pharmacy, management, etc. routinely offered by conventional institutions.
- 3.3 To provide for high quality teaching and research and for the advancement of knowledge and its dissemination through various research programmes undertaken in-house by substantial number of full time faculty / research scholars (PhDs and Post Doctoral) in diverse disciplines.
- 3.4 To enable creation of institutions deemed to be university under the 'de novo' category devoted to unique and emerging areas of knowledge, not being pursued by conventional or existing institutions - particularly in specific areas of study and research preferably sponsored by the Government of a State / UT or the Central Government regarded as important for strategic needs of the country or for the preservation of our cultural heritage, so determined by a well laid-out process of wide consultation with the eminent peers of academic community.
- 4.0 **ELIGIBILITY CRITERIA FOR AN INSTITUTION TO BE DECLARED AS AN INSTITUTION DEEMED TO BE UNIVERSITY**

An institution applying to be declared as an institution deemed to be university shall have to meet the following stipulations:-

- (a) Eligibility criteria

- 4.1 Has been in existence for at least fifteen years (except in case of institutions seeking declaration as an institution deemed to be university under the 'de novo' category).
- 4.2 Has acquired the characteristics of a university as demonstrated by the diversity of its programmes of study, proven contribution to innovations in teaching; and, verifiable high quality of research output.
- 4.3 Has a record of having undergone periodic reviews and assessments by recognized external accrediting / assessment agencies recognized under any law for the time being in force provided that an institution described in article 3.4 of these Regulations where no accreditation has been made or is possible, shall be subjected to a mandatory assessment of its suitability for declaration as a deemed to be university under the 'de novo' category.
- 4.4 Has well-established, broad-based, and viable under graduate, post graduate, and research programmes in several disciplines with firm inter-disciplinary orientation and linkages.
- 4.5 Shall not be an institution imparting education leading to conventional degrees only. For example, it shall not be limited to imparting programmes in engineering or management or medicine or pharmacy or dental sciences, etc., which can continue to be offered with the existing status of a college.
- 4.6 Shall not be an institution mainly engaged in offering training programmes for in-service personnel, or conducting only skill-oriented or production-related degree or diploma programmes.
- 4.7 Shall be engaged in quality research activity, publications and scholarly works of a high standard as evidenced by inclusion in internationally recognized databases; and shall have strong doctoral / post-doctoral research programmes and significant output of full time Doctoral-level degrees.
- 4.8 Shall have adequate number of full-time fully qualified faculty for teaching and research with at least some being acclaimed leaders in their discipline.

UGC [Institutions Deemed to be Universities] Regulations, 2010

- 4.9 Shall possess the necessary infrastructure for quality research and seamless access to modern information resources.
- 4.10 Shall have a proven record of securing merit-based extramural research funding from various public / private agencies.
- 4.11 Shall have generated Intellectual Property in the form of patents, copyrights and transfer of technology as a desirable attribute.
- 4.12 Shall have a demonstrable and proven record of extension services and societal engagement.
- 4.13 Each constituent unit included in the original proposal shall have accreditation with the highest grade offered, which is currently valid, either from National Assessment and Accreditation Council (NAAC) or all its eligible courses shall be accredited with the highest grade offered, which is currently valid, by National Board of Accreditation (NBA) or an accreditation agency recognized by the Commission from time to time; or valid certificate of assessment where the institution is seeking declaration as a 'de novo' institution deemed to be university.
- 4.14 Shall undertake not to offer any programme in the distance mode.
- (b) Conditions
- 4.15 Once an institution is declared as an institution deemed to be university, no other existing institution can be annexed to it as its constituent institution unless the institution proposed to be annexed fulfills independently, all the criteria stipulated in these Regulations.
- 4.16 There shall be a mandatory intensive external review of every deemed to be university once in every five years based on the criteria prescribed by the Commission from time to time.
- 4.17 The applicant institutions shall be a not-for-profit organization and shall not be engaged in commercialization of higher education.

- 4.18 The applicant institution shall have a track record of having not violated any of the provisions of any of the statutes / guidelines of any Statutory Authority in the period of five years preceding the date of submission of the application seeking status of an institution deemed to be university.

5.0 GOVERNANCE SYSTEM FOR AN INSTITUTION TO BE DECLARED AS AN INSTITUTION DEEMED TO BE UNIVERSITY

An institution to be declared as a deemed to be university shall adhere to the following criteria:

- 5.1 The proposed institution deemed to be university shall be registered either as a not-for profit Society under the Societies Registration Act, or as a not-for-profit Trust under the Public Trust Act with the Society / Trust strictly in accordance with the following provisions.
- 5.2 Among the authorities of the deemed to be universities, there shall be a Chancellor who shall be appointed by the sponsoring Society or the sponsoring Trust. He /she shall be an eminent educationist or a distinguished public figure other than the President of the sponsoring Society or his/ her close relatives.
- 5.3 There shall be no position of Pro-Chancellor(s).
- 5.4 The highest governing body of the deemed to be university shall be a Board of Management to be headed by the Vice Chancellor or a distinguished academic. This body shall consist of a minimum of ten members and a maximum of twelve members.
- 5.5 The Board of Management of the institution shall be independent of the Trust (or) Society with full autonomy to perform its academic and administrative responsibilities. The number of representative(s)/ nominee(s) of the trust (or) society on the Board of Management shall be limited to a maximum of two.

5.6 The Board of Management shall consist of eminent persons capable of contributing to and upholding university ideals and traditions.

5.7 There shall be a Board of Management consisting of the following: -

- i) Vice-Chancellor.....Chairperson
- ii) Pro Vice-Chancellor (wherever applicable)
- iii) Deans of Faculties not exceeding two (by rotation based on seniority)
- iv) Three eminent academics as nominated by the Chancellor
- v) One eminent academic to be nominated by the Central Government in consultation with UGC
- vi) Two teachers (from Professors, Associate Professors) by rotation based on seniority
- vii) One nominee of the sponsoring Society
- viii) The Registrar, who shall be the Secretary

The term of membership of the Board of Management and its powers are as shown in Annexure 1.

5.8 The Vice Chancellor shall be an eminent academic and shall be appointed by the Chancellor on the recommendation of a Search-cum-Selection Committee consisting of a nominee of the Government who shall be nominated in consultation with UGC, a nominee of the Chancellor and that of the Board of Management. The Committee shall be chaired by the nominee of the Board of Management.

5.9 All other statutory bodies of the deemed to be university shall be as described in Annexure 2

6.0 ADMISSIONS AND FEES STRUCTURE

6.1 Admission of students to all deemed to be universities, public or private, shall be made strictly on merit based on an All India examination as prescribed by the Regulations and in consistence with the national policy in this behalf, from time to time.

- 6.2 Admission of Non-Resident Indians (NRI) / Persons of Indian Origin (PIO) / Foreign Students to institutions deemed to be universities shall be governed by the guidelines / Regulations framed by the Commission in this behalf from time to time.
- 6.3 The institution deemed to be university shall preserve the records of admission at least for five years.
- 6.4 The fee structure for various programmes of study in the deemed to be universities shall also be fixed in accordance with the Fee Regulations framed by the Government or by the Commission in this behalf from time to time.
- 6.5 The level of the fees charged for the courses offered in deemed to be universities shall have a reasonable relation to the cost of running the course. The fee structure shall be displayed in the prospectus and on the institution's website.
- 6.6 Every institution declared as a deemed to be university, public or private, shall ensure that there is no commercialization of education. Further, every such institution shall provide for equity and access to all deserving students.
- 6.7 On being declared an institution deemed to be university under the Act, an institution shall admit students to its approved academic programmes, under its enrolment, only from the academic session that follows the notification issued by the Central Government. Enrolment of students to the institution, for any reason whatsoever, in anticipation of the declaration as an institution deemed to be university or inclusion of the institution under the ambit of an institution deemed to be university, shall render the application invalid. The students already on the rolls of the institutions prior to the date of application for declaration as an institution deemed to be university or its inclusion under the ambit of an institution deemed to be university shall continue to be the students, for all purposes, of the affiliating university with whom they have already been enrolled, and shall also be awarded degree only by that affiliating university.

7.0 INFRASTRUCTURE AND OTHER FACILITIES

7.1 It shall have the necessary financial and infrastructural viability for administering and maintaining the institution as an institution deemed to be university and the management capable of contributing to the university ideals and traditions and enhancing the quality of teaching, research and extension activities.

7.2 It shall have the following minimum infrastructure and other facilities:

7.2.1 Land and Buildings:-

- i) Not less than five acres of land at its main Campus if it is located in metropolitan area, seven acres of land at its main Campus, if it is located in non-metropolitan urban area, or ten acres of land at its main Campus, if it is located in non-urban areas or as per the norms of the Statutory / Regulatory body concerned, whichever is higher. In case of multi-disciplinary Institution, the aggregate land requirement shall be the sum of the land area prescribed by various Statutory Councils for all courses
- ii) Administrative Building of at least 1,000 sq. meters.
- iii) Academic Building, including library, lecture theatres and laboratories, of at least 10,000 sq. meters, of which the central library alone being of about 2000 sq. meters.
- iv) Some residential accommodation for teachers, guest house and hostel accommodation for students shall be in existence at the time of applying for declaration as an institution deemed to be university. Hostel accommodation shall be gradually increased to at least 25% of the students within 3 years of existence of institution deemed to be university.
- v) In case the institution is engaged in conducting professional programmes of study, the prevailing norms and standards of the respective Statutory Body shall be applicable, in addition to the above.

vi) Equipment, Books, Journals and other infrastructural facilities:

Equipment, Books and Journals of the institution shall be commensurate with the size and activities of the institution and shall satisfy the requirements of the Statutory/Regulatory body concerned. The institution shall also have Broadband Connectivity of appropriate level in order to cater to the needs of self learning / virtual experiments / hands on techniques as well as provide electronic access to journals, books and other learning materials.

7.3 Academic Programmes

- Academic program shall offer sufficient scope for interdisciplinary learning and research
- Delivery of program shall be based on innovative teaching and learning process and evaluation system
- Shall be supported by adequate qualified faculty

It shall have under graduate and at least five postgraduate academic Departments with every Department having in position a minimum permanent faculty of one Professor, two Readers and three Lecturers for general courses and in case of courses in other disciplines such as Engineering & Technology, Medicine, Dental, Nursing, Pharmacy, Physiotherapy etc. the faculty shall be as per the norms and guidelines of the respective Statutory Council having the qualifications and pay scales prescribed by the Commission / respective Statutory Council together with the necessary supporting technical and ministerial staff as per the norms and standards laid down by the respective Statutory body.

7.4 Financial Viability:

The financial viability of the institution shall be verifiable by the audited statements of accounts of the institution for the previous five years immediately preceding the date of application for declaration as deemed to be university.

7.5 Corpus Fund:

- 7.5.1 In the case of Institutions not maintained or financed by the Government, the following Corpus Fund shall be created and maintained permanently in the name of the proposed institution deemed to be university by way of irrevocable Government Securities or other forms approved by the Commission:
- a. For institutions conducting professional programmes, such as Engineering & Technology, Medicine – Rs. 8.00 crore
 - b. For institutions conducting programmes, such as Management, Law, Education – Rs.5.00 crore
 - c. For institutions conducting other programmes – Rs.4.00.crore
 - d. For institutions conducting both professional and other programmes – Rs. 10.00 crore
 - e. For institutions under *de novo* category – Rs. 25 crore
- 7.5.2 The Corpus fund shall not be liquidated without prior permission of the Commission
- 7.5.3 The Commission shall have the power to direct any upward revision of the Corpus Fund from time to time.
- 7.5.4 The interest accrued on the Corpus Fund may be used only for the purpose of development of the institution deemed to be university.
- 7.5.5 In the event of withdrawal of the declaration of 'deemed to be university' status or dissolution of the Society or the Trust of the institution deemed to be university, the Corpus Fund shall stand forfeited to the Commission for meeting the liabilities, if any.
- 7.5.6 The provisions related to corpus fund shall be applicable only to those deemed universities which come into existence after notification of these Regulations. However, in the case of public funded institutions, the commitment of the

State / UT or the Central Government to fund them continuously shall be considered as sufficient.

- 7.6 All movable and immovable properties of the institution or institutions that form the integral part of the proposed institution deemed to be university shall remain legally vested in the name of the institution in the manner as recognized under the Transfer of Property Act, 1882 or any other law which may be in force. However, in case the immovable property has been acquired by the institution by way of lease, the lease shall be perpetual in nature and initially for at least 99 years.
- 7.7 The income and property of the institution, howsoever derived, shall be utilized only for the promotion of the objectives of the institution including its growth and development. No portion of the income / property of the institution shall be paid or transferred, directly or indirectly by way of profit, to the persons who were / are members of the institution, provided that nothing herein contained shall prevent the payment in good faith or remuneration to any member thereof or to any other person in return for any service rendered to the institution or for travelling, halting and other similar charges, and all such expenditure shall be appropriately reflected in the accounts of the institution, maintained for the purpose.

8.0 PROCEDURE FOR BEING DECLARED AS AN INSTITUTION DEEMED TO BE A UNIVERSITY

- 8.01 The institution fulfilling the minimum eligibility criteria as laid down in these Regulations for considering proposals for declaration as an institution deemed to be a university may send its application in duplicate in the prescribed Proforma to the Secretary, Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education, Government of India. Processing fees for each application shall be paid to the Commission by way of a Demand Draft drawn in favour of The Secretary, University Grants Commission, Bahadurshah Zafar Marg New Delhi 110002.
- 8.02 It shall submit a certificate as also an undertaking along with its application to the effect that the professional programmes already being conducted by it, if

any, have the approval of the relevant Statutory/Regulatory bodies like AICTE, MCI, DCI, NCTE, BCI, INC, etc., along with a duly attested copy of the letter of approval granted to it by such bodies. In addition, each application shall be accompanied by an essentiality certificate from the State Government concerned, wherever necessary.

- 8.03 It shall also submit, along with its application, a certificate from the affiliating university / affiliating universities, as the case may be, to the effect that the students already admitted in the institution or institutions that is / are to become integral part of the proposed institution deemed to be University institution enrolled under the said affiliating university / affiliating universities shall continue to be the students of that university for all purposes under the existing terms and conditions till they complete the relevant academic programmes.
- 8.04 The Ministry of Human Resource Development shall refer the application to the Commission for its advice.
- 8.05 The Commission shall make a preliminary scrutiny of the application submitted by the institution and, if necessary, write to the institution pointing out the lacuna(e), if any, and call for clarification / additional information / requisite documents. The Commission shall also write to the State/UT Government concerned to elicit the latter's views on the application.
- 8.06 The Commission shall examine the application with the help of an Expert Committee constituted as per the procedure prescribed in these Regulations. The Committee of Experts shall not include any sitting member of the Commission. The Expert Committee so constituted shall have one member as representative of the concerned Statutory Council(s), who may have the authorization to remit the advice.
- 8.07 The Expert Committee shall, *inter alia*,
- a) scrutinize and examine the application in detail;

- b) visit the Institution, hold discussions with its major stake holders and make on the spot assessment of its academic viability to function as an institution adhering to the concept and ideals of a university as enunciated in these Regulations;
- c) ascertain the academic and research excellence based on available records;
- d) give specific information on matters like performance of students who have graduated, research scholars registered for PhD, sponsored research projects completed and on-going, research publications in indexed journals, faculty having PhD, etc., for the past five years;
- e) verify its records to ascertain its financial viability; and
- f) submit a report to the Commission to enable it to advise the Government appropriately.

8.08 The report of the Expert Committee shall be examined by the Commission along with the views of the State/UT Government, if any, and the Statutory/Regulatory body concerned and thereafter, the Commission shall submit its advice to the Ministry of Human Resource Development for the Ministry's consideration. The report of the Statutory body to the Commission shall indicate not merely the fulfillment of minimum requirements for the institution's performance as a college, but shall include its assessment of the achievements of the institution in high standards of education and research as well as its capability to promote innovation and excellence commensurate with the status as a university in contrast to a conventional professional college.

8.09 The advice of the Commission shall state the reasons for advising the Central Government to declare the institution as an institution deemed to be university or otherwise, along with the number and names of institutions to be part of the institution deemed to be university.

8.10 The Commission, in its final recommendations to the Central Government, shall apprise the Government regarding submission of necessary documents related to transfer of moveable and immovable assets in the name of the proposed institution deemed to be university and other conditions, if any.

- 8.11 Each State / UT Government shall formulate a transparent policy for giving its views under article 8.05 and shall send their considered comments, in the proforma prescribed by the Commission, within 60 days, to the Commission and the Central Government, with a copy to the institution concerned. In case no such comments are received by the Commission within 60 days of the issue of the letter, it shall be presumed that the State / UT Government have no comments to offer on the application.
- 8.11.1 The State / UT Government recommending the proposal would have to indicate its willingness to safeguard the interest of the students admitted to the proposed deemed to be university in the event it ceases to exist as such, for any reason whatsoever.
- 8.12 Having been satisfied that the institution fulfills all the requirements as laid down in these Regulations the Central Government may issue a notification under Section 3 of the Act, declaring such institution as an institution deemed to be university. This declaration would initially be made for a period of five years. Confirmation of the declaration of the 'deemed to be university' would be based on a review of the institution deemed to be university's compliance and the institution's satisfactory performance with the provisions of these Regulations.
- 8.13 If on the advice of the Commission, the Central Government comes to the conclusion that the institution does not qualify to be declared as a institution deemed to be university, it may inform the institution accordingly stating reasons there for.
- 8.13.1 In case the Government disagrees with the recommendation of the Commission, the Government shall provide reasons in writing and its decision shall be final.
- 8.14 The decision not to declare an institution as an institution deemed to be university shall be considered for review not before one year from the date of the earlier decision only on a specific request for review made by the

institution concerned to the Central Government. Institutions may request the Central Government for such a review only after having rectified the deficiencies based on which the Central Government had rejected its earlier application / proposal.

8.15 The Central Government may refer the matter to the Commission for the latter's advice.

8.16 The Commission shall then initiate the process of review, in the manner prescribed in this Regulation as per articles 8.05 through 8.07 above, for scrutiny and evaluation of the revised application by constituting a new Expert Committee. This Committee shall be at least of the same size as the previous one that had recommended rejection earlier, with no expert member from the previous Committee as its member.

8.17 The decision taken on such a 'review' shall not be reconsidered or reviewed further. It is however permissible for the applicant institution to re-apply seeking declaration as an institution deemed to be university after a gap of not less than three years from the date on which the decision of the Government on the 'review' was communicated to the institution concerned.

8.18 The Commission shall post information about the status of each application on a monthly basis on its website. Further, the Commission shall submit an annual report to the Central Government giving a progress report on the fulfillment of the conditions stipulated in the notifications issued by the Central Government in this regard.

9.0 INSTITUTION DEEMED TO BE UNIVERSITY UNDER THE *de novo* CATEGORY

9.1 An institution seeking declaration as an institution deemed to be university under this category, shall provide evidence of being devoted to unique and emerging areas of knowledge not being pursued by conventional / existing institutions - particularly in specific areas of study and research and preferably, sponsored by the Government of a State / UT or the Central Government regarded as important for strategic needs of the country or for

the preservation of our cultural heritage, so determined by a well laid-out process of wide consultation with the eminent peers of academic community. For this purpose, the applicant institution shall give detailed syllabi of the courses and research programmes conducted by it in the emerging areas of knowledge.

- 9.1.1 *De novo* institutions desiring to expand their activities and enter into related / complementary areas shall do so after its declaration as an institution deemed to be university is confirmed by the Government following a review at the end of five years of the institution's existence as an institution deemed to be university. Such institutions shall have to seek prior permission of the Central Government, which shall cause the Commission to subject such institutions to a rigorous peer review before according such permission.
- 9.2 On receipt of an application from an institution seeking declaration as an institution deemed to be university under the *de novo* category through the Government (Ministry of Human Resource Development) for advice, the Commission shall follow the procedures laid down in article 8 of the Regulations. However, before proceeding to the stage of the process as laid down in article 8, the Commission shall examine the application with the help of a Committee consisting of a Chairperson and three experts in the relevant disciplines, who shall be nominated by the Chairman, UGC. The Committee shall also include a representative from the relevant Statutory Council. The applicant institution shall also make a presentation before the Committee. The Committee shall have the duty to recommend whether it is an institution in emerging areas of knowledge in conformity with the policy of the Commission and whether the institution can be considered under *de novo* category before deciding on a visit to the institution by an Expert Committee of the Commission.
- 9.3 The Central Government may follow the procedure in article 8 and, after being satisfied that the institution fulfills the requirements as laid down in these Regulations, may issue a notification declaring the institution provisionally as an institution deemed to be university under the *de novo* category.

- 9.4 The Central Government may, on the advice of the Commission, confirm the declaration of an institution deemed to be university made under the *de novo* category, by way of a notification, after completion of five years of the institution as such. The Commission shall render its advice for this purpose on the basis of five successive annual performance reports of Expert Committee(s) appointed by the Chairman of the Commission to review the institution concerned. If the Central Government comes to the conclusion that the institution does not qualify to be declared as an institution deemed to be university, it may inform such institution accordingly stating reasons there for.

10.0 FUNDING

Institutions which are declared as institutions deemed to be universities shall continue to receive the funds for their maintenance and developmental expenditure, including the salary and non-salary increases in expenditure and the future expansion, from the same funding sources which have been funding them prior to such declaration. Such Institutions may also supplement their finances.

11.0 MAINTENANCE OF STANDARDS

An institution deemed to be university shall maintain standards, higher than the minimum, of instruction, academic and physical infrastructure, qualifications of teachers, etc. as prescribed for college level institutions by the Commission or by the Statutory/Regulatory body concerned, such as All India Council for Technical Education (AICTE), Medical Council of India (MCI), Dental Council of India (DCI), National Council for Teachers Education (NCTE), Bar Council of India (BCI), Indian Nursing Council (INC), etc. and shall obtain their approval for running various programmes of study, where applicable. This shall be periodically monitored by the duly constituted Committee (s) of the Commission.

12.0 NEW DEPARTMENTS, OFF-CAMPUS CENTRES AND OFF-SHORE CAMPUSES

- 12.01 An institution deemed to be university shall normally operate within its own main Campus as is declared by the Central Government in the notification and conduct approved programmes of study falling within the area of its specialization.
- 12.02 If an institution deemed to be university wishes to start a new Department dealing with a subject which is not in the field of its specialization or in an allied field, it may do so only if that field is covered under the objectives for which the institution deemed to be university was established, and with the prior approval of the Commission.
- 12.03 An institution deemed to be university may be allowed to operate beyond its approved geographical boundaries and start Off-Campus(es) / Off-shore Campus(es) under the following conditions:
- 12.03.1 It has been in existence as an institution deemed to be university for a minimum period of three years
- 12.03.2 It has been conducting post-graduate programmes and research
- 12.03.3 It has earned a reputation for excellent and innovative teaching, which, inter alia, includes practicing academic and examination reforms like introducing modular structure, continuous internal evaluation, etc. and for meaningful and purposeful research and extension activities
- 12.03.4 It has a good track record of conforming to the relevant Regulations/norms of the Commission and other Statutory/Regulatory bodies regarding minimum standards of instruction, qualification of faculty, merit-based admission of students on an all India basis and reasonable fee structure;
- 12.03.5 It has obtained prior approval of the Statutory/Regulatory body to start the new department / programme, wherever applicable, and undertakes to comply with all the requirements of the said body;

- 12.03.6 It has a currently valid accreditation from National Accreditation and Assessment Council (NAAC) with the highest grade offered;
- 12.03.7 It has adequate financial resources for starting the proposed new department/ off-Campus Centre / off-shore Campus;
- 12.03.8 It has not entered into any franchise agreement, either overtly or covertly, with any other organization for establishing and running the off-Campus Centre / off-shore Campus of the institution deemed to be university.
- 12.04 A new Department in the Campus or in the approved off-Campus Centre shall be established by an institution deemed to be university only with the prior approval of the Commission.
- 12.05 An off-Campus Centre shall be established by an institution deemed to be university with the prior approval of the Central Government, on the recommendation of the Commission. The Central Government shall also consider the views of the State / UT Government concerned where the off-Campus Centre is proposed to be established.
- 12.06 An off-shore Campus of an institution deemed to be university shall be established with the prior permission of the Central Government, on the recommendation of the Commission:
Provided that the country, where such off-shore Campus is proposed to be established, requires grant of approval by it for such establishment, then the application to the Central Government for permission shall be made along with the approval granted by that country:
Provided further that if the country where such off-shore Campus is proposed to be established requires prior concurrence of the Government of India for the approval, referred to in the first *proviso*, of that country to be granted, then the Central Government, on the recommendation of the UGC, may give a 'No Objection' to the proposal but such 'No Objection' shall not be construed as permission of the Central Government to the institution deemed to be university to establish an off-shore Campus. Such an institution deemed to be

university shall also submit an undertaking that it shall comply with all laws, norms or standards prescribed by that country where the off-shore Campus is proposed to be established.

- 12.07 An institution deemed to be university intending to start a new off-Campus Centre / off-shore Campus shall apply to the Government of India in the prescribed proforma at least six months prior to the proposed date of starting the Centre / off-shore Campus. The Government of India shall forward the proposal to the Commission for its advice. In case of establishment of a new Department in the Campus or an approved off-Campus Centre, the application in the prescribed format shall be sent directly to the Commission.
- 12.08 The Commission shall cause to be undertaken a spot visit / verification of the proposed off-Campus(es) and off-shore Campus(es) to verify the infrastructure facilities, programmes, faculty, financial viability, etc. before sending its advice to the Central Government. In case of a proposal for establishment of a new Department, the Commission shall arrive at a decision after the spot visit.
- 12.09 In case such permission is not granted, the institution deemed to be university may re-apply for such permission, but not before two years from the date of rejection of its earlier application.
- 12.10 The off-Campus Centre / off-shore Campus shall have adequate academic and physical infrastructure facilities as per the norms and standards prescribed by the Commission and the Statutory / Regulatory body concerned. Such facilities shall be proportionate to the size and activities of the off-Campus Centre / off-shore Campus. The off-shore Campus of the institution deemed to be university shall also comply with all norms and standards of the country in which it is established.
- 12.11 The off-Campus Centre/ off-shore Campus shall be directly administered by the parent institution deemed to be university in matters of admission, instruction, evaluation, conferring of degrees, etc. In case of the off-shore Campus, lease in the name of the institution deemed to be university may be

acceptable (as per the procedure of the country in which such off-shore campus is proposed to be established). In case lease is not permissible in any particular country, land and other assets in the name of a Strategic Partner shall be accepted. For this, the institution deemed to be university shall have a duly registered MOU / collaboration with the Strategic Partner which shall be governed in accordance with the law for the time being in force, in India.

12.12 The new Department / off-Campus Centre / off-shore Campus shall offer only those programmes of study which are approved by the appropriate bodies of the institution deemed to be university and the statutory / regulatory body concerned such as All India Council for Technical Education (AICTE), Medical Council of India (MCI), Dental Council of India (DCI), Pharmacy Council of India (PCI), National Council for Teachers Education (NCTE), Bar Council of India (BCI), Indian Nursing Council (INC), etc. wherever applicable. In case of any new or existing institution of higher learning proposed to be brought under the ambit as a constituent unit of any existing institution deemed to be university, only those students who were admitted in such institutions on a date subsequent to the date of notification of the declaration under Section 3 of the UGC Act 1956 in regard to bringing the institution under the ambit of the existing institution deemed to be university, shall be eligible for being examined by the institution deemed to be university and therefore, for the award of degree or any other qualification by the institution deemed to be university on successful completion of their respective courses or programmes of study.

12.13 In the case of an off-shore Campus, the remittances of funds from / to the main Campus shall be governed by the Reserve Bank of India rules.

12.14 The over-all performance of an off-Campus Centre / off-shore Campus shall be monitored by the Commission biennially for six years and subsequently after five years and whose directions on management, academic development and improvement shall be binding on the Campus.

12.15 If the functioning of the Campus / off-Campus Centre of an institution deemed to be university does not meet the standards stipulated by the Commission

and remains unsatisfactory for two consecutive reviews, as assessed by the Commission, the institution deemed to be university may be instructed by the Central Government, on the advice of the Commission, to close down the off-Campus Centre / Campus concerned. The Commission may initiate action against erring institutions deemed to be universities even on the basis of complaints received against such Centres / Campuses. In the interest of the students, the Commission may allow the Centre / Campus to function till the last batch of students enrolled therein, as on the date of such instruction, passes out. The institution deemed to be university shall take appropriate steps to safeguard the interests of the faculty / staff at the Centre / Campus. In the event of closure of the Centre / Campus, the assets and liabilities thereof shall revert to the institution deemed to be university.

- 12.16 The Commission may give an 'in-principle No Objection' to the institution deemed to be university for establishing an off-Campus Centre, wherever required by the Statutory Councils, if the Commission is so satisfied about the viability of the proposal; but such 'No Objection' shall not be construed as permission of the Commission to the institution deemed to be university to establish an off-Campus Centre. In all such cases, formal proposal(s) shall be examined by the Commission under these Regulations. The institution deemed to be universities shall not admit student(s) to its course(s) in such off-Campus Centre(s) before the permission is granted by the Commission to such proposal(s).

13.0 INCLUSION OF OTHER INSTITUTIONS UNDER THE AMBIT OF INSTITUTION DEEMED TO BE UNIVERSITY

- 13.01 An institution deemed to be university may apply, in the proforma prescribed by the Commission, for inclusion of institutions existing under the same management as its constituent institution / unit after confirmation of its declaration as an institution deemed to be university, as mentioned under article 8.12.

- 13.02 All institutions deemed to be universities shall necessarily comply with the conditions that the Commission may insist upon in this regard from time to time, to prevent franchising of education.
- 13.03 If an institution existing under the same management is affiliated to a university, it shall be included in the ambit of the institution deemed to be university only on its disaffiliation from the affiliating university. The affiliating university shall also give its consent to the effect that the students of that particular institution(s) who have already been enrolled under it, shall continue to pursue their courses under its affiliation for all purposes and that it shall also award degrees to these students upon successful completion of the courses they are presently pursuing at such institution(s).
- 13.04 Such institution shall have accreditation with the highest grade offered, which is currently valid, either from National Assessment and Accreditation Council (NAAC) or all its eligible courses shall be accredited with the highest grade offered, which is currently valid, by National Board of Accreditation (NBA) or an accreditation agency recognized by the Commission from time to time.
- 13.05 An institution deemed to be university intending to bring an institution within its ambit as its constituent unit shall submit a proposal, in duplicate, in the proforma prescribed by the Commission, to the Secretary, Ministry of Human Resource Development (Department of Higher Education) Government of India, subject to the said institution fulfilling the eligibility criteria and other relevant conditions stipulated under these Regulations.
- 13.06 The Ministry of Human Resource Development, Government of India shall refer one copy of the proposal to the Commission for advice.
- 13.07 The Commission shall then adopt the procedure described under articles 8.05 to 8.07 to examine the proposal so received by it.
- 13.08 The Commission shall verify all the relevant factors and aspects through its Expert Committee before making a suitable recommendation to the Ministry of Human Resource Development, Government of India.

- 13.09 The inspection report as well as the recommendation of the Expert Committee along with the opinion / comments of the Statutory / Regulatory body concerned and the views, if any, of the State Government concerned shall be examined by the Commission as per procedure before making recommendation to the Ministry of Human Resource Development, Government of India.
- 13.10 If rejected, the Central Government shall inform the institution, accordingly.
- 13.11 After taking the relevant steps of the procedure prescribed in article 8, the Central Government shall notify the inclusion of the institution under the ambit of the institution deemed to be university on being satisfied that institution deemed to be university has:
- a) earned a reputation for excellent and innovative teaching, for meaningful and purposeful research, for practicing academic and examination reforms like modular structure, continuous internal evaluation, etc. and for extension activities; and
 - b) a good track record of conforming to the relevant Regulations / norms of the Commission and the Statutory / Regulatory body concerned regarding minimum standards of instruction, qualifications of teachers, merit-based admission of students on an all India basis and reasonable fee structure.
- 13.12 On an institution coming under the ambit of the institution deemed to be university, the institution deemed to be university shall award degrees only to the students enrolled in the institution after the institution concerned disaffiliates itself from the affiliating university. The students enrolled in such an institution prior to its inclusion under the ambit of the institution deemed to be university, shall, receive their degrees from the university to which the institution was affiliated at the time of their enrollment.
- 13.13 Once an institution comes under the ambit of an institution deemed to be university, it shall be at par with an off-Campus of the institution deemed to

be university, and all articles of these Regulations relating to off-Campus Centres of institutions deemed to be universities shall be applicable to it.

13.14 The entire movable and immovable property as well as the existing manpower of the institution and its records (except those pertaining to the students who had already registered till they pass out of the Institution) shall be transferred to the institution deemed to be university before the notification.

13.15 If an institution, not being under the same registered Society / Trust, is desirous of coming under the ambit of an institution deemed to be university, it shall apply to the Society / Trust and become a part of the Society / Trust, as per procedure of Societies Registration Act or Trust Act, as the case may be. Thereafter, the Society / Trust shall follow these Regulations to bring it under the ambit of the institution deemed to be university.

13.16 If the application of an institution deemed to be university for bringing an institution under its ambit is rejected for any reason whatsoever, the institution deemed to be university shall be eligible to re-apply, but not before two years from the date of the rejection of its earlier such application.

14.0 JOINT PROGRAMMES

14.1 An institution deemed to be university may conduct joint academic programme(s) with other Universities / institutions deemed to be universities in India and abroad with the prior approval of the Commission. The proposed joint programme(s) shall conform to the Acts and Rules of the Commission that shall apply to such programmes from time to time.

14.2 There shall be sufficient safeguards so as to protect the interests of students enrolled in such programmes.

14.3 The joint programmes shall be subjected to mandatory assessment and accreditation.

15.0 INSTITUTION DEEMED TO BE UNIVERSITY OPEN TO ALL

15.1 Admission and employment in an institution deemed to be university shall be open to all citizens of India regardless of race, religion, caste or creed and the area/ place of residence in India.

15.2 All policies and procedures, as applicable to the university level institutions of public and privately funded institutions respectively, shall apply to the appropriate category of institutions deemed to be universities.

16.0 INSTITUTION DEEMED TO BE UNIVERSITY TO BE UNITARY

Once an institution is declared as a unitary institution deemed to be university, it shall not affiliate any other institution.

17.0 RESERVATION POLICY

The institution deemed to be university shall implement the reservation policy in admissions and recruitment, in accordance with any Act of Parliament for the time being in force.

18.0 DISTANCE EDUCATION

No institution deemed to be university, so declared by the Central Government subsequent to these Regulations, shall be allowed to conduct courses in the Distance mode. Also, such institutions declared as such, prior to these Regulations, shall not be allowed to conduct courses in the Distance mode from any of its off-Campus Centre / off-shore Campus approved subsequent to these Regulations.

19.0 MEETINGS OF UNIVERSITY BODIES

The institution deemed to be university shall conduct meetings of all its statutory bodies, like Board of Management, Academic Council, etc. at regular intervals as per the Regulations and the minutes of each such meeting shall be displayed in the website of the institution.

20.0 USE OF THE WORD 'UNIVERSITY'

An Institution deemed to be University shall not use the word 'University' suffixed to its name but may mention the words "deemed to be university" within parenthesis suffixed thereto.

21.0 PROHIBITION OF USE OF CERTAIN WORDS IN NOMENCLATURE

Educational institutions established by the Central Government alone may prefix the words, "Indian / National Institute" (either in English or in vernacular) with their respective names.

22.0 CONSEQUENCES OF VIOLATION OF REGULATIONS

22.1 The Central Government / Commission shall have the right to cause an inspection of the institution deemed to be university, its buildings, laboratories, its examinations, teaching and other work conducted or done by the institution deemed to be university, and to cause an enquiry to be made, if considered necessary by the Central Government / UGC, in respect of any matter of the institution deemed to be university.

22.2 After conducting an inspection of the institution deemed to be university by the Commission on its own or on the basis of any other authentic information or report received from any other reliable source(s) and after considering the explanation submitted by the institution deemed to be university, if the Commission is satisfied that the institution deemed to be university has violated any of the provisions of these Regulations or any directives issued by the Commission, the Commission may direct the concerned institution deemed to be university not to admit new students for the period to be decided by the Commission and in case of deliberate continuous violation of these Regulations, may advise the Central Government for withdrawal of the declaration notifying the institution as an institution deemed to be university. In the event of such withdrawal of the declaration, the entire movable and immovable properties of the institution deemed to be university shall stand

forfeited to the Commission. For first violation, the withdrawal may be restricted to one academic session which can be extended up to five academic sessions for repeated violations. However, for serious and deliberate violation, the status of deemed to be university shall be withdrawn permanently.

22.3 In the event of the withdrawal of the deemed university status, action shall be simultaneously initiated to protect the interests of the students according to such precedents and practices as applicable or determined for the specific situation.

22.4 If an institution deemed to be university wishes to withdraw itself or its constituents from the status of 'institution deemed to be university', it may do so with the prior permission of the Central Government. Such withdrawal shall take effect only after the last batch of students then enrolled, passes out of the institution deemed to be university.

23.0 **CONSIDERATION OF OLD PROPOSALS**

All proposals (whether seeking declaration as an institution deemed to be university or seeking approval for establishing off-Campus Centres / off-shore Campus(es) or inclusion of off-Campus Centres in the ambit of the institution deemed to be university), which are either pending / in process in the Commission or have been received by the Central Government, shall be governed by these Regulations.

N. A. KAZMI, Secy.
[ADVT. III/4/113/10-Exty.]

Annexure-1

1. Every institution seeking to be declared as an institution deemed to be university under Section 3 of the UGC Act shall be registered as a Society or as a Trust in the name and style of the proposed institution deemed to be university.

2. Each such institution shall indicate, unambiguously, the following:

i) Name: The name of the Society / Trust, along with the name of the proposed institution deemed to be university.

ii) Office: The registered office of the Society or Trust; the official address of institution.

iii) Objectives: The objectives of the proposed institution deemed to be university shall be clearly enunciated. The objectives shall be well-defined and well known to the students, teachers and non-teaching staff of the proposed institution deemed to be university.

iv) The objectives as set forth above shall be regarded in law to be charitable in nature.

3. **Programmes of the institution deemed to be university**

3.1 In keeping with objectives, the institution shall spell out the following:

- (i) The proposed programmes of study and research and facilities to provide for instruction in such branches of study as the institution deems appropriate for the advancement of learning and dissemination of knowledge;

(ii) The nature of Degrees and Diplomas and/ or Certificates to persons who have satisfactorily completed the approved programmes of study and / or research and the scheme prescribed for examination and evaluation.

(iii) Details of other academic schemes such as visitor-ship, fellowship, prizes, and medals.

4. Management of the Institution

4.1 The names, addresses, and occupation of the members of the first Board of Management to whom the management of the institution is entrusted till the various authorities are constituted in accordance with the Rules, shall be furnished at the time of application along with their letter of consent.

4.2 The Board of Management shall be a compact and homogeneous body enabling it to promptly take and implement well considered decisions and to effectively handle crisis situations.

4.3 The Board of Management shall consist of: -

- ix) Vice-Chancellor.....Chairperson
- x) Pro Vice-Chancellor (wherever applicable)
- xi) Deans of Faculties not exceeding two (by rotation based on seniority)
- xii) Three eminent academicians as nominated by the Chancellor
- xiii) One eminent academic to be nominated by the Central Government in consultation with UGC
- xiv) Two teachers (from Professors, Associate Professors) by rotation based on seniority
- xv) One nominee of the sponsoring Society
- xvi) The Registrar, who shall be the Secretary

The term of membership of the Board of Management and its powers shall be as follows:

4.3.1 All the members of the Board of Management other than the ex-officio members and the members of the teaching staff shall hold office for a term of three years and shall be eligible for reappointment.

4.3.2 Members of teaching staff in the Board of Management shall hold office for a period of 2 years or till such time as they continue to be members of the teaching staff, whichever is less.

4.4 Powers of the Board of Management:

The Board of Management shall be the principal organ of Management and principal executive body of the institution deemed to be university and shall have the following powers, namely:

- i) To establish, on the advice of the Academic Council, Divisions and Departments for the academic work and functions of the institution deemed to be University and to allocate areas of study, teaching and research to them;
- ii) To create teaching and academic posts, to determine the number, cadres and qualifications thereof as approved by the Commission, and statutory body concerned and the emoluments of such posts in consultation with the Finance Committee;
- iii) To appoint such Professors, Associate Professors, Assistant Professors and other academic staff as may be necessary on the recommendation of the Selection Committee;
- iv) To lay down the duties and conditions of service of the Professors, Associate Professors and Assistant Professors and other academic staff of the institution deemed to be university in consultation with the Academic Council;
- v) To provide for appointment of Visiting fellows and Visiting Professors;

- vi) To create administrative, ministerial and other necessary posts in terms of the cadres laid down and to make appointment thereof in consultation with the Finance Committee;
- vii) To constitute, for the benefit of the teaching, academic, technical, administrative and other staff, such pension, insurance, provident fund and gratuity as it may deem fit and aid in the establishment and support of Association, Institutions, Funds, Trusts and conveyances calculated to benefit the staff and the students of the Institution deemed to be University;
- viii) To regulate and enforce discipline among the employees of the institution deemed to be university and to take appropriate disciplinary action, wherever necessary;
- ix) To entertain and adjudicate upon and, if thought fit, to redress any grievances of the employees and students of the institution deemed to be university;
- x) To grant leave of absence to the Vice-Chancellor and to make necessary arrangements for carrying on his/her functions during the period of absence;
- xi) To approve the award of Degrees and diplomas based on the results of examinations and tests and to confer, grant or award Degrees, Diplomas, Certificates and other academic titles and distinctions;
- xii) To fix the emoluments and traveling and other allowances of examiners, moderators, tabulators and such other personnel appointed for examinations in consultation with the Academic Council and the Finance Committee;
- xiii) To institute Fellowships, including Travel Fellowships, Scholarships, Studentships, Medals and Prizes in accordance with the Rules to be framed for the purpose;

- xiv) To advise the Holding Trustees (if any) on matters regarding acquisition, management and disposal of any immovable property on behalf of the institution deemed to be university;
- xv) To purchase, take on lease or accept as gift or otherwise any land or buildings or works which may be necessary or convenient for the purpose of the institution deemed to be university, on such terms and conditions as it may deem fit and proper, and to construct or alter and maintain any such building(s) or work(s);
- xvi) To transfer or accept transfers of any movable property on behalf of the institution deemed to be university;
- xvii) To execute in consultation with the Holding Trustees (if any) conveyance, transfer Government Securities, re-conveyances, mortgages, leases, bonds, licenses and agreements in respect of property, movable or immovable, belonging to the institution deemed to be university or to be acquired for the purposes of the institution deemed to be university;
- xviii) To issue appeals for funds for carrying out the objectives of the institution deemed to be university and, consistent with the provisions of the objectives, to receive grants, donations, contributions, gifts, prizes, scholarship, fees and other moneys, to give grants and donations, to award prizes, scholarships, etc.;
- xix) To raise and borrow in consultation with the Holding Trustee (if any) money on bonds, mortgages, promissory notes or other obligations or securities founded or based on any of the properties and assets of the institution deemed to be university, or without any securities, upon such terms and conditions as it may think fit and to pay out of the funds of the institution deemed to be university, all expenses incidental to the raising of money and to repay and redeem the money borrowed;

- xx) To draw and accept and make and endorse discount and negotiate Government of India's and other promissory notes, bills of exchange, cheques or other negotiable instruments;
- xxi) To maintain a fund to which shall be credited:
 - (a) all moneys provided by the Central or State / UT Government(s) / University Grants Commission;
 - (b) all fees and other charges received by the institution deemed to be university;
 - (c) all money received by the institution deemed to be university as grants, gifts, donations, benefactions, bequest or transfers and
 - (d) all money received by the institution deemed to be university in any other manner or from any other source;
- xxii) To open account or accounts of the institution deemed to be university with anyone or more scheduled banks and to lay down the procedure for operating the same;
- xxiii) To deposit all moneys credited to the funds in scheduled banks or to invest them in consultation with the Finance Committee;
- xxiv) To invest the funds of the institution deemed to be university or money entrusted to the institution deemed to be university in or upon such securities and in such manner as it may deem fit and from time to time transpose any investment;
- xxv) To maintain proper accounts and other relevant records and prepare Annual Statements of Accounts, including the balance sheet for every previous financial year, in such form as may be prescribed by the Regulations / Bye-Laws;

- xxvi) To manage, regulate and administer the revenue, the finance, accounts, investments, properties, business and all other administrative affairs of the institution deemed to be university and for that purpose to appoint such agent or agents as it may deem fit;
- xxvii) To provide building or buildings, premises, furniture, fittings, equipments, appliances and other facilities required for carrying on the work of the institution deemed to be university;
- xxviii) To establish, maintain and manage residencies for faculty and staff and hostels for the students of the institution deemed to be university;
- xxix) To recognize and maintain control and supervision on hostels owned and managed by other agencies for the students of the institution deemed to be university and to rescind such recognition;
- xxx) To appoint such committees for such purpose and with such powers as the Board of Management may think fit and to co-opt such persons on these Committees as it thinks fit;
- xxxi) To appoint in order to execute an instrument or transact any business of the institution deemed to be university, any person as attorney of the institution deemed to be university with such powers as it may deem fit;
- xxxii) To appoint Auditor(s) for the ensuing year;
- xxxiii) To select an emblem and to have a common seal for the institution deemed to be university and to provide for the custody and use of such seal;

xxxiv) To delegate all or any of its powers to any Committee or sub-Committee constituted by it or the Vice-Chancellor of the institution deemed to be university or any other person;

xxxv) To conduct all administrative affairs of the institution deemed to be university not otherwise specifically provided for;

xxxvi) To take all necessary decisions for the smooth and efficient functioning of the institution deemed to be university.

4.5 Meetings of the Board of Management:

- (i) The Board of Management shall meet at least four times a year. Not less than 15 days' notice shall be given of a meeting of the Board of Management. Eight (8) members shall make the quorum for a Board of Management meeting.
- (ii) Every meeting of the Board of Management shall be presided over by its Chairman and in his/her absence, by a member chosen by the members present, from amongst themselves.
- (iii) Each member of the Board of Management, including its Chairman, shall have one vote and decisions at the meetings of the Board shall be taken by simple majority. In case of a tie, the Chairman shall have a casting vote.
- (iv) Any business which it may be necessary for the Board of Management to perform may be carried out by circulating appropriate resolution thereon among its members and any resolution so circulated and approved by a simple majority shall be as effective and binding as if such resolution had been passed at the meeting of the Board.
- (v) A copy of the proceedings of each meeting shall be furnished to the Chancellor of the institution deemed to be university as soon as possible after the meeting.

4.6 Termination of Membership

If a member other than the Vice-Chancellor, and those representing the teachers, accepts a full time appointment in the Institution deemed to be University or does not attend three consecutive meetings of the Board of Management, without proper leave of absence, he/she shall cease to be a member of the Board of Management.

4.7 Constitution of Standing Committee and Ad-hoc Committee by the Board of Management

4.7.1 Subject to the provision of the Rules of the Institution deemed to be University, the Board of Management may, by a resolution, constitute such Standing Committee or Ad hoc Committee or Committees for such purposes and with such powers as the Board may think fit for discharging any function of the institution deemed to be university or for inquiring into, reporting and advising upon any matter of the Institution deemed to be University.

4.7.2 The Board of Management may co-opt such persons on the Standing Committees or Ad-hoc Committees, as it may consider suitable.

4.8 Delegation of Powers of the Board of Management

The Board of Management may, by a resolution, delegate to the Vice Chancellor or any other officer of the institution deemed to be university of the Standing Committee or the Ad-hoc Committee such of its powers as it may deem fit subject to the condition that the action taken by the Vice Chancellor or the officer concerned or the Standing Committee or the Ad-hoc Committee concerned in the exercise of the powers so delegated shall be reported at the next meeting of the Board of Management.

Annexure- 2**Other Authorities of the institution deemed to be university**

The following shall be the other authorities of the institution deemed to be university:

1. Academic Council
2. Planning and Monitoring Board
3. Finance Committee
4. Board of Studies
5. Such other authorities as may be declared by the Rules to be authorities of the institution deemed to be university

1. Academic Council (AC)

1.1 The Academic Council shall be the principal academic body of the institution deemed to be university and shall, subject to the provision of the Rules, have the control over and be responsible for the maintenance of standards of teaching, research and training, approval of syllabus, co-ordination of research activities, examinations and tests within the institution deemed to be university and shall exercise such powers and perform such other duties and functions as may be prescribed or conferred upon it by the Rules of the institution.

1.2 Composition of the Academic Council

The Academic Council shall consist of the following persons, namely:

1. Vice Chancellor Chairperson
2. Pro Vice-Chancellor (if any)
3. Dean(s) of Faculties
4. Heads of the Departments
5. Ten Professors other than the Heads of the Departments (by rotation of seniority)

6. Three Associate Professors from the Departments other than the Heads of the Departments by rotation of seniority
7. Three Assistant Professors from the Departments by rotation of seniority
8. Three persons from amongst educationists of repute or persons from any other field related to the activities of the Institution deemed to be University who are not in the service of the Institution deemed to be University, nominated by the Vice-Chancellor
9. Three persons who are not members of the teaching staff, co-opted by the Academic Council for their specialized knowledge
10. The Registrar, who shall be the Secretary of the Academic Council

Note: The representation of different categories shall be only through rotation and not through election. It may also be ensured that no particular faculty dominates the membership of the Council.

1.3 Term of Membership:

The term of members other than the *ex-officio* members shall be two years.

1.4 Powers and Functions of the Academic Council:

The Academic Council shall have the following powers and duties, namely

- i. To consider matters of academic interest either on its own initiative or at the instance of the Board of Management or those proposed by the departments/ faculties and to take proper action thereon;
- ii. To exercise general supervision over the academic work of the institution deemed to be university and to give direction regarding methods of instruction, evaluation, and improvements in academic standards;

- iii. To promote research within the institution deemed to be university, acquire reports on such researches from time to time;
- iv. To prescribe courses of study leading to degrees and diplomas of the institution deemed to be university;
- v. To make arrangements for the conduct of examinations in conformity with the Bye-Laws;
- vi. To appoint examiners, moderators, tabulators and such other personnel for different examinations;
- vii. To maintain proper standards of the examinations;
- viii. To recognize diplomas and degrees of universities and other Institutions and to determine equivalence with the diplomas and degrees of the institutions deemed to be university;
- ix. To suggest measures for departmental co-ordination;
- x. To make recommendations to the Board of Management on:
 - a) measures for improvement of standards of teaching research and training;
 - b) institution of Fellowships, Travel Fellowships, Scholarships, Medals, Prizes etc.;
 - c) to recommend to the Board of Management, the establishment or abolition of departments/ centres; and
 - d) To frame rules covering the academic functioning of the institution deemed to be university, admissions, examinations, award of fellowships and studentships, free-ships, concessions, attendance, discipline, residence etc.

- xi. To appoint sub-committees to advise on such specific matters as may be referred to it by the Board of Management;
- xii. To consider the recommendations of the sub-committees and to take such action as the circumstances of each case may require;
- xiii. To take periodical review of the activities of the Departments/Centres and to take appropriate action with a view to maintaining and improving standards of instruction;
- xiv. To recommend institution of teaching posts (Professors, Associate Professors and Assistant Professors) to the Board of Management; and
- xv. To exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred or imposed upon it by the Rules.

1.5 Meeting of the Academic Council

- i. The Academic Council shall meet as often as may be necessary but not less than three times during an academic year. Not less than 15 days' notice shall be given of a meeting of the Academic Council.
- ii. One third of the total number of members of the Academic Council shall constitute the quorum for the meeting of the Academic Council.
- iii. Each member, including its Chairman, shall have one vote and decisions at the meetings of the Academic Council shall be taken by simple majority. In case of a tie, the Chairman shall have a casting vote.
- iv. Any business which it may be necessary for the Academic Council to perform, except such as may be placed before its meeting, may be carried out by circulation of the resolution among all its

members and the resolution so circulated and approved by a simple majority shall be effective and binding as if such resolution had been passed in the meeting of the Academic Council, provided that at least one half of the total number of the members of the Academic Council have recorded their views on the resolution.

2.0 Planning & Monitoring Board:

- 2.1 The Planning & Monitoring Board shall be the principal Planning Body of the institution deemed to be university and shall be responsible for the monitoring of the development programmes of the Institution deemed to be University.
- 2.2 The Vice-Chancellor shall be the Chairman of the Planning & Monitoring Board. The Registrar shall be its Secretary. It may include seven internal members and three outside eminent experts, including one nominee of the UGC.
- 2.3 The constitution, powers and functions of the Planning & Monitoring Board shall be prescribed by the Rules.
- 2.4 The Planning & Monitoring Board would have the right to advise the Board of Management and the Academic Council on any matter which it considers necessary for the fulfillment of the objectives of the institutions deemed to be university.
- 2.5 The recommendations of the Planning & Monitoring Board shall be placed before the Board of Management for consideration and approval. Proposals relating to the academic matters may be processed through the Academic Council.

3.0 Finance Committee (FC)**3.1 Composition of the Finance Committee:**

The Finance Committee shall consist of the following members

1. Vice Chancellor – Chairperson
2. Pro Vice-Chancellor
3. A person nominated by the Society or Trust
4. Two nominees of the Board of Management, one of whom shall be a member of the Board
5. A representative of the Central Government
6. A representative of the State Government, in case the institution deemed to be university is receiving grants from the State Government
7. Finance Officer- Secretary

3.2 Terms of Office of the Finance Committee:

All members of the Finance Committee other than ex-officio members shall hold office for a term of three years.

3.3 Powers and Functions of the Finance Committee:

- (i) To consider the annual accounts and financial estimates of the institution deemed to be university and submit them to the Board of the Management for approval;
- (ii) To consider and recommend the annual budget and revised estimates to the Board of Management;
- (iii) To fix limits of the total recurring expenditure and the total non-recurring expenditure of the year based on the income and resources of the institution deemed to be university.

Note: No expenditure other than that provided in the budget shall be incurred by the institution deemed to be university without the approval of the Finance Committee.

3.5 Meetings of the Finance Committee:

The Finance Committee shall meet at least twice a year to examine the accounts and to scrutinize proposals for expenditure. Five members shall constitute the quorum for the meeting.

4.0 Board of Studies:

4.1 There shall be one Board of Studies for each Department of the institution deemed to be university.

4.2 The Board of Studies of each faculty/ Department shall consist of:

1. Dean of faculty/ Head of the Department - Chairperson
2. All Professors of the faculty/ Department
3. Two Associate Professors of the faculty/ Department by rotation of seniority
4. Two Assistant Professors of the faculty/Department by rotation of seniority
5. Not more than 2 persons to be co-opted for their expert knowledge including those belonging to the profession or industry concerned

4.3 The powers and functions of the Board of Studies shall be prescribed by the Rules of the Institution deemed to be University.

5.0 Selection Committee:

5.1 There shall be a Selection Committee for making recommendations to the Board of Management for appointment to the post of Professors, Associate Professors, Assistant Professors and such other posts as may be prescribed by the Rules, in the institution deemed to be university.

5.2 Every Selection Committee shall be constituted in accordance with the Rules framed by the Board of Management.

5.3 Meetings of the Selection Committee

- (a) The meetings of the Selection Committees shall be convened by the Chairman of the Selection Committee as and when necessary.
- (b) Four members of the Selection Committee shall consisting of at least two experts shall form the quorum.
- (c) If the Board of Management is unable to accept the recommendations of the Selection Committee, it shall record its reasons thereof and require an appropriate review by a high power committee.

6.0 Officers of the institution deemed to be university

The following shall be the officers of the institution deemed to be university:

- a) Chancellor
- b) Vice-Chancellor
- c) Pro Vice-Chancellor
- d) Registrar
- e) Finance Officer
- f) Controller of Examinations
- g) Dean of Faculties
- h) Head of Department
- i) Such other officers as may be prescribed in the Rules of the institution deemed to be university

6.1 Chancellor

The institution deemed to be university shall have a Chancellor who shall, when present, preside over the convocations of the institution deemed to be university but shall not be the Chief Executive Officer. The Chancellor shall be appointed by the sponsoring Society or Trust, shall hold office for a period of 5

years and shall be eligible for one more term. The Chancellor shall neither be a member of the Society or the Trust nor a close relative of the President of the Society or the Trust.

Where power is conferred upon the Chancellor to nominate persons to authorities, he/she shall, to the extent necessary, nominate persons to represent the various interests for the furtherance of the objectives of the institutions deemed to be university.

6.2 Vice-Chancellor

- (i) The Vice-Chancellor shall be a whole time salaried officer of the institution deemed to be university and shall be appointed by the Chancellor from a panel of three names suggested by a Search-cum-Selection Committee. The composition of the Search-cum-Selection Committee shall be:-

1. A nominee of the Chancellor
2. A nominee of Central Government; who shall be an eminent academic nominated by the Government in consultation with the UGC
3. A nominee of the Board of Management

- (ii) The Vice-Chancellor shall hold office for a term of 5 years. He shall be eligible for a second term, provided that in no case shall he hold office beyond the age of 70 years.

Provided that notwithstanding the expiry of the period of 5 years, he/she may continue in office for not more than six months or till his/her successor is appointed and the latter assumes office, whichever, is earlier.

- (iii) In case of the office of the Vice-Chancellor becoming vacant due to death, resignation or otherwise and in case of his/her absence due to illness or any other cause, the Pro Vice-Chancellor, and in his/her absence, the Senior most Dean or, if there is no Dean, the senior most Professor shall perform the duties of the Vice-Chancellor until a new Vice-Chancellor is

appointed, or the existing Vice-Chancellor resumes duties, as the case may be.

6.3 Powers of the Vice-Chancellor

- i) The Vice-Chancellor shall be the Principal Executive Officer of the institution deemed to be university and shall exercise general supervision and control over the affairs of the institution deemed to be university and shall be mainly responsible for implementation of the decisions of all the authorities of the Institution deemed to be University.
- ii) The Vice-Chancellor shall be the Ex-officio Chairman of the Board of Management, the Academic Council, the Finance Committee, the Planning & Monitoring Board and Selection Committees.
- iii) The Vice-Chancellor shall have the power to convene or cause to be convened meeting of the various authorities of the institution deemed to be university.
- iv) The Vice-Chancellor may, if he/ she is of the opinion that immediate action is called for on any matter, he / she shall exercise any power conferred upon any authority of the institution deemed to be university under its Regulations and Rules, and take such action or proceed to take such action and shall report to the authority concerned on the action taken by him/her on such matters.

Provided that if the authority concerned as mentioned in clause (ii) above is of the opinion that such action ought not to have been taken, it may refer the matter to the Chancellor whose decision thereon shall be final.

Provided further that if any person in the service of the institution deemed to be university is aggrieved by the action taken by the Vice-Chancellor under the said clause, he/she shall have the right to appeal

against such decision to the Board of Management within 30 days from the date on which such action is communicated to him/her and thereupon the Board of Management shall call the meeting in a subsequent meeting and may confirm, modify or reverse the action taken by the Vice-Chancellor.

- v) It shall be the duty of the Vice-Chancellor to ensure that Regulations and Rules of the institution deemed to be university are duly observed and implemented; and, he/she shall have all the necessary powers in this regard.
- vi) All powers relating to the proper maintenance and discipline of the institution deemed to be university shall be vested in the Vice-Chancellor.
- vii) The Vice-Chancellor shall have the power to re-delegate some of his powers to any of his/her subordinate officers with the concurrence and approval of the Board of Management.
- viii) The Vice-Chancellor shall exercise all other powers as may be delegated to him/her by the Board of Management.
- ix) The Vice-Chancellor shall exercise such other powers and perform such other functions as may be prescribed by the Regulations, Rules and Bye-Laws.

6.4 Pro Vice-Chancellor

- (i) The post of the Pro Vice-Chancellor may be created with the approval of the Board of management and the Central Government.
- (ii) The Pro Vice-Chancellor shall be appointed by the Board of Management on the recommendation of the Vice-Chancellor.

- (iii) The Pro Vice-Chancellor shall hold office co-terminus with the office of the Vice-Chancellor and at the pleasure of Vice-Chancellor.
- (iv) The Pro Vice-Chancellor shall have the powers and duties as prescribed by Rules of the institution deemed to be university.

6.5 Registrar

- (i) The Registrar shall be a whole time salaried officer of the institution deemed to be university and shall be appointed by the Board of Management on the recommendations of the Selection Committee consisting of the following:-
 - 1. Vice Chancellor - Chairperson
 - 2. One nominee of the Chancellor
 - 3. One nominee of the Board of Management.
 - 4. One expert appointed by the Board of Management who is not an employee of the institution deemed to be university.
- (ii) The emoluments and other terms and conditions of service of the Registrar shall be as prescribed by Rules of the institution deemed to be university.
- (iii) When the office of the Registrar is vacant or when the Registrar is absent by reason of illness or any other reason, the duties and functions of the Registrar shall be performed by such other person as the Vice Chancellor may appoint for the purpose.
- (iv) The Registrar shall be ex-officio Secretary of the Board of Management, the Academic Council and the Planning and Monitoring Board, but shall not be deemed to be a member of any of these authorities.
- (v) The Registrar shall be directly responsible to the Vice-Chancellor and shall work under his direction.

2013 G1/10-15

(vi) The following shall be the duties of the Registrar: -

1. To be the custodian of the records and the funds and such other property of the institution deemed to be university as the Board of Management may commit to his/her charge;
2. To conduct the official correspondence on behalf of the authorities of the institution deemed to be university;
3. To issue notices convening meetings of the authorities of the institution deemed to be university and all Committees and sub-Committees appointed by any of these authorities;
4. To maintain the minutes of the meetings of all the authorities of the institution deemed to be university and of all the Committees and sub-Committees appointed by any of these authorities;
5. To make arrangements for and supervise the examinations conducted by the institution deemed to be university;
6. To represent the institution deemed to be university in suits or proceedings by or against the institution deemed to be university, sign powers of attorney and perform pleadings or depute his/her representatives for this purpose;
7. To enter into agreement, sign documents and authenticate records on behalf of the institution deemed to be university;
8. To make arrangements to safeguard and maintain the buildings, gardens, office, canteen, cars and other vehicles, laboratories, libraries, reading rooms, equipment and other properties of the institution deemed to be university;

9. To perform such other duties as may be specified in the Rules or as may be assigned by the Board of management or the Vice-Chancellor from time to time.

6.6 Finance Officer

- (i) The Finance Officer shall be a whole time salaried officer of the institution deemed to be university and shall be appointed by the Board of Management.
- (ii) The emoluments and other terms and conditions of service of the Finance Officer shall be as may be prescribed by Rules of the institution deemed to be university.
- (iii) The Finance Officer shall work under the direction of the Vice-Chancellor and shall be responsible to the Board of Management through the Vice-Chancellor.
- (iv) He/she shall be responsible for the preparation of annual budget, estimates and statements of account for submission to the Finance Committee and the Board of Management.
- (v) He/she shall be responsible for the management of funds and investments of institution deemed to be university, subject to the control of Board of Management.

6.7 Controller of Examinations

- (i) The Controller of Examinations shall be appointed by the Board of Management
- (ii) The emoluments and other terms and conditions of service of the Controller of Examination shall be as may be prescribed by Rules of the institution deemed to be university.

- (iii) The Controller of Examinations shall ensure that all the specific directions of the Board of Management, Academic Council and Vice-Chancellor in respect of examination and evaluation are complied with.
- (iv) The Controller of Examinations shall be a permanent invitee to the Board of Management.

6.8 Dean

The Departments dealing with allied subjects could be grouped into faculties: Each faculty may be headed by a Dean.

6.9 Head of the Department

- (i) There shall be a Head of the Department for each of the Departments in the institution deemed to be university who shall be appointed by the Vice-Chancellor from amongst the Professors of the Department.

Provided that if there is no Professor in the Department or there is only one Professor in the Department whose term as Head of the Department is ending, the Vice-Chancellor may appoint an Associate Professor as Head of the Department.

- (ii) The term of the Head of the Department shall normally be 3 years and he/she shall be eligible for reappointment for one more term, but not for two consecutive terms.
- (iii) The powers and functions of the Head of the Department shall be prescribed by Rules of the institution deemed to be university.

7.0 Delegation of Powers

Subject to the provisions of these Regulations and Rules, any authority or officer of the institution deemed to be university, with the approval of Board of Management, may delegate its power to any other authority or officer or

person under their respective control and subject to the conditions that the overall responsibility for exercising the powers so delegated shall continue to rest in the authority or officer delegating such powers.

8.0 Seniority List

- (a) Whenever in accordance with these Rules any person is to hold an office or to be a member of an authority of the Institution deemed to be University by rotation of seniority, such seniority shall be determined according to the length of the continuous service of such person in the grade in the institution deemed to be university in accordance with such other principles as the Board of Management may from time to time prescribe.
- (b) It shall be the duty of the Registrar to prepare and maintain in respect of each class/cadre of persons to whom the provisions of these Rules apply a complete and up-to-date seniority list in accordance with the provisions of the foregoing clause.
- (c) If two or more persons have equal length of continuous service in a particular grade/cadre or the relative seniority of any person or persons is in doubt, the Registrar may on his/her own notion and shall at the request of any such person, submit the matter to the Board whose decision shall be final and binding.

9.0 Dispute as to Membership

If any question arises, whether any person has been duly nominated or appointed, as or is entitled to be a member of any authority or any committee of the institution deemed to be university, the matter shall be referred to the Chancellor, whose decision thereon shall be final and binding.

10.0 Grievance Redress Mechanism

For individual grievances and complaint(s), every institution deemed to be university shall have a Grievance Redress Mechanism as may be prescribed by the Rules.

11.0 Resignation

Any member other than an ex-officio member of any authority may resign by a letter addressed to the Registrar and the resignation shall take effect as soon as it is accepted by the Chancellor or the Chairman of the Board of Management, as the case may be.

12.0 Acting Chairman of the Meetings

Where no provision is made for a Chairman to preside over a meeting of an authority of the institution deemed to be university or any committee of such authority, or if the Chairman so provided is absent, the members present may select one from amongst themselves to preside at such meeting.

13.0 Validation of certain actions, decisions

No action or proceedings of any authority or anybody or any committee of the institution deemed to be university shall be invalid merely by reason of any vacancy therein.

14.0 Disqualification

(a) A person shall be disqualified for being chosen as and for being a member of any of the authorities of the institution deemed to be university:

- i) if he/she is of unsound mind
- ii) if he/she is an un-discharged insolvent
- iii) if he/she has been convicted by a court of law of an offence involving moral turpitude.

- (b) If any question arises as to whether a person is or has been subjected to any disqualifications mentioned above, the question shall be referred for decision to the Chancellor and his decision shall be final.

15.0 Filling of Casual Vacancies

Casual vacancies among the members (other than ex-officio members) of any authority or any Committee of the institution deemed to be university shall be filled as soon as it may be convenient by the such authority or the person who appointed or co-opted the member whose place has become vacant and the person appointed or co-opted to a casual vacancy shall be member of such authority or committee for the residual term for which the person whose place he/she fills would have been a member.

16.0 Review of the Academic Activities of the institution deemed to be university

The functioning of the institution deemed to be university may be reviewed after a period of every 5 year or earlier, if necessary, by a Committee appointed by the Commission.

17.0 Inspection of the institution deemed to be university by the Commission

- i) The Commission may cause an inspection, to be made by such person or persons as it may direct, of the institution deemed to be university, its buildings, fixtures and fittings, laboratories and equipment as also examinations, teaching and other work carried on or done and, if necessary, to cause an inquiry to be made in respect of any matter connected with the administration or finances of the institution deemed to be university.
- ii) The Commission shall, in every case, give notice to the institution deemed to be university of its intension to cause an inspection or inquiry to be made and on receipt of such a notice, the institution deemed to be university shall have the right to make such representations to the Commission as it may consider necessary.

- iii) Where an inspection or inquiry has been caused to be made by the Commission, the institution deemed to be university shall be entitled to appoint a representative who shall have the right to be present and to be heard at such inspection or inquiry.
- iv) The Commission may communicate the result of such inspection or inquiry together with such advice as it may be pleased to offer as to the action to be taken by the institution deemed to be university to the Vice-Chancellor who shall communicate the same to the Board of Management.
- v) The Board of Management shall give proper consideration to the said communication regarding the result of inspection or inquiry and the proposals for action by the institution deemed to be university and communicate to the Commission the action, if any, which it proposes to take or has taken upon the result of such inspection or inquiry.
- vi) Where the Board of Management does not, within a reasonable time, take any action to the satisfaction of the Commission, the Commission may, after giving due consideration to the explanation furnished or representation made by the Board of Management to it, issue such directions as it may think fit and the Board of Management shall comply with such directions.

18.0 Income and Property of the institution deemed to be university to be utilized for its objectives only

The income and property of the institution deemed to be university shall be utilized solely for promoting the objectives of that institution deemed to be university.

19.0 Ban on payment or transferring of Income and Property of the institution deemed to be university by way of Profit

No portion of the income and property of the institution deemed to be university shall be paid or transferred directly or indirectly, by way of dividend, bonus or otherwise howsoever by way of profit to the persons who were at any time or are members of the institution deemed to be university or to any of them or any persons claiming through them, provided that nothing herein contained shall prevent the payment in good faith of remuneration to any member thereof or other person as consideration for any service rendered to the institution deemed to be university or for traveling or other allowances and such other charges.

20.0 Funds, Accounts, Audits and Annual Report

- i) The accounts of the institution deemed to be university shall be maintained in the name of the institution deemed to be university and not in the name of the sponsoring Society or Trust. The accounts of the institution deemed to be university shall be kept in such forms as may be laid down by the Board of Management and shall conform to the rules, if any, prescribed by the Commission. The accounts of the institution deemed to be university shall be open for examination by the Controller and Auditor General of India. The accounts shall also be open for inspection by the Commission.
- (ii) The annual financial statements and accounts shall be audited by the Chartered Accountant of the institution deemed to be university.
- iii) Annual Reports and the Audit Reports shall be submitted by the institution deemed to be university to the Commission within nine months of the closure of the accounting year.

21.0 Rules of the institution deemed to be university

Subject to the provisions of the Regulations and the Rules of the Commission, the Board of Management shall, in addition to all other powers vested in it, have the power to frame the Rules of the institution deemed to be university that may provide for all or any of the following matters: -

- (i) establishment of Departments of teaching ;
- (ii) courses of study to be laid down for all degrees, diplomas and certificates of the Institution deemed to be University;
- (iii) grant of academic awards (such as degrees and diplomas) and distinctions;
- (iv) admission of students to the Institution deemed to be University and their enrolment as such;
- (v) the fees to be charged for courses of study and for admission to the examinations, degrees, diplomas and certificates of the Institution deemed to be University.
- (vi) conduct of examinations, appointment of examiners and approval and publication of results thereof;
- (vii) institution of award of fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes and prescription of the conditions thereof;
- (viii) maintenance of discipline among the students;
- (ix) maintenance of discipline among the employees;
- (x) establishment of halls of residence and conditions of residence and health of the students;

- (xi) classification, emoluments, method of appointment and determination of the terms and conditions of service of the staff;
- (xii) such other powers, functions and duties of the Academic Council as are not mentioned elsewhere;
- (xiii) constitution, powers and functions of the Planning & Monitoring Board
- (xiv) Powers and functions of the Board of Studies;
- (xv) composition, powers and functions of the Grievance Redress Mechanism;
- (xvi) prescribing persons as such other officers of the institution deemed to be university;
- (xvii) such other powers and functions of the Vice-Chancellor as are not specified elsewhere;
- (xviii) emoluments, terms and conditions of service of the Register;
- (xix) emoluments, terms and conditions of service of the Finance Officer;
- (xx) constitution of pension, provident fund, insurance etc for the benefit of the officers, teachers, and the other staff;
- (xxi) establishment of special centers;
- (xxii) creation, composition and functions of any committees or body, which is considered necessary for the work of the institution deemed to be university;
- (xxiii) procedure for preparation and submission of budget estimates;
- (xxiv) procedure for convening of meeting of any authority or committee;

- (xxv) laying down of procedures to be observed at any meeting of any authority or any committee;
- (xxvi) constitution of any other body as an authority of the institution deemed to be university;
- (xxvii) delegation of powers to any authority or officer;
- (xxviii) all other matters by this Regulation or the Rules may be provided but no rule shall be made affecting the condition of residence, health, discipline, admission, enrolment of students, conditions, mode of appointments, duties of examiners, conduct of and standard of examinations or any course of study without consulting the Academic Council.

22.0 Interpretation Clause

In the event of conflict of opinion with regard to interpretation of Regulations or the Rules of the Commission, the opinion of the Commission shall be final.

23.0 Adjustment of Income and Property on Dissolution of the institution deemed to be university

If on the winding up or dissolution of the institution deemed to be university there remains, after the satisfaction of all its debts and liabilities, any property whatsoever, the same shall not be paid or distributed among the members of the institution deemed to be university or any of them, but shall be transferred to the Commission, or other bodies in consultation with the agencies concerned who have helped in creation of those assets.

24.0 Legal Proceedings

- i) For the purpose of Section 6 of the Societies Registration Act, 1860, the person in whose name the institution deemed to be university may sue or be sued shall be the Registrar.

- ii) No suit or legal proceedings shall lie against the Central Government or the Commission or the institution deemed to be university or an Officer of the institution deemed to be university or a member of the authority of the institution deemed to be university in respect of anything done or purported or intended to be done in pursuance of any of these Regulations.

25.0 Alteration, Amendments and Additions to the Rules governing the functioning of the institution deemed to be university

No Rule and Bye law governing the functioning of the institution deemed to be university may be altered, amended and added to by the Board of Management or such other competent body to the effect that it is in conflict with or to the detriment of the provisions of these Regulations; and, no alteration, amendment or addition to the Rules and bye laws shall be given effect to without the prior approval of the Commission in accordance with the provision of the Societies Registration Act, 1860 or the relevant Public Trust Act as in force for the time being.